*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 की पहली छमाही में लचीली बनी रही और मुद्रास्फीति में कमी आयी जिससे परिवार खर्च का बोझ कम हुआ। मौद्रिक नीति में ढील के बीच स्थिर संवृद्धि गति अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख विषय बनती जा रही है। भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत के विकास दृष्टिकोण को मजबूत घरेलू प्रयासों का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में गति में कमी दिखाई है जो आंशिक रूप से अगस्त और सितंबर में असामान्य रूप से हुई भारी बारिश जैसे विशिष्ट कारकों के कारण है। इसके अलावा निजी निवेश प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में कुछ उत्साहजनक संकेत दिखा रहा है, और त्योहारी मौसम में खपत व्यय में सुधार हो रहा है। मुद्रास्फीति के लगातार दो महीनों तक लक्ष्य से नीचे रहने के बाद सितंबर में उसमें उछाल आया क्योंकि खाद्य मूल्य पुन: बढ़ने से प्रतिकूल सांख्यिकीय आधार प्रभाव और बढ़ गया।

परिचय

जैसे-जैसे वे अक्टूबर – स्थायित्व और परिवर्तन के मेलजोल के महीना[1] - के करीब पहुँचे, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देते हुए कमान संभाली। उनकी विशिष्ट गतिविधियों का उल्लेख खंड II में किया गया है। यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएफसी) द्वारा अत्यधिक दर-कटौती चक्र की असामान्य रूप से शुरुआत करने के उसके उद्देश्य पर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था "अच्छी स्थिति में है" और " यह विश्वास बढ़ा है कि श्रम बाजार में मजबूती को बनाए रखा जा सकता है"[2]; मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मिशन पूरा हुआ; यूरोप और चीन से प्रतिकूल स्पिलओवर से बचाव; शुरुआती बिंदु पर असाधारण रूप से उच्च वास्तविक ब्याज दरें; और अत्यधिक अनिश्चित परिदृश्य की वास्तविकता का सामना करने के लिए बीमा[3]। यह अटकलें इसलिए हैं क्योंकि मौद्रिक नीति लंबे और परिवर्तनशील अंतराल के साथ प्रसारित हुई है। यह अनुमान स्वाभाविक भी है। शुरुआती दर में बड़ी कटौती बाजारों के लिए संकट का संकेत है और चेतावनी है कि अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में है। हालाँकि एफओएफसी की कार्रवाई 2024 की दूसरी तिमाही और पिछली तिमाही के लिए जीडीपी के अनुमानों में संशोधनों से दिखाई देने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में हुई है। कई लोगों का मानना है कि एफओएफसी दीर्घकाल रही दर वृद्धि के बारे में अपनी आलोचना से आहत है और इसलिए दर कार्रवाई के इस चरण में आगे रहना चाहता है। यूएस की ब्याज दरों में यह बदलाव उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के अन्य केंद्रीय बैंकों के लिए एक संकेत है, जिसमें होल्डआउट भी शामिल हैं, और विशेष रूप से वे जो मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने में सफल रहे हैं और इसलिए उनके पास अपनी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए वजह है। हालांकि मौद्रिक नरमी बरते जाने का वातावरण बन रहा है फिर भी कुछ देशों में, जैसे कि जापान; ब्राजील; और रूस में इसके विरुद्ध अर्थात सख्ती लाने की घटना हो सकती है।

दूसरी ओर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दिए जाने वाले अपने सुगम समर्थन को समाप्त कर दिया है और अपनी बीमार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए संपत्ति और शेयर बाजारों सहित प्रोत्साहन उपायों की बौछार की है। इस कदम के बाद चेतावनी के संकेत मिले, जैसे कि कर राजस्व में कमी; घरों और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट; खुदरा बिक्री में कमी; उपभोक्ता विश्वास में कमी; और कमजोर औद्योगिक उत्पादन और निवेश। इन उपायों ने वित्तीय बाजारों को सक्रिय किया है। शंघाई और हांगकांग के शेयर बाजारों में चार साल में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज किए जाने के कारण दुनिया भर में इक्विटी की कीमतों में गिरावट आई। एशिया भर में मुद्राओं में गिरावट आई और युआन में तेजी आई क्योंकि पूंजी प्रवाह घूम कर फिर चीन की ओर बढ़ा। यह देखना अभी बाकी है कि चीनी प्राधिकारी लंबे समय से चले आ

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, अर्पिता अग्रवाल, रजनी दहिया, गरिमा वाही, यामिनी झांब, हरेंद्र बेहेरा, के. एम. नीलिमा, वृंदा गुप्ता, साक्षी चौहान, मधुरेश कुमार, आयुषी खंडेलवाल, देबप्रिया साहा, रागिनी, सुगंधि डी., प्रतिभा केडिया, आयन पॉल, अगमानी साहा, आयुषी अग्रवाल, दिलप्रीत शर्मा, खुशी सिन्हा, अवनीश कुमार, निखिल प्रकाश कोसे, सुप्रियो मंडल, युवराज कश्यप, साक्षी अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव, और श्रीमती रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] बोनारो डब्ल्यू. ओवरस्ट्रीट, अमेरिकी लेखक, कवि, मनोवैज्ञानिक और वाशिंगटन पोस्ट में स्तंभकार।

[2] "इकोनॉमिक आउटलुक", अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के चेअर जेरोम पॉवेल द्वारा भाषण, 30 सितंबर 2024।

[3] मोहम्मद ईएल-एरियन, दी फेड टेक्स आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ओन रेट्स, फाइनेंशियल टाइम्स, 1 अक्टूबर 2024।

रहे स्थावर संपदा संकट, वृद्ध और सिकुड़ते कार्यबल, औद्योगिक अतिक्षमता, व्यापार तनाव और गंभीर रूप से तनावग्रस्त स्थानीय सरकारी वित्त को हल करने के लिए कितना आगे बढ़ेंगे।

अपने नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने मूल्यांकन किया कि 2024 की पहली छमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली बनी रहेगी जिसमें घटती मुद्रास्फीति परिवार खर्च के बोझ को कम करेगी। उच्च आवृत्ति संकेतक अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास गति का संकेत देते हैं। कारोबार संबंधी सर्वेक्षण विनिर्माण की तुलना में सेवाओं में अधिक गतिविधि होने का संकेत देते हैं। सर्वेक्षण यह भी संकेत देते हैं कि यूरोप के साथ-साथ कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हो रहा है। वैश्विक व्यापार में अच्छा सुधार हो रहा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं, दोनों में व्यापार की मात्रा बढ़ रही है। वैश्विक कंटेनर शिपिंग ने ज्यादातर लाल सागर और पनामा नहर मार्गों में स्थित व्यवधानों के अनुकूल खुद को ढाल लिया है, लेकिन यात्रा का समय लंबा हो गया है और प्रमुख एशियाई बंदरगाहों में भीड़ बढ़ गई है। शिपिंग लागत में एक साल पहले की तुलना में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे अंततः मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ प्रतिबंधात्मक स्तरों से बाहर निकल रही हैं। वित्तीय बाज़ार नीतिगत दरों में कटौती की अपनी अपेक्षाओं में केंद्रीय बैंकों से आगे चल रहे हैं। दीर्घकालिक बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट आई है, जबकि कारपोरेट बॉण्ड निर्गमों में तेज़ी आई है और इक्विटी बाज़ारों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में शत्रुता के युद्ध में परिवर्तित होने और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ने बाज़ार सहभागियों को विवश कर रखा है। वैश्विक उत्पादन वृद्धि के संबंध में दृष्टिकोण को थोड़ा उन्नत किया गया है (विवरण खंड II में दिया गया है)। ओईसीडी द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक प्रदर्शन के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच लगातार असंतोष के बारे में है जो इस तथ्य से जुड़ा है कि खाद्य कीमतें अपने पूर्व-महामारी स्तर से काफ़ी ऊपर बनी हुई हैं: "सुपर मार्केट में जाने वाले लोगों के लिए मज़दूरी की तुलना में खाद्य कीमतें अभी भी अधिक हैं"।[4] निकट अवधि के प्रमुख जोखिमों में वैश्विक और व्यापार तनावों का बने रहना; श्रम बाज़ार के दबाव के कम होने से संवृद्धि में मंदी की संभावना; और अवस्फीति के बने रहने पर वित्तीय बाज़ारों में संभावित व्यवधान शामिल हैं। कुल मिलाकर ओईसीडी का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अपना स्वरूप बदल रही है।

[4] अल्वारो परेरा, चीफ इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल में 25 सितंबर 2024 का उल्लेख।

अमेरिका में ब्याज दरों में बड़ी कटौती से कर्ज में डूबे ईएमई पर दबाव कम होने और स्थानीय मुद्रा बॉण्डों की मांग में तेजी आने की संभावना है। उनके कई केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी ब्याज दरों में कमी की आशंका के चलते अपनी नीतिगत दरों में कमी की है या आगे के लिए नरम रुख अपनाने का संकेत दिया है। ईएमई फिक्स्ड इन्कम एसेट्स को मिलने वाला प्रत्याशित समर्थन उनमें से 'लेट कटर' के पक्ष में प्रतीत होता है। एफओएफसी के फैसले के बाद ईएमई इक्विटी में आम तौर पर तेजी आई है, हालांकि हाल ही में चीन के प्रति झुकाव और ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष के बढ़ने से इसमें बाधा आई है। इसके अलावा दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए यह अत्यंत खराब दशक रहा है[5] जिसमें अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, और साथ ही संक्रामक रोगों से लड़ने में प्रगति भी धीमी हुई है।

इन सबके बीच भू-राजनीतिक तनावों और तेजी से बढ़ते बाजार की भावना के कारण सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर को पार कर गई हैं। दूसरी ओर पश्चिम एशियाई शत्रुता के हाल ही में भड़कने के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में एक स्थिरता है जो एक अजीब स्थिति है। यह मांग और आपूर्ति के बीच अधिक अनुकूल संतुलन को दर्शाता है। प्रतिबंधों ने वैश्विक आपूर्ति पर कोई दबाव नहीं डाला है। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और गुयाना जैसे गैर-ओपेक देशों से उत्पादन में वृद्धि हुई है। ओपेक *प्लस* की स्थिति विखंडित है, जिसमें उत्पादन में कटौती से राजस्व लाभ के बिना बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम है। मांग के आकलन में भी भिन्नता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) को जबकि उम्मीद है कि 2024 में प्रतिदिन अतिरिक्त 9,00,000 बैरल तेल की आवश्यकता होगी, वहीं ओपेक कहीं अधिक आशावादी है और उसे उम्मीद है कि अतिरिक्त 2 मिलियन बैरल की आवश्यकता होगी।

[5] द इकोनॉमिस्ट, एंड ऑफ द रोड, 21 सितंबर 2024।

बहुपक्षीय संस्थाओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि निरंतर सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के कारण भारत की मध्यम अवधि की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की संभावनाओं में सुधार से, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में, संवृद्धि और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।[6]

हाल के भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारत के विकास दृष्टिकोण को मजबूत घरेलू चालकों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में गति में कमी दिखाई है, जो आंशिक रूप से अगस्त और सितंबर में असामान्य रूप से भारी बारिश और *पितृ पक्ष*[7] जैसे अजीबोगरीब कारकों के कारण है जिससे माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह; ऑटोमोबाइल बिक्री; बैंक ऋण वृद्धि; माल निर्यात; और विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) प्रभावित हुए हैं। गति में कमी खंड III में दिए गए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के हमारे नाउकास्ट में भी दिखाई देती है।

इसी के समानांतर, अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक हैं जो स्थिर वृद्धि दर्शाते हैं। त्यौहारी सीज़न में उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है, खासकर छोटे शहरों और निचले स्तर के शहरों में। उच्च कीमतों के कारण उत्साह में कुछ कमी आने के बावजूद कई खरीदार डिस्काउंट से आकर्षित हो रहे हैं। सर्वेक्षण के सहभागी व्यय में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जिसमें नई अलमारी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर की सजावट और आभूषणों की खरीद मुख्य कारण हैं। पैकेट-बंद फूड कंपनियां शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में मांग में वृद्धि की उम्मीद में त्यौहारी सीज़न के लिए आपूर्ति श्रृंखला और पेशकश बढ़ा रही हैं। खुदरा मीडिया पर अनोखे ऑन-प्लेटफ़ॉर्म नवाचार उनके ब्रांडों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हालाँकि शुरुआती ई-कॉमर्स बिक्री निराशाजनक रही है, खुदरा विक्रेताओं को उम्मीद है कि सीज़न के अंत में इसमें तेज़ी आएगी। पिछले साल के दशहरा-दिवाली के मुकाबले उपभोक्ता व्यय लगभग 25 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है।[8] इसमें ऑफ़लाइन खुदरा के आगे रहने और उसके बाद ऑनलाइन माध्यम का क्रम रहने की उम्मीद है। क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉम) प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शॉपर्स के व्यवहार में तेजी से बदलाव ला रहे हैं, जिसमें किराने की जरूरतों और खाने के लिए तैयार भोजन (रेडी-टू-ईट मील) के लिए फास्ट डिलीवरी विकल्पों पर निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है।[9] क्यू-कॉम भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदल रहा है: अलमारी में हाथ डालने के बजाय, वे ऐप स्वाइप करते हैं; वे स्टोर की तुलना में सामने के दरवाजे पर जाना पसंद करते हैं। बड़े पैमाने पर खरीदारी में नरमी बनी हुई है, जबकि बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मजबूती आई है। वित्त कंपनियों ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक रूप से नकदी का प्रचलन है, ऋण-संचालित खपत में वृद्धि देखी जा रही है, विशेष रूप से दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट फोन के लिए। क्यू-कॉम खरीदार तेजी से समझदार, कीमत के प्रति सचेत और चैनल निरपेक्ष (चैनल एग्नोस्टिक) बन रहे हैं। शीर्ष निजी बैंकों में भर्ती की होड़ चल रही है, जो खपत के लिए सकारात्मक है।[10] त्योहारी दौर के लिए मौसमी कर्मियों की भर्ती में भी उछाल की उम्मीद है।[11]

निजी निवेश में नरमी के बावजूद कुछ प्रमुख संकेतक उत्साहजनक स्थिति दर्शा रहे हैं। 2024-25 की पहली तिमाही के कॉरपोरेट नतीजों में गैर-सरकारी गैर-वित्त कंपनियों द्वारा जोड़े गए वास्तविक सकल मूल्य में कमी देखी गई है।[12] संयंत्रों और मशीनरी में वास्तविक निवेश कम रहा, तथा निवल अचल संपत्तियों में कमी आई है। जाहिर है, सरकारी पूंजीगत व्यय के प्रभाव में क्राउडिंग इन प्रभाव कम हुआ है। बिक्री वृद्धि में कमी को देखते हुए कंपनियां कच्चे माल और जनशक्ति दोनों पर खर्च को बचाकर लाभ को बचाते हुए बड़े पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में देरी करते हुए दिखाई

6 एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक - सितंबर 2024।

7 पितृ पक्ष हिंदू कैलेंडर में 16-चंद्र दिन की अवधि है जब हिंदू अपने पूर्वजों (पितरों) को श्रद्धांजलि देते हैं, विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से।

8 डेलॉइट; रेड सियर; कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 30 सितंबर, 2024।

9 नीलसनआईक्यू, 24 सितंबर 2024।

10 द इकोनॉमिक टाइम्स, "एट टॉप प्राइवेट बैंक्स, पोस्ट-कोविड बूम फ्यूल्स हायरिंग स्प्री", 21 सितंबर 2024।

11 फाइनेंशियल एक्सप्रेस, " ओवर मिलियन गिग वर्कर्स सेट टू बी हायर्ड धिस फेस्टिवल सीजन ", 25 सितंबर 2024।

12 यदि नाममात्र जीवीए डब्ल्यूपीआई विनिर्माण के साथ डिफ्लेट है, तो 24-25 की पहली तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की वास्तविक जीवीए वृद्धि ने पिछली तिमाही से वृद्धि दर्ज की।

देते हैं। एक दृष्टिकोण यह बन रहा है कि निजी निवेश का समय अब आ गया है और देरी करने से प्रतिस्पर्धात्मकता के खत्म होने का जोखिम है। निजी क्षेत्र के लिए पूंजी लगाने और विकास में निवेश करने, क्षमता निर्माण करने, रोजगार सृजित करने और दक्षता में सुधार करने के लिए वातावरण तैयार है। कारपोरेट इंडिया को चाहिए कि वे अपने मुनाफे का उत्पादन मूल्य श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए पुन: निवेश करें ताकि भारतीय उपभोक्ता की भिन्न-भिन्न बढ़ती जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव उत्पादों और सेवाओं का डिजाइन बना कर उन्हें तैयार किया जा सके और बेचा जा सके। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार योग्य विनिर्माण कार्यबल में भी निवेश करना चाहिए।

हाल के प्रमुख संकेतकों को देखें तो अमेरिका और यूरोप में मांग की प्रत्याशित वापसी के मद्देनज़र तकनीकी क्षेत्र के आय कोटि उन्न्यन (अर्निंग अपग्रेड) में वृद्धि हो रही है जो इस क्षेत्र में निवेश के नए दौर का संकेत है। इसके अलावा, ग्रीनफील्ड होटल निवेश महामारी से पहले के स्तर पर लौट आया है। चुनावी दौर की मंदी के बाद परियोजना घोषणाओं में तेज़ी आई है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र आगे है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र शीर्ष परियोजना घोषणाओं में शामिल है। दूसरी तिमाही में नई परियोजनाओं में संकुचन का सिलसिला समाप्त होता दिखाई दे रहा है। परियोजनाओं का सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन उनका पूरा होना एक चुनौती है।

वित्तीय बाजारों की बात करें तो, जिनकी चर्चा खंड IV में अधिक विस्तार से की गई है, इक्विटी का दृष्टिकोण सकारात्मक है, जिसमें मध्यम अवधि के लिए अधिकांश समय के लिए प्रगति बरकरार दिखाई देती है।[13] अस्थिरता आम तौर पर कम रही है जो विस्तारित मूल्यांकन के बावजूद कम बाजार जोखिम का संकेत देती है। अक्टूबर में अब तक चीन के प्रभाव को छोड़कर, जून से सितंबर 2024 तक इक्विटी और कर्ज (डेट) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में उछाल आया है, जो भारत की विकास यात्रा, तेजी से बढ़ते आईपीओ बाजार और वैश्विक सूचकांकों में भारत के बढ़ते प्रभाव जैसे आकर्षक कारकों से आकर्षित हुआ है। वास्तव में भारत ने अब तक 2024 के दौरान वैश्विक आईपीओ बाजार का नेतृत्व किया है, जिसमें छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) और प्रमुख खंडों, दोनों ने उछाल में योगदान दिया है। इस दिवाली पर मेगा आईपीओ[14] के प्रवेश के लिए मंच तैयार है।

हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड से लेन-देन की मात्रा में कमी आयी है क्योंकि ऋणदाता अरक्षित ऋणों में पाए जा रहे जोखिमों के मद्देनजर सावधानी अपना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में शुरुआती तनाव उधारकर्ताओं की मांग के बजाय ऋण वितरित करने वाले ऋणदाताओं के अभियान से प्रेरित है।[15] स्व-नियामक संगठन - माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) – आस्ति गुणवत्ता की चुनौतियों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों की ओर इशारा करता है, जैसे उधारकर्ता के ऋण चुकौती दायित्वों को परिवार की आय के 50 प्रतिशत पर सीमित करना, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं की संख्या सीमित करना और कुल ऋणग्रस्तता को सीमित करना।[16] क्रेडिट ब्यूरो के आंकड़े संकेत देते हैं कि खुदरा ऋण की वृद्धि धीमी हो गई है क्योंकि ऋणदाताओं ने वैयक्तिक ऋण की आपूर्ति को सख्त कर दिया है।[17] बैंकिंग क्षेत्र में, ऋण वृद्धि में कुछ धीमी गति के बावजूद जमा दरों के ऊंचे रहने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान में थोक जमा दरें चरम पर हैं। बैंक भी अभिनव जमा योजनाएं शुरू कर रहे हैं। बैंकों ने धन जुटाने के लिए जमा प्रमाण पत्र (सीडी) पर भरोसा करना जारी रखा है। अवसंरचना क्षेत्र में कर्ज में चूक की दरों में उल्लेखनीय गिरावट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है जिससे बैंकों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने की मजबूत मांग बढ़ी है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी बॉण्ड जारी कर वित्त जुटाने पर विचार कर रही हैं।

[13] https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/markets/india-stock-market-outlook।

[14] बिज़नेस स्टैंडर्ड, "मेगा आईपीओ टू शाइन धिस दिवाली: ह्यूंदई, स्विगी, एनटीपीसी सेट फॉर लॉन्च", सितंबर 26 2024।

[15] बिजनेस स्टैंडर्ड, "माइक्रोफाइनेंस ग्रोथ ड्रिवन मोर बाय लेंडर्स लोन डिस्बर्समेंट दॅन डिमांड", 29 सितंबर 2024।

[16] https://mfinindia.org/assets/upload_image/news/pdf/08_Jul_MFIN%20takes%20proactive%20steps%20for%20strengthening%20responsible%20lending.pdf।

[17] ट्रांसयूनियन सिबिल, क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर - सितंबर 2024.

वैश्विक स्तर पर, बैंकिंग, वित्त और भुगतान में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि देश तत्काल भुगतान समाधान और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) निर्मित या शुरू कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 134 देश डिजिटल फिएट मुद्राएं विकसित कर रहे हैं।[18] सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (एस डबल्यू आई एफ़ टी) ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों को सीबीडीसी और डिजिटल आस्तियों के साथ जोड़ने की योजना बनाई है ताकि विभिन्न प्रकार की आस्तियों और मुद्राओं का लेनदेन संभव हो सके।[19] 22 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में आयोजित 'समिट ऑफ दी फ्यूचर' में 'पैक्ट फॉर दी फ्यूचर'को अपनाया गया जिसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और सुरक्षित और समावेशी डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह मानव अधिकारों और न्यायसंगत भागीदारी पर बल देते हुए जिम्मेदार डेटा अभिशासन, गोपनीयता संरक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अभिशासन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

भारत में, डिजिटलीकरण एक स्व-चालित विकास पथ पर अग्रसर है। भारत का फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर ढंग से विकसित हो रहा है। पंजीकृत फिनटेक स्टार्टअप की संख्या जो वर्ष 2021 में 2,100 थी बढ़कर 2024 में 10,200 हो गई है, जो पाँच गुना वृद्धि है।[20] 2023-24 में ₹एक लाख से कम के अधिकांश व्यक्तिगत ऋण फिनटेक के माध्यम से प्राप्त किए गए।[21] 2024-25 की पहली तिमाही में, फिनटेक ऋण वितरण में व-द-व (वाई-ओ-वाई) 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो डिजिटल ऋण के लिए ग्राहकों की मजबूत मांग को रेखांकित करता है।[22] वित्तीय सेवा क्षेत्र भी परिवर्तनीय आय स्रोतों और सीमित ऋण इतिहास वाले विशिष्ट क्षेत्रों की बढ़ती क्षमता का दोहन कर रहा है।[23]

लगातार दो महीने लक्ष्य से कम रहने के बाद सितंबर में मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई, क्योंकि खाद्य मूल्य पुन: बढ़ने से प्रतिकूल सांख्यिकीय आधार प्रभाव और बढ़ गया था। यह तीव्र वृद्धि खाद्य समूह के कारण थी, लेकिन ईंधन की कीमतों में अपस्फीति के कम होने के साथ-साथ मूल (कोर) मुद्रास्फीति में भी उछाल दर्ज किया गया। सब्जियों के संबंध में खाद्य मूल्य दबाव *खरीफ* फसल की मजबूत आवक के साथ अल्पकालिक हो सकता है, हालांकि तेल और वसा की कीमत में उछाल से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की इनपुट लागत के माध्यम से समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले दूसरे क्रम के प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि *रबी* फसलों की संभावनाओं में सुधार के कारण सर्दियों में खाद्य कीमतों में सामान्य कमी से हेडलाइन मुद्रास्फीति का पुनर्संतुलन हो सकता है, ताकि 2024-25 की चौथी तिमाही से यह लक्ष्य के अनुरूप हो सके।

इस पृष्ठभूमि में आलेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को समाहित किया गया है, और अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ हैं।

II. वैश्विक स्थिति

भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ता प्रदर्शित की है। चूंकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम होकर लक्ष्य की ओर बढ़न जारी रखा, कई केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत नरमी लाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। सितंबर 2024 के अपने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण में, ओईसीडी ने सेवा क्षेत्र की गतिविधि में आई मजबूत गति के कारण 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंकों (बीपीएस) से बढ़ाकर 3.2 प्रतिशत (मई 2024 में उनके पहले के पूर्वानुमान से) कर दिया (चार्ट II.1)। 2025 के लिए संवृद्धि पूर्वानुमान 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया।

---

18 अटलांटिक काउन्सिल। सीबीडीसी ट्रैकर। सितंबर 2024 को देखा गया।

19 स्विफ्ट प्रेस विज्ञप्ति। अक्टूबर 3 2024। वैश्विक बैंक 2025 से लाइव डिजिटल आस्ति लेनदेन के परीक्षण के लिए स्विफ्ट का उपयोग करेंगे।

20 बीम्स फिनटेक फंड और जेएम फाइनेंशियल (2024)। "इंडियन फिनटेक जर्नी फ्रॉम इवोल्यूशन टू मेगा पब्लिक लिस्टिंग"।

21 एक्सपेरियन (2024)। "स्मॉल इज बिग – हाऊ फिनटेक्स आर रिवोल्यूशनाइजिंग लेंडिंग

22 फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफएसीई), "फैसेट्स। डिजिटल ऋण पर एफएसीई सदस्यों के रुझान, वि.व 24-25 की पहली तिमाही, अंक 11"।

23 दी लाइवमिंट, "बैंक्स, फिनटेक्स रोल आउट रेड कार्पेट फॉर क्रिएटर इकॉनोमी।" 28 सितंबर 2024।

चार्ट II.1: ओईसीडी वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान

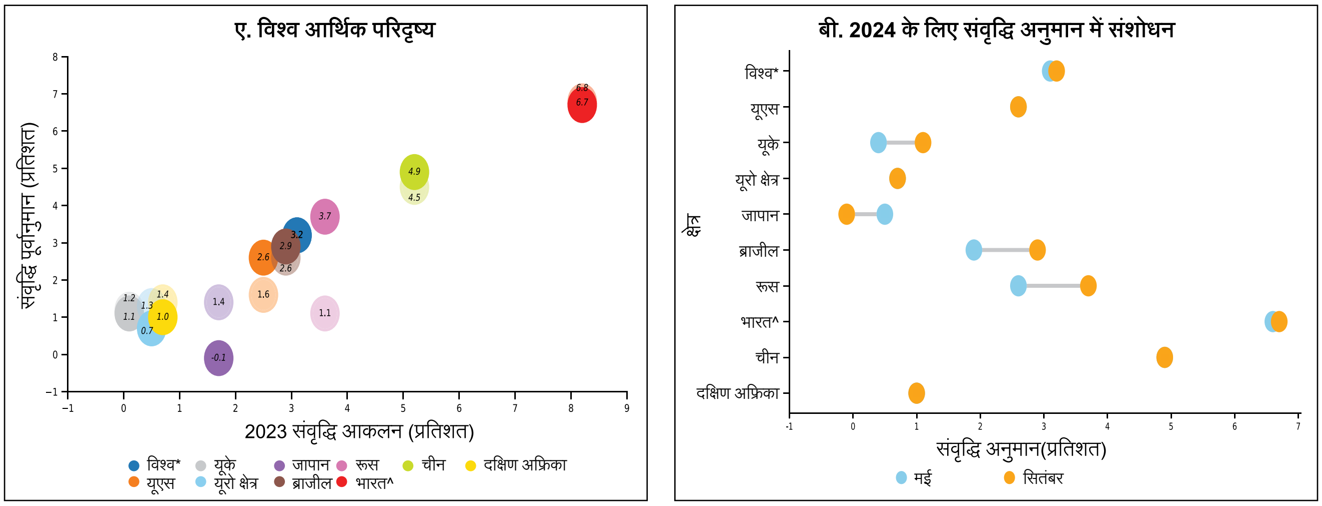

टिप्पणियाँ: 1. *: पीपीपी भारित, ^:भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।
2. चार्ट II.1ए में गहरे (हल्के) छायांकित वृत्त 2024 (2025) के पूर्वानुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत: ओईसीडी।

हमारा मॉडल-आधारित नाउकास्ट 2024 की तीसरी तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति में मंदी की ओर इशारा करता है, जिसका कारण है बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिम (चार्ट II.2)।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) अपने ऐतिहासिक औसत स्तरों से ऊपर रहा, लेकिन सितंबर में इसमें मामूली कमी आई (चार्ट II.3ए)। कंटेनर शिपिंग लागत में जुलाई 2024 में दर्ज किए गए चरम स्तरों से कुछ कमी दर्ज की गई, लेकिन उनका स्तर उच्च बना हुआ है (चार्ट II.3बी)। ईस्टकोस्ट और मैक्सिको की खाड़ी में बंदरगाह कर्मचारियों की हड़ताल ने सितंबर में माल ढुलाई और शिपिंग लागत को बढ़ा दिया जिससे बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अक्टूबर में श्रमिकों के बीच समझौते पर पहुंचने के बाद पूर्ववत हुई(चार्ट II.3सी)। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण भू-राजनीतिक जोखिम उच्च बने रहे, हालांकि जुलाई 2024 से इसमें कुछ कमी आई है (चार्ट II.3डी)।

चार्ट II.2: वैश्विक जीडीपी वृद्धि तात्कालिक अनुमान (नाउकास्ट) (ति-द-ति)

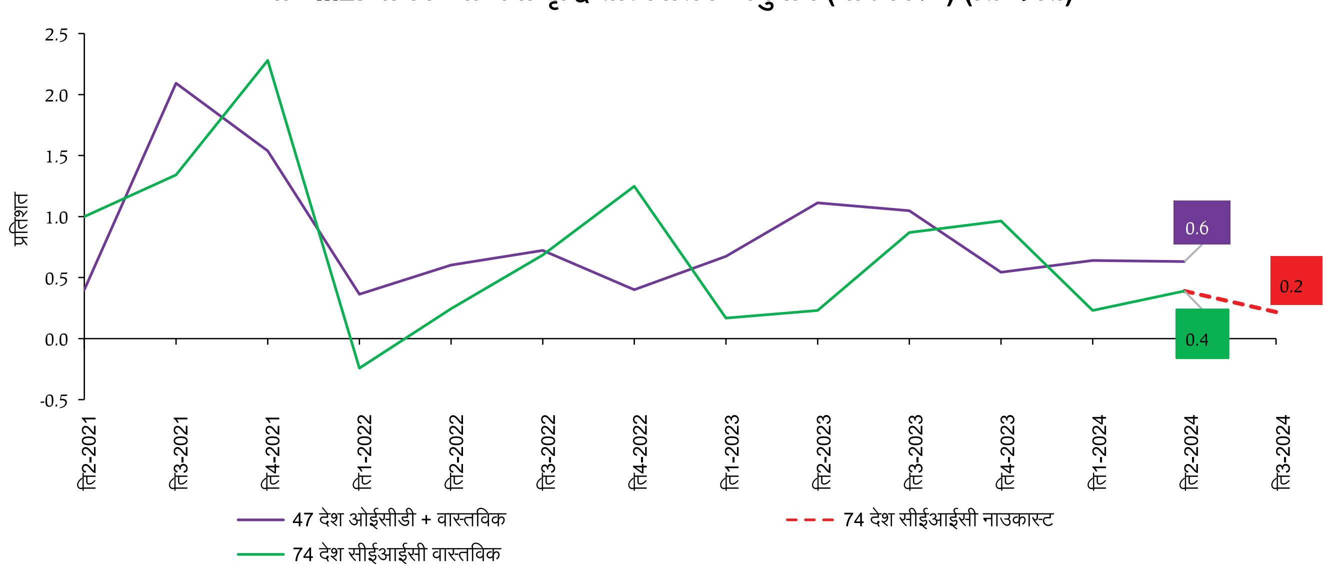

स्रोत : सीईआईसी; ओईसीडी; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.3: आपूर्ति श्रृंखला दबावों और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान

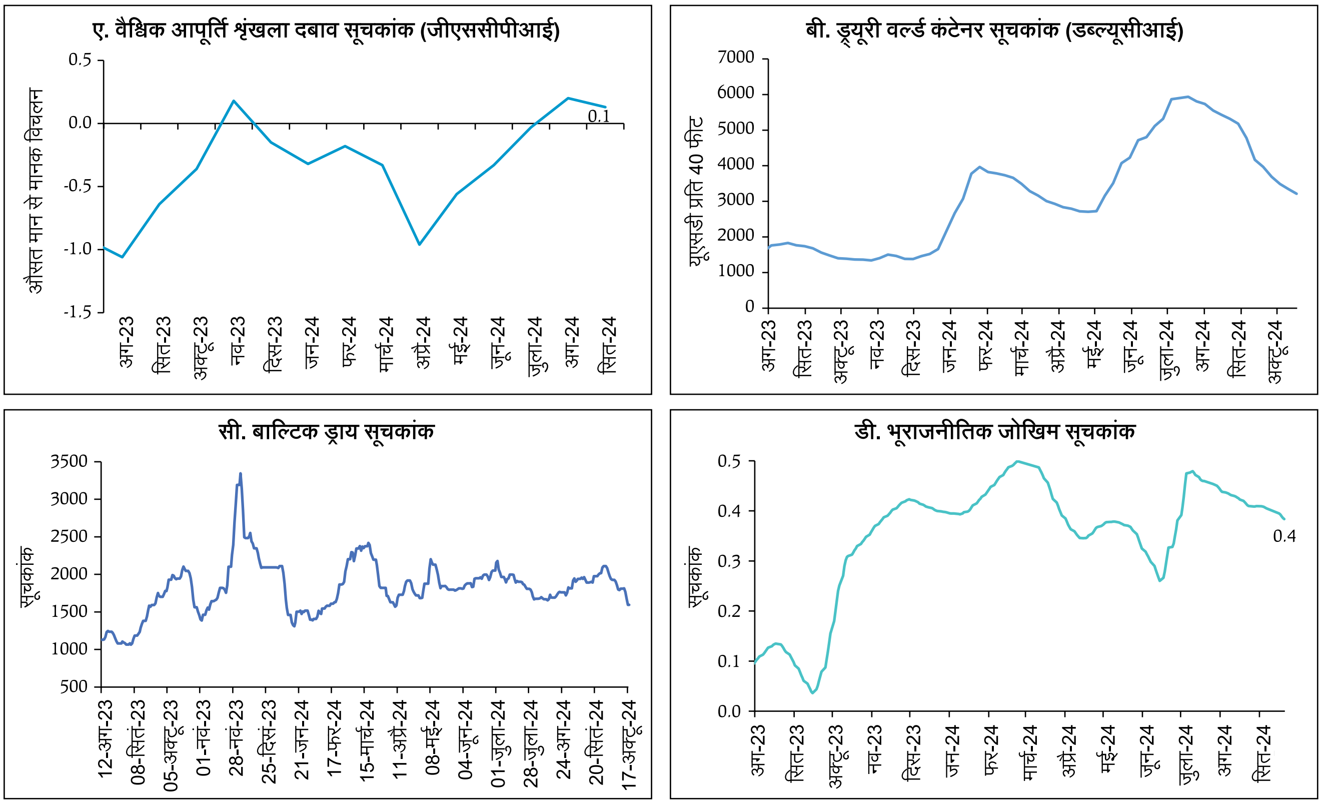

टिप्पणियां: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों का डेटा दर्शाता है।
2. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक रूप से मूल्यांकन किए गए डब्ल्यूसीआई में प्रमुख पूर्व पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर फ्रेट दरों की रिपोर्ट की जाती है। यह समग्र डेटा 8 शिपिंग मार्गों का भारित औसत दर्शाता है और इसे यूएसडी प्रति 40-फुट कंटेनर में रिपोर्ट किया गय है।

स्रोत: फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, सितंबर 2024; और ब्लूमबर्ग।

सितंबर 2024 में यू.एस., यूरो क्षेत्र, भारत और जापान में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ, लेकिन यू.के. में स्थिति खराब हुई (चार्ट II.4ए)। प्रमुख एई और ईएमई में वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है (चार्ट II.4बी)।

चार्ट II.4: उपभोक्ता मनोभाव और वित्तीय स्थितियां

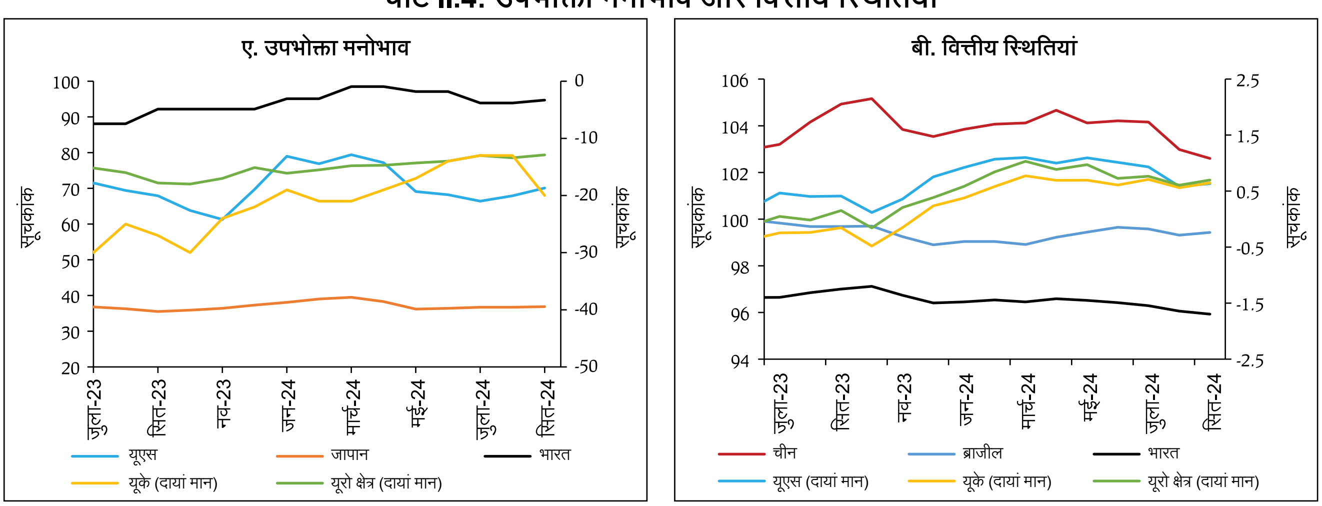

टिप्पणियां: 1. जापान: 50 से अधिक का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरो क्षेत्र और यूके: (-)100 अत्यधिक आत्मविश्वास की कमी, 0 तटस्थता और 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और यूएस: मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता का विश्वास उतना अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैश द्वारा निर्मित और ईएमई से संबंधित) के लिए 100 से नीचे का अंक समायोजनात्मक है और ऊपर का अंक असमायोजनात्मक है। एई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक सकारात्मक मूल्य समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और धनात्मक मूल्य उसके विपरीत स्थिति को।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.5: वैश्विक पीएमआई

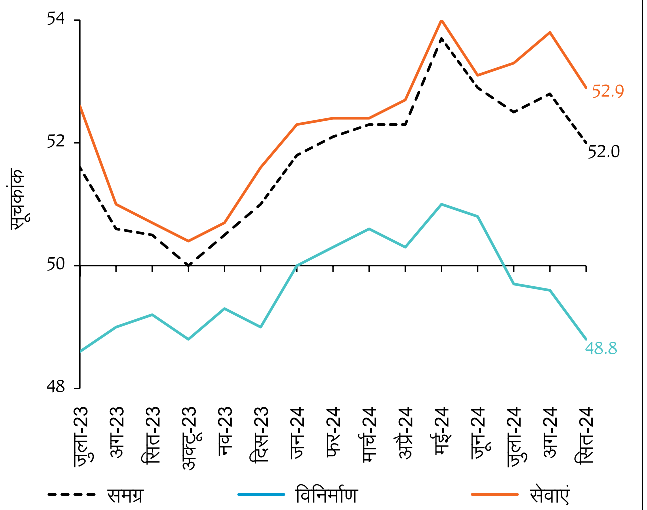

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है, 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और 50 से नीचे इसकी विपरीत स्थिति दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात ऑर्डर

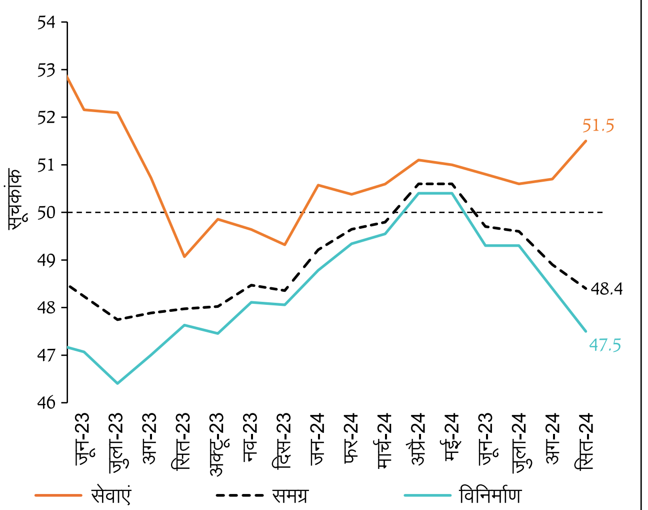

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है, 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और 50 से नीचे इसकी विपरीत स्थिति दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर में आठ महीने के निचले स्तर पर आ गया, जो विनिर्माण में मंदी के कारण हुआ, तथा जो उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार वृद्धि में संकुचन के कारण ग्यारह महीने के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, सेवा गतिविधि में लगातार बीसवें महीने विस्तार हुआ, जिसने विनिर्माण में आई कमी की भरपाई करते हुए वैश्विक समग्र पीएमआई को विस्तार क्षेत्र में रखा, लेकिन इसमें क्रमिक गिरावट रही (चार्ट II.5)।

निर्यात ऑर्डर के संबंध समग्र पीएमआई सितंबर में घट गया क्योंकि सेवा निर्यात ऑर्डर में वृद्धि विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में गिरावट से अधिक थी (चार्ट II.6)।

वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सितंबर में तेज उछाल दर्ज किया गया क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में जो गिरावट आई वह धातु की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रभावहीन हो गई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में सितंबर में 4.4 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि हुई (चार्ट II.7ए)। हालांकि, अक्टूबर के पहले पखवाड़े में इसने इस वृद्धि को आंशिक रूप से उलट दिया, क्योंकि सूचकांक में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आई। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक ने सितंबर में 3 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2022 के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है। सभी श्रेणियों के मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई, जिसमें महीने के दौरान चीनी की कीमतों में 10.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट II.7बी)। बेस मेटल के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करने के बाद मांग में सुधार के दृष्टिकोण से सितंबर में धातु की कीमतों में वृद्धि हुई। हालांकि अक्टूबर में गति धीमी पड़ गई क्योंकि धातु की कीमतों ने सितंबर की अपनी वृद्धि को आंशिक रूप से कम कर दिया। सितंबर में सोने की कीमतों में 5.0 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि हुई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो कि अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच सुरक्षित पनाहगाह की मांग के कारण हुआ (चार्ट II.7सी)। हालांकि, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में सितंबर में 8.8 प्रतिशत (मासिक) की तीव्र गिरावट दर्ज की गई - अगस्त में लगभग 81 डॉलर प्रति बैरल से सितंबर में लगभग 74 डॉलर प्रति बैरल - क्योंकि सऊदी अरब द्वारा दिसंबर से "स्वैच्छिक कटौती" को समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा से आपूर्ति के बेहतर दृष्टिकोण ने भू-राजनीतिक तनावों और मांग संबंधी चिंताओं से उभरने वाली बाधाओं को कम कर दिया। अक्टूबर की शुरुआत में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया और सितंबर के अंत के

चार्ट II.7: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें

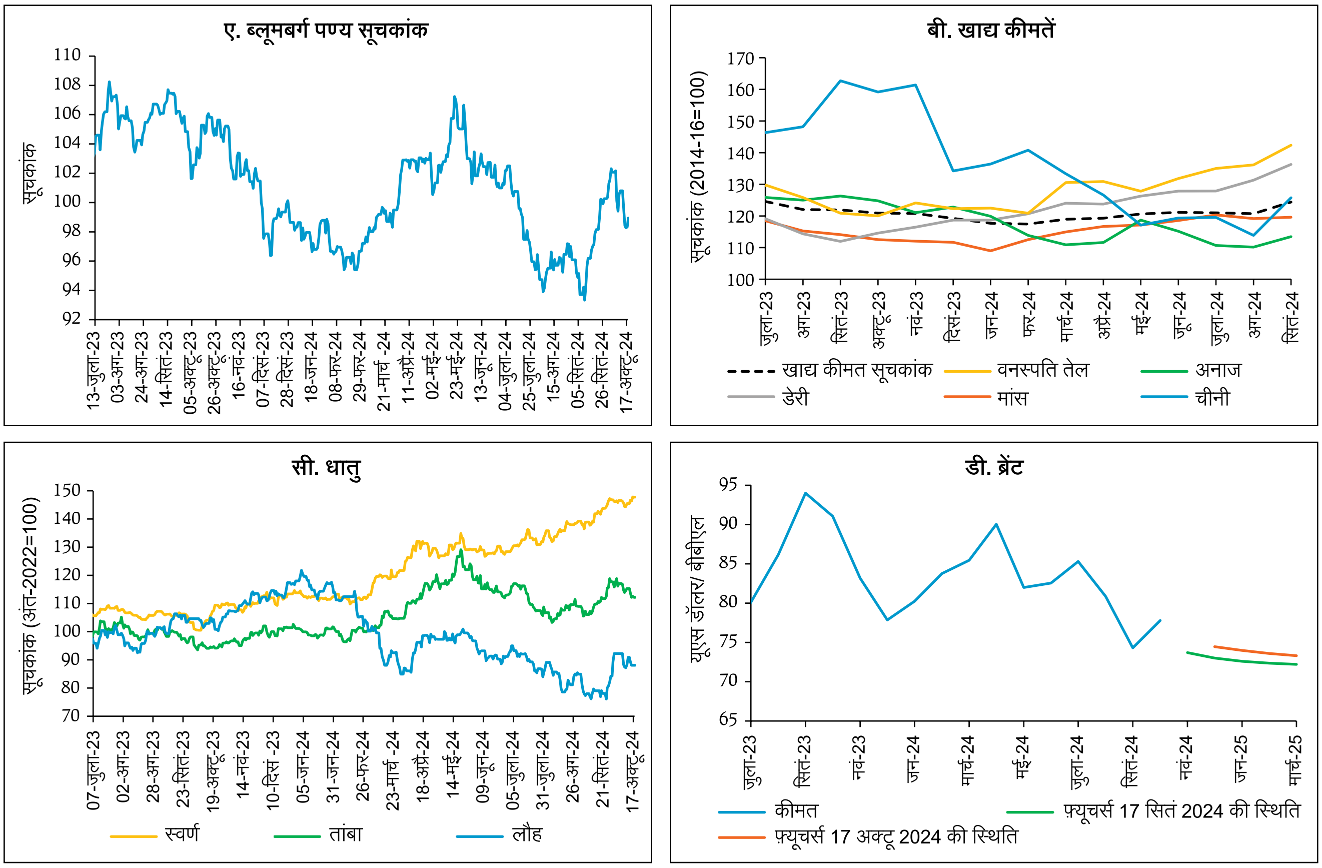

स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

स्तर से 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 17 अक्टूबर 2024 तक 74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया (चार्ट II.7डी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही, जो असमान रूप में थी। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त के 2.5 प्रतिशत से सितंबर में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) डिफ्लेटर के संदर्भ में मुद्रास्फीति जुलाई के 2.5 प्रतिशत से कम होकर अगस्त में 2.2 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र और यू.के. में हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर में कम होकर क्रमशः 1.8 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजा खाद्य को छोड़कर सीपीआई) सितंबर में कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8ए)। ईएमई देशों में सितंबर में ब्राजील में मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन सितंबर में रूस और चीन तथा अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में कम हो गई (चार्ट II.8बी)। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर और सेवा मुद्रास्फीति में गिरावट आई; लेकिन वह हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट II.8सी और 8डी)।

सितंबर के पहले सप्ताह में वैश्विक इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ, जो यूएस फेड द्वारा नीति दर में 50 बीपीएस की कटौती के निर्णय से प्रेरित था। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक ने सितंबर में 2.2 प्रतिशत (माह-दर-माह) वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.9ए)। एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रोत्साहन उपायों की घोषणा के बाद चीन में इक्विटी बाजारों ने 2008 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ सप्ताह दर्ज किया। आर्थिक सुधार और प्रत्याशित आर्थिक प्रोत्साहन पर बाजार की निराशा के बीच अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चीन के इक्विटी बाजारों ने अपने लाभ में कुछ गिरावट दर्ज की। सितंबर में 10-वर्षीय और 2-वर्षीय बॉण्ड, दोनों पर अमेरिकी सरकार की

चार्ट II.8: मुद्रास्फीति: एई और ईएमई

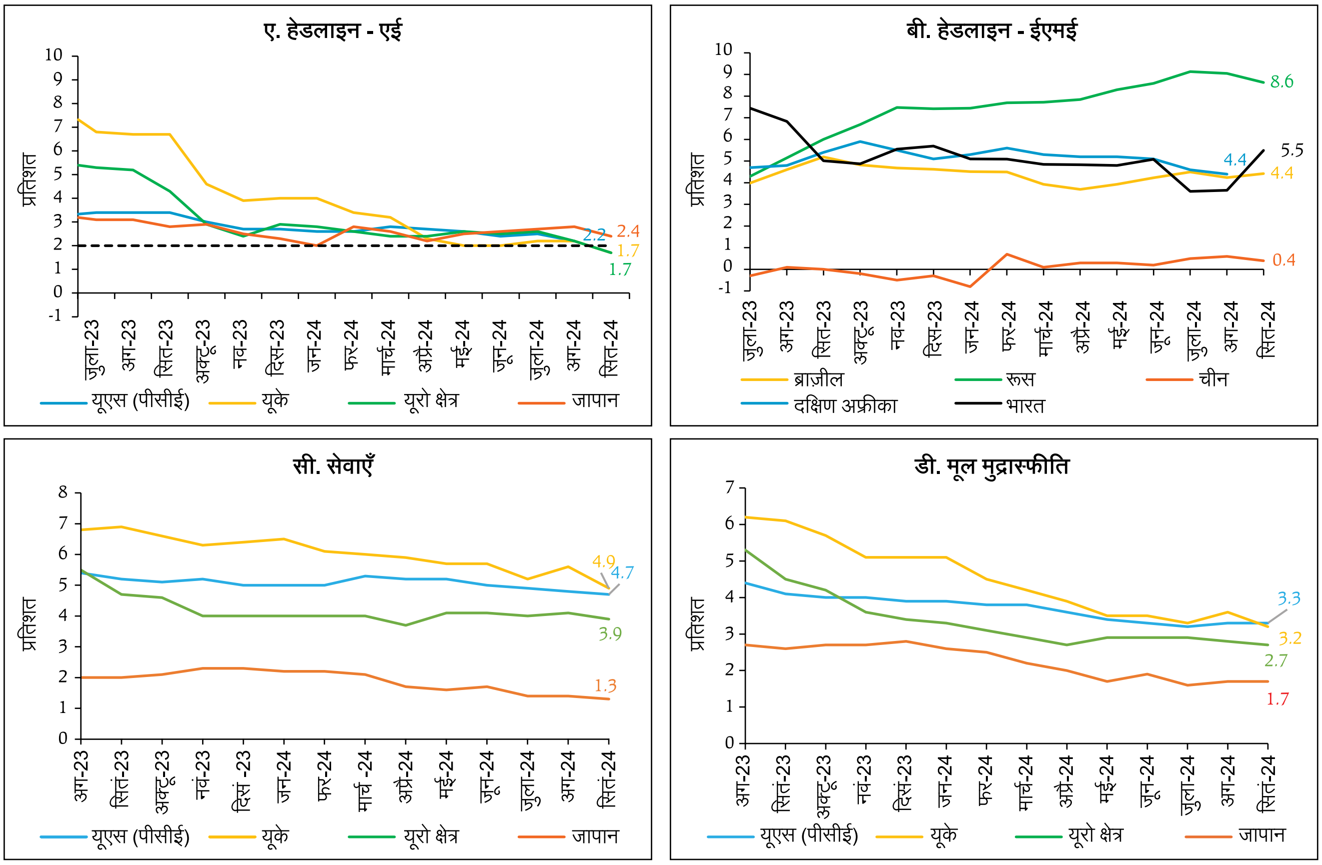

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

प्रतिभूतियों के प्रतिफल क्रमशः 12 बीपीएस और 28 बीपीएस कम हो गए, क्योंकि बाजारों ने फेड दर में कटौती को हिसाब में लिया। चूंकि 2-वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए प्रतिफल अपेक्षाकृत और कम हो गया, स्प्रेड (10-वर्षीय घटा 2-वर्षीय) विपरीत दिशा में चला गया और सितंबर में सकारात्मक हो गया (चार्ट II.9बी)। हालांकि अगस्त की शुरुआत के बाद पहली बार अक्टूबर की शुरुआत में यूएस 10-वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल 4 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया, क्योंकि उम्मीद से बेहतर जॉब मार्केट डेटा ने बड़ी नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया। मुद्रा बाजारों में यूएस डॉलर कमजोर हुआ, और सितंबर में उसमें 0.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई। इसके साथ ही मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट में पूंजी प्रवाह के कारण ईएमई एमएससीआई मुद्रा सूचकांक सितंबर में 1.7 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट II.9सी और II.9डी)। हालांकि, अक्टूबर की शुरुआत में, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर सुरक्षित निवेश की मांग के कारण यूएस डॉलर में तेजी से मजबूती आई। इसके साथ ही, अक्टूबर में अब तक ईएमई मुद्राओं में गिरावट रही है (17 अक्टूबर 2024 तक)

एई केंद्रीय बैंकों की ओर देखें तो यूरो क्षेत्र, दक्षिण कोरिया और आइसलैंड ने अपने नीति दरों में 25 बीपीएस की कटौती की, और न्यूजीलैंड ने अक्टूबर में अपनी बेंचमार्क दर में 50 बीपीएस की कटौती की। स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और चेक गणराज्य ने सितंबर की अपनी बैठकों में अपनी बेंचमार्क दरों में 25 बीपीएस की कमी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में अपनी नीति दर को अपरिवर्तित रखा (चार्ट II.10 ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों को देखें तो थाईलैंड और फिलीपींस ने अक्टूबर में अपनी नीति दरों में 25 बीपीएस की कटौती की। सितंबर में दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और हंगरी ने अपनी प्रमुख दरों में 25 बीपीएस की कटौती की, जबकि कोलंबिया ने अपनी नीति दर में 50 बीपीएस की कमी की (चार्ट II.10 बी)। चीन ने अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन उपायों की एक श्रृंखला की

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार

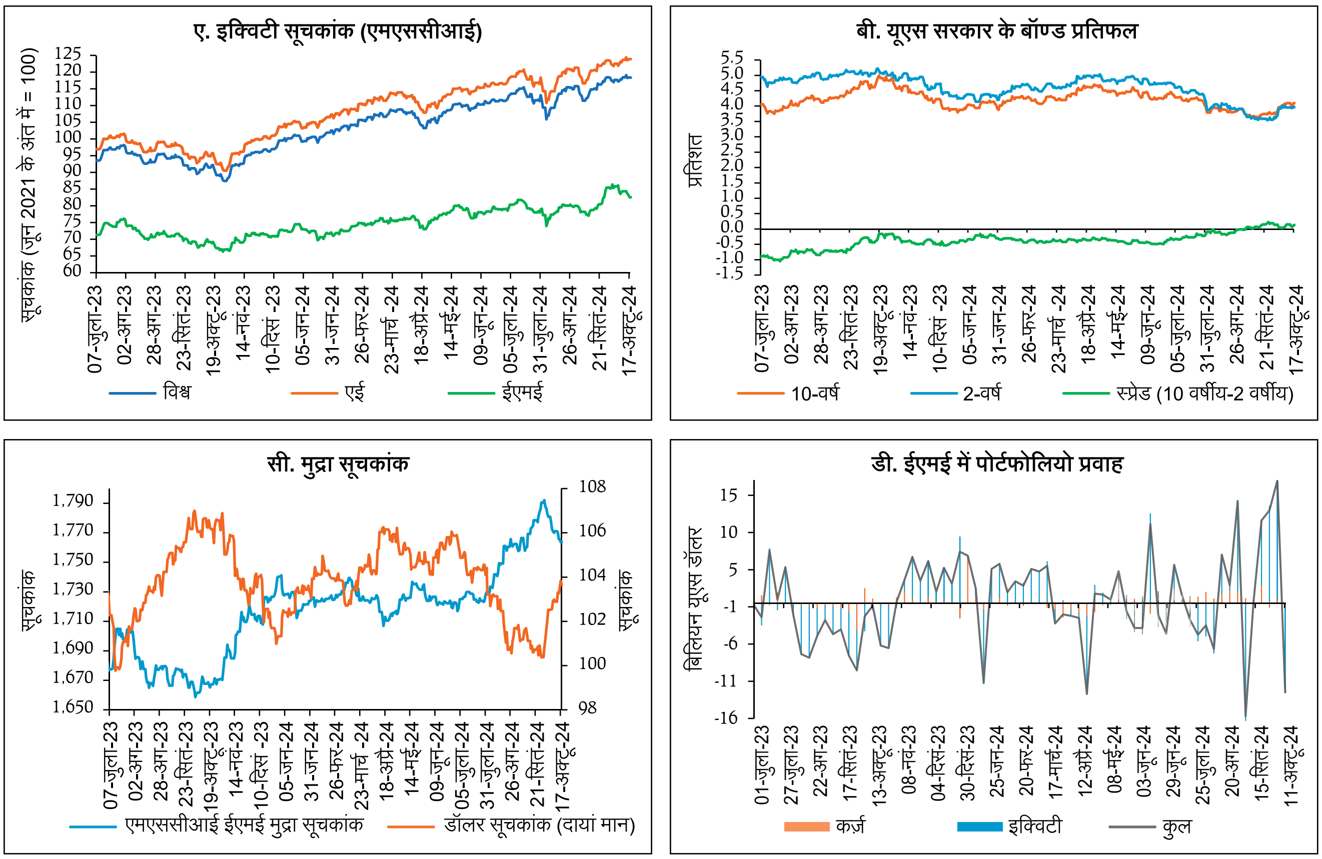

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

घोषणा की, जिसमें सात दिवसीय रिवर्स रेपो दर में 20 बीपीएस की कटौती, मध्यम अवधि की उधार सुविधा दर में 30 बीपीएस की कटौती और रिज़र्व रिक्वायरमेंट अनुपात में 50 बीपीएस की कटौती शामिल है।

चार्ट II.10: नीतिगत दरों में परिवर्तन

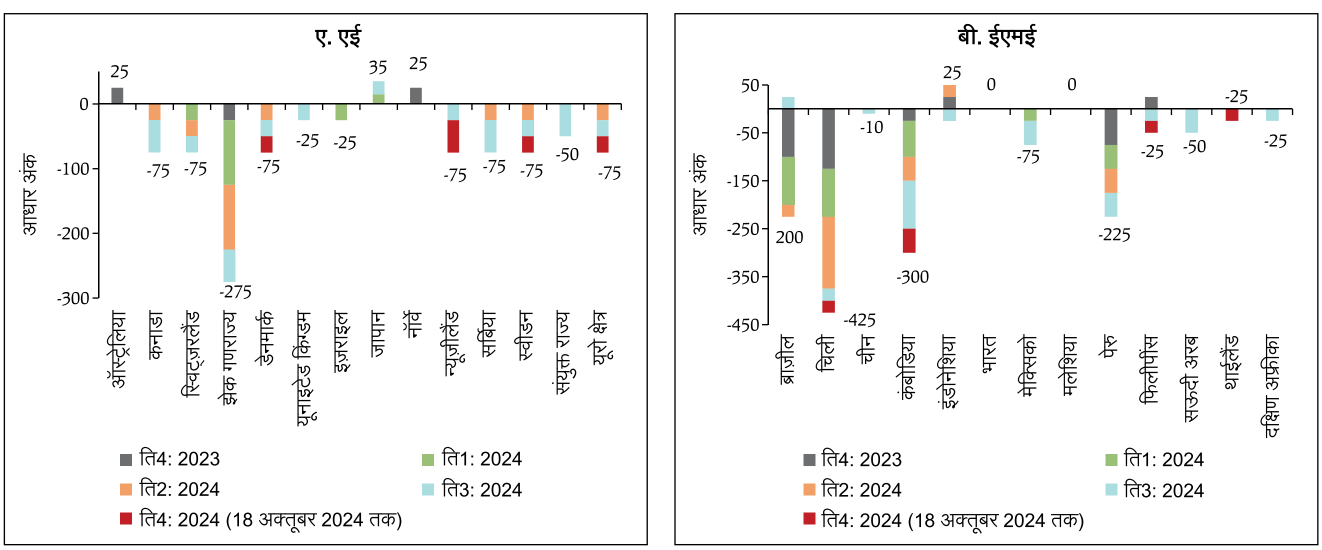

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में अपनी गति में क्रमिक गिरावट के बावजूद उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की जिसके कई कारक हैं और जिनका उल्लेख परिचयात्मक खंड में किया गया है। रिज़र्व बैंक के परिवार सर्वेक्षण के नवीनतम दौर के अनुसार वर्तमान स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा और उनकी भविष्य की अपेक्षाओं में क्रमिक रूप से सुधार हुआ है (चार्ट III.1ए)। विनिर्माताओं ने आगामी तिमाहियों में क्षमता उपयोग (सीयू) पर सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनाए रखा (अनुलग्नक 1)। विभिन्न उद्योग हितधारकों से प्राप्त सूचनाएं भी भारत में भविष्य की विकास संभावनाओं के प्रति निरंतर आशावाद की ओर इशारा करती हैं (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1 रिज़र्व बैंक के उद्योग निगरानी समूह (आईएमजी) से फीडबैक

रिजर्व बैंक उद्योग संघों के प्रतिनिधियों का अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण करता है, जिसमें कई उद्योग निकाय, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और बैंक शामिल हैं। सर्वेक्षण के सितंबर 2024 दौर की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं।

खपत

- गैर-टिकाऊ वस्तुओं की खपत में उछाल देखा गया क्योंकि ग्रामीण खपत में वृद्धि शहरी खपत से अधिक रही, खासकर गैर-खाद्य श्रेणी में।
- टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें छोटे शहरों में प्रीमियम/फीचर-समृद्ध क्षेत्रों पर खर्च में वृद्धि दर्ज की गई।
- आगामी त्यौहारी मौसम में उपभोक्ता उत्पादों की मांग में तेजी आने की उम्मीद है।

निवेश

- निवेश मांग में तेजी बुनियादी ढांचे से संबंधित क्षेत्रों और कुछ विनिर्माण क्षेत्रों, जैसे रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और हरित ऊर्जा द्वारा संचालित की जा रही है।
- विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोगिता विभिन्न उद्योगों में 70 से 80 प्रतिशत के बीच होने के कारण, सर्वेक्षण के अधिकांश उत्तरदाताओं को 2024-25 की दूसरी छमाही में निजी निवेश में सुधार की उम्मीद है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से निवेश में तेजी आई है और आने वाले महीनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) और आतिथ्य क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में अधिक निजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
- मध्यम अवधि के पूंजीगत व्यय का दृष्टिकोण (2024-2028) सकारात्मक है, जिसे आंशिक रूप से सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश के इरादों से समर्थन मिला है।

अन्य विकास के चालक

- रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड से आगे निकल गए हैं और क्रेडिट अनुपात 2.224 है। बिजली, स्थावर संपदा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में क्रेडिट अनुपात में सुधार हुआ, जबकि ऑटो कंपोनेंट, निर्यात और सेवाओं में नरमी देखी गई।
- उभरती प्रौद्योगिकियों, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई); क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की बढ़ती मांग से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अधिक नियुक्तियाँ और बेहतर लाभ मिलेंगे।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में राजस्व वृद्धि स्वास्थ्य सेवा, खपत, कृषि से जुड़े क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी व्यवसायों जैसे कि कपड़ा और समुद्री खाद्य से प्रेरित होने की उम्मीद है।

पिछले तीन वर्षों में एमएसएमई और समग्र खुदरा क्षेत्रों के ऋण चूक में लगातार कमी आई है, हालांकि हाल की तिमाहियों में क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण चूक में मामूली वृद्धि हुई है।25

[24] इनवेस्टमेंट इनफोर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

[25] ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड से प्राप्त सूचना के आधार पर।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान

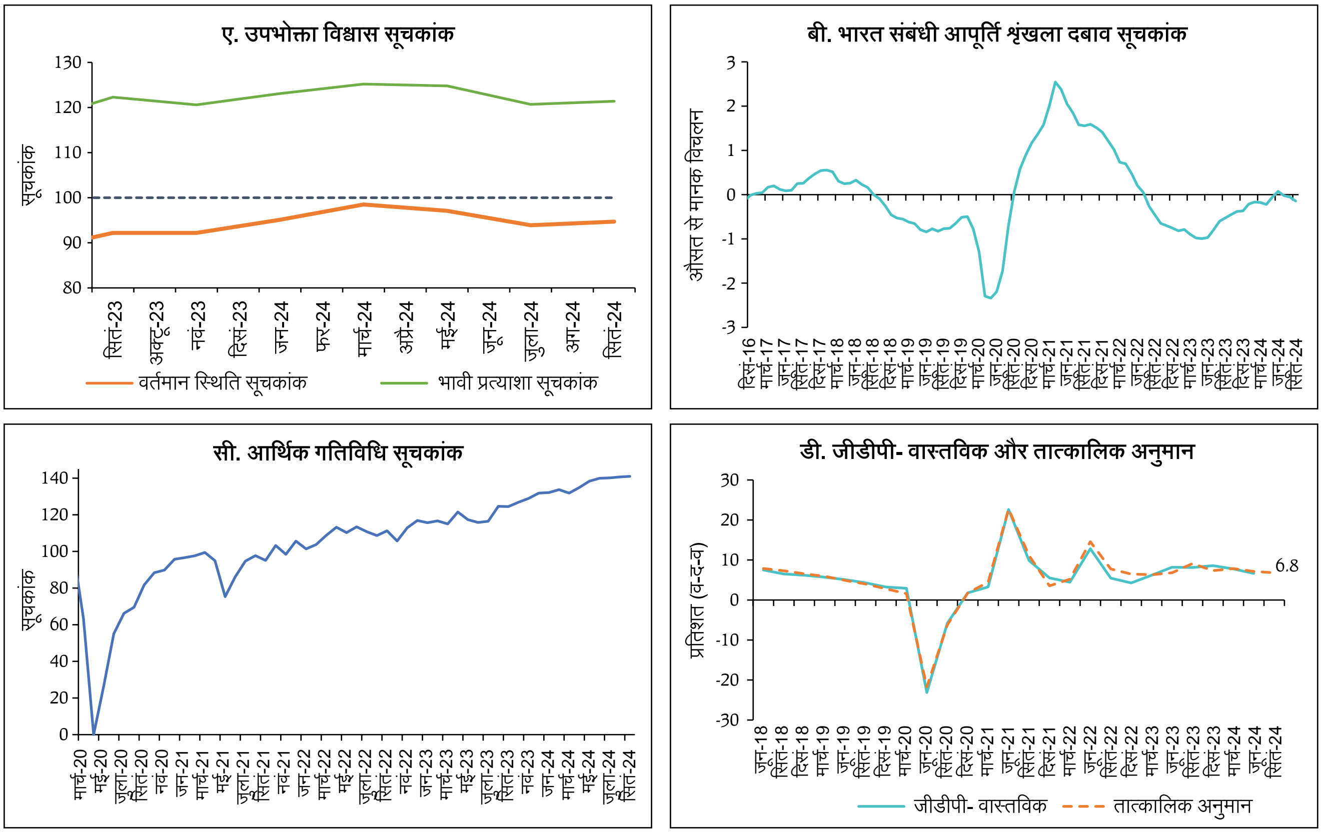

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च-आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को प्राप्त करके किया जाता है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 तक और अप्रैल 2020, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना है, 0 रखा गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस), आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सितंबर में आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव कम हुआ, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे चला गया, हालांकि वे भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं और अक्टूबर में बढ़ गए हैं (चार्ट III.1बी)। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई)[26], उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक श्रृंखला के आधार पर, 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान बताता है (चार्ट III.1सी और III.1डी)।

समग्र मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक यह संकेत देते हैं कि समग्र मांग में वृद्धि जारी रही, लेकिन पिछली तिमाहियों की तुलना में इसकी गति धीमी रही। सितंबर 2024 में भी ई-वे बिल में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.2ए)। सितंबर में टोल संग्रह में 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले महीने में यह 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी (चार्ट III.2बी)।

सितंबर 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 13.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे दोपहिया वाहनों (चार्ट III.3ए) का समर्थन प्राप्त हुआ। सितंबर में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में भी 3.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.3बी)। गैर-परिवहन और परिवहन वाहन, दोनों खंडों में गिरावट के कारण सितंबर में वाहन पंजीकरण में कमी आई (चार्ट III.3सी)। डीजल की खपत में गिरावट के कारण सितंबर 2024 में लगातार दूसरे महीने औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में कमी आई (चार्ट III.3डी)।

2023-24 (जुलाई-जून) के लिए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल

[26] यह सूचकांक उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक प्राप्त करता है।

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल संग्रह

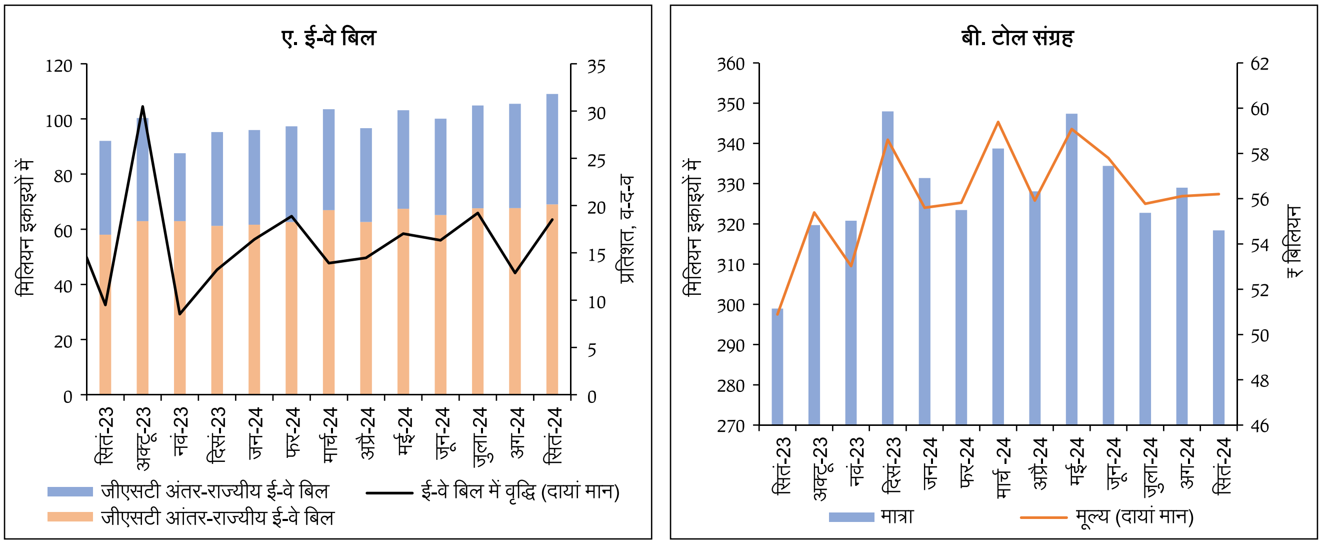

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 60.1 प्रतिशत और 58.2 प्रतिशत तक बढ़ गए, जो सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से अपने उच्चतम स्तर को चिह्नित करते हैं। 2023-24 में बेरोजगारी दर

चार्ट III.3: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक

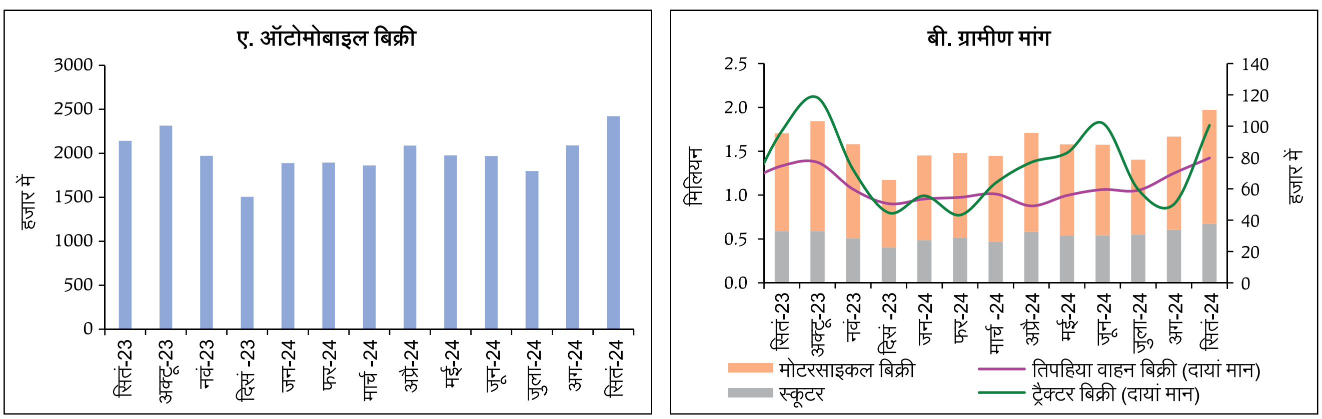

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरर्स (एसआईएएम)।

स्रोत: एसआईएएम; और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए)।

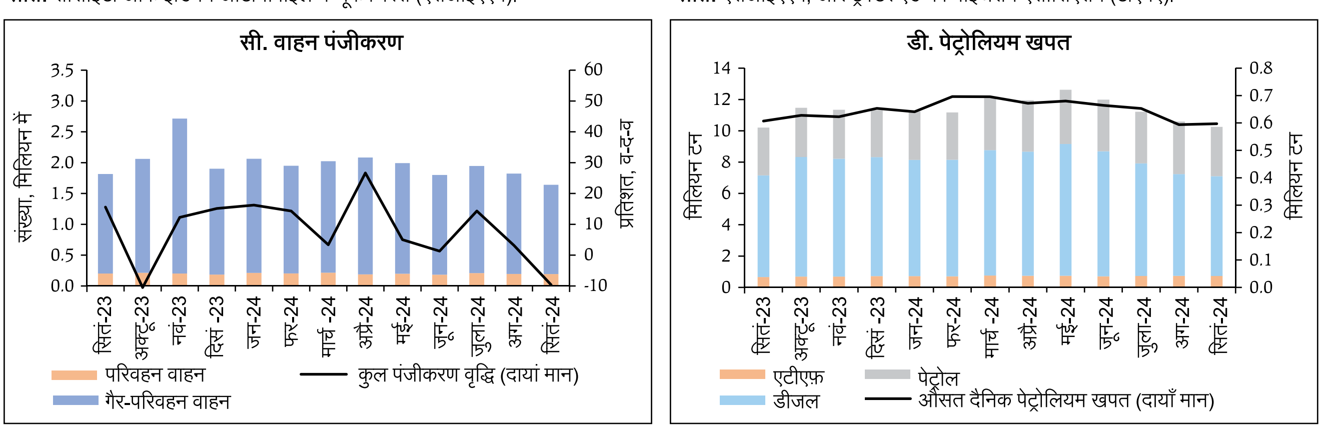

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

स्रोत: पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ।

पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही[27] (चार्ट III.4ए)। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र एलएफपीआर में वृद्धि हुई, जो महिला एलएफपीआर में वृद्धि के कारण हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 6.1 प्रतिशत अंक और शहरी क्षेत्रों में 2.6 प्रतिशत अंक बढ़ी (चार्ट III.4बी और III.4सी)। डब्ल्यूपीआर के मामले में भी इसी तरह की स्थिति रही।

घरेलू उद्यमों में नियमित वेतनभोगी श्रमिकों और हेल्परों की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि आकस्मिक श्रमिकों की हिस्सेदारी घटी (चार्ट III.5ए)। तृतीयक क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी बढ़ी (चार्ट III.5बी)।

क्रय प्रबंधक (पीएमआई) रोजगार सूचकांकों के अनुसार संगठित विनिर्माण रोजगार ने कुछ नरमी के साथ सितंबर 2024 में लगातार सातवें महीने विस्तार दर्ज किया। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर सितंबर में तेज हुई जिसने दो वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.6)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के लिए परिवारों की मांग सितंबर 2024 में लगातार चौथे महीने सिकुड़ी, जो *खरीफ* बुवाई के मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों की अधिक मांग को दर्शाती है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें लगातार सातवें महीने गिरावट दर्ज की गई, जो वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की बढ़ती उपलब्धता की ओर इशारा करती है (चार्ट III.7)।

चार्ट III.4: पीएलएफएस वार्षिक 2023-24 (आयु 15 और ऊपर)

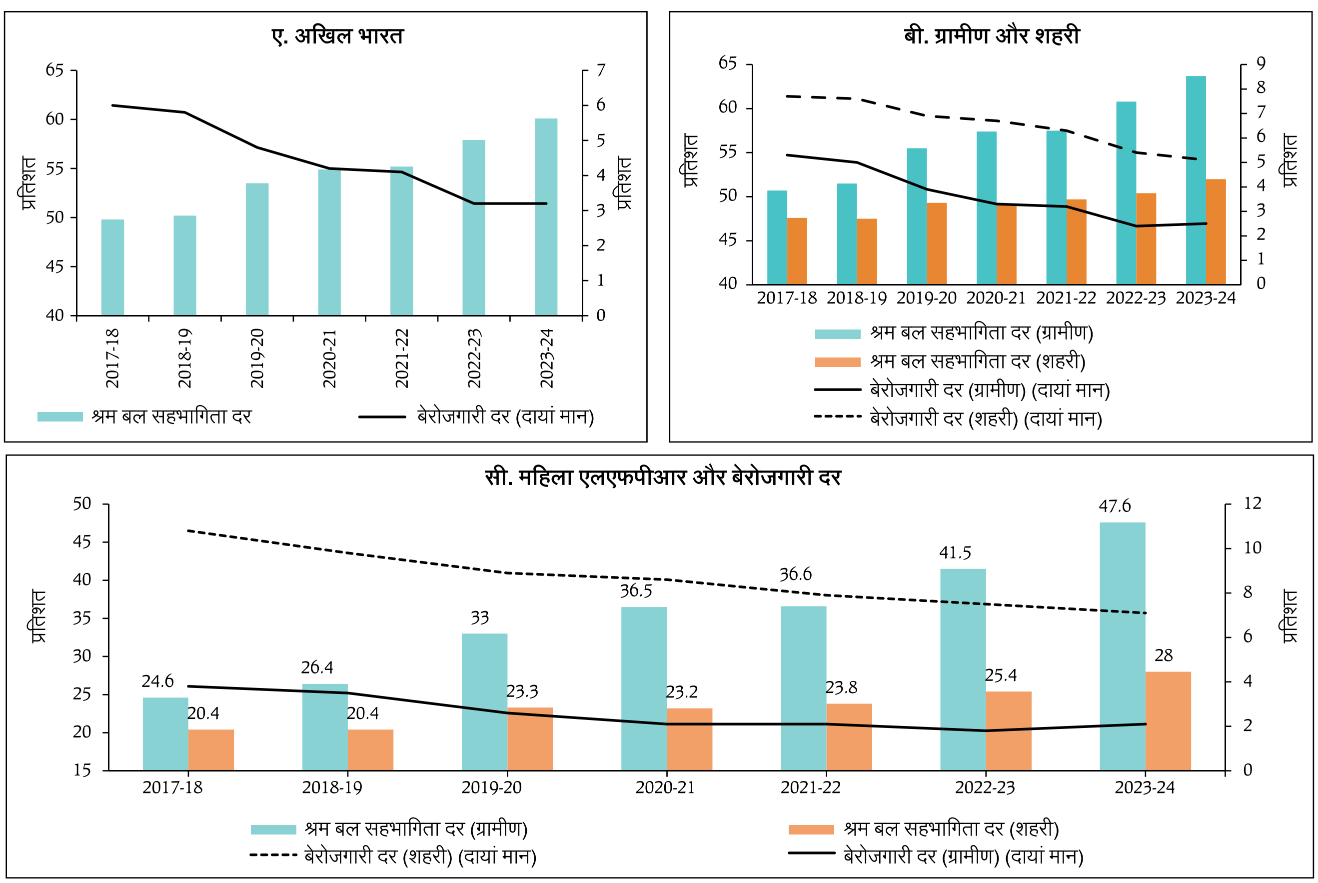

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[27] mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf।

चार्ट III.5: पीएलएफएस वार्षिक 2023-24 (वर्ग और क्षेत्रवार रोजगार)

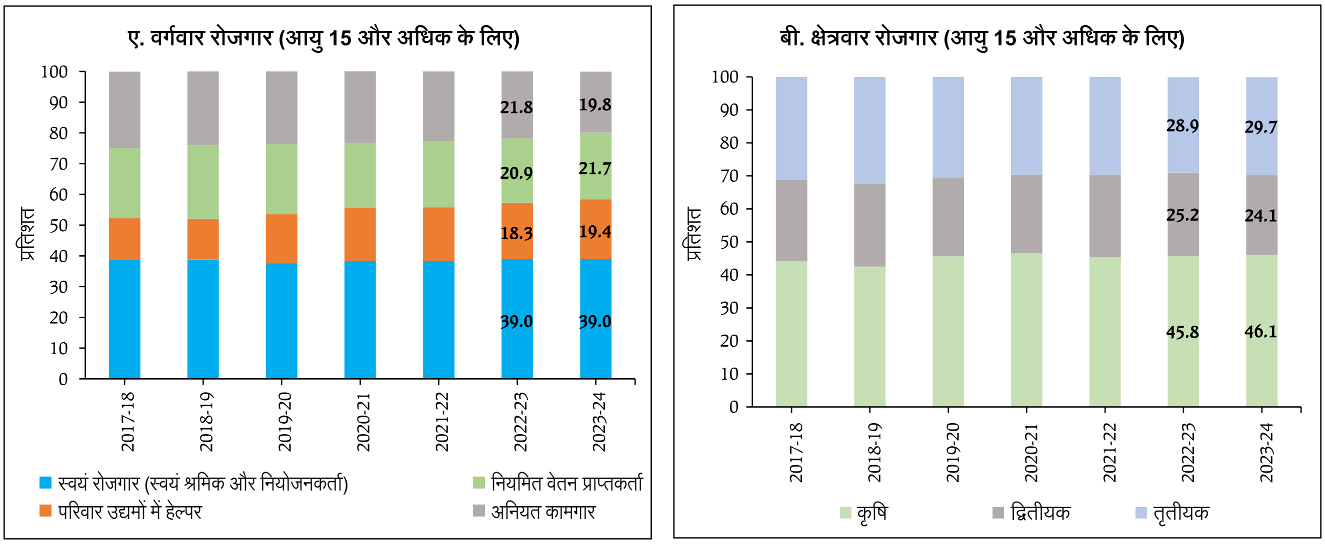

टिप्पणी: विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत चार्ट III.5बी में शामिल किया गया है।
स्रोत: एमओएस एवं पीआई

सितंबर 2024 में भारत का माल निर्यात 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो अनुकूल आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) के साथ 0.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा (चार्ट III.8)।

सितंबर में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 23 (निर्यात समूह का 63 प्रतिशत हिस्सा) के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग सामान, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन, प्लास्टिक और लिनोलियम, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, और तैयार कपड़े (आरएमजी) निर्यात के प्रमुख चालक थे। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, और सिरेमिक उत्पाद तथा कांच के बने सामान पिछड़े रहे (चार्ट III.9)। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 1.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 213.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स,

चार्ट III.6: पीएमआई रोजगार सूचकांक

टिप्पणी: 50 से अधिक पीएमआई मूल्य विस्तार दर्शाता है।
स्रोत: ए एंड पी ग्लोबल

चार्ट III.7: मनरेगा के अंतर्गत परिवारों द्वारा काम की मांग

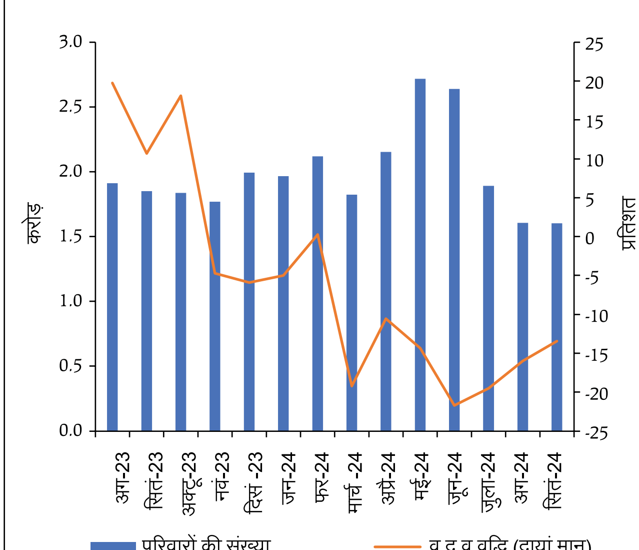

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

चार्ट III.8: भारत का पण्य निर्यात

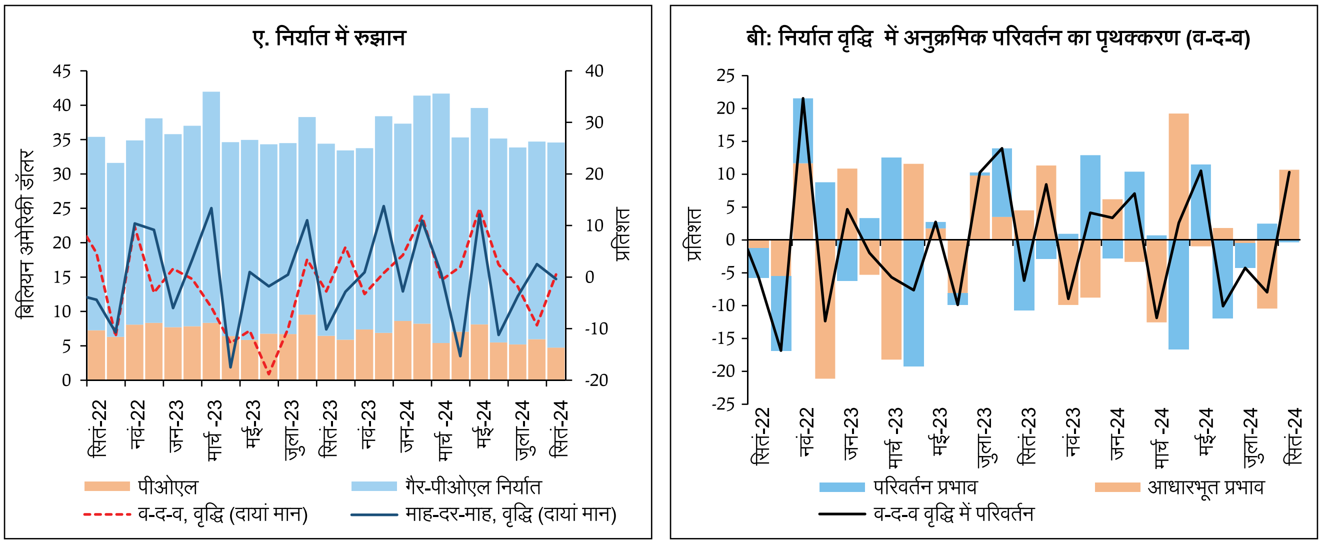

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन और आरएमजी प्रमुख रहे, लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क और अन्य अनाज ने समग्र निर्यात वृद्धि को रोक रखा।

सितंबर 2024 में और अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान 20 प्रमुख देशों में से 13 के साथ निर्यात में वृद्धि हुई, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष 3 स्थान पर रहे।

सितंबर में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ 55.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापारिक आयात हुई, जबकि अनुक्रमिक संकुचन पॉजिटिव बेस इफेक्ट से अधिक था (चार्ट III.10)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 20 वस्तुओं (आयात समूह का 48.7 प्रतिशत हिस्सा) ने सितंबर में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातु, रसायन और सोने ने समग्र आयात वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया, जबकि

चार्ट III.9: भारत का पण्य निर्यात – सापेक्ष योगदान (सितंबर 2023 की तुलना में सितंबर 2024 में)

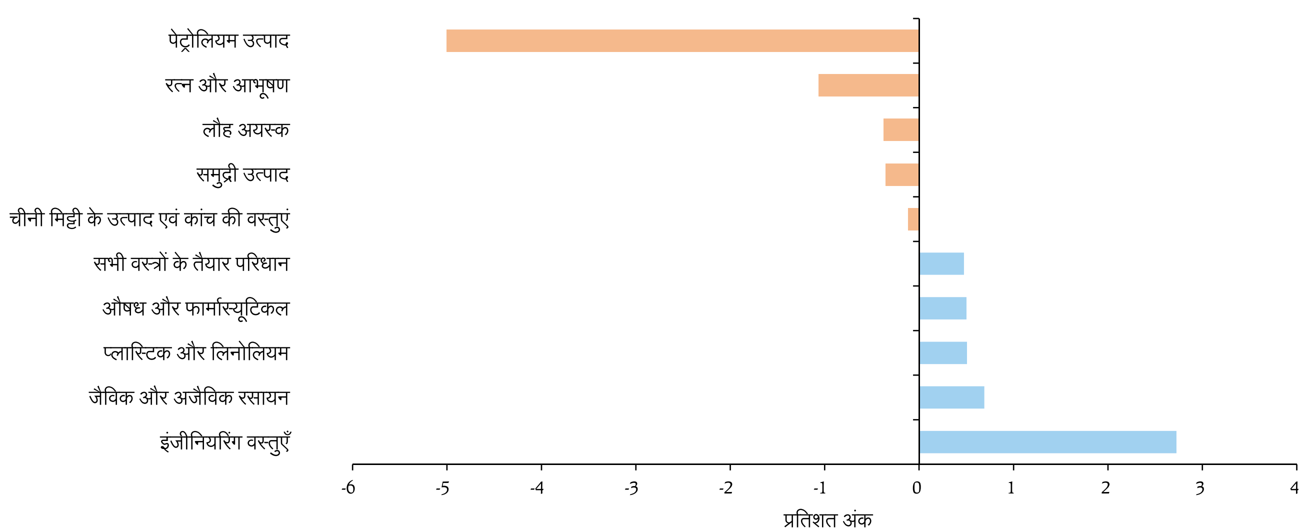

स्रोत: पीआईबी; आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.10: भारत का पण्य आयात

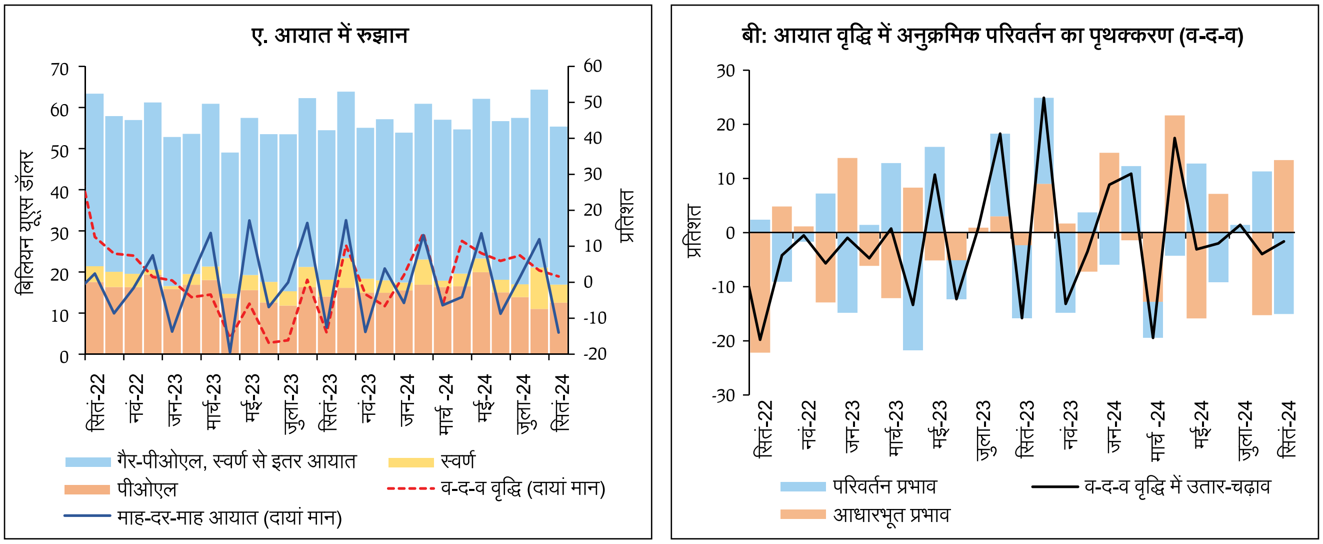

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पीओएल, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, वनस्पति तेल, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, आदि और रंगाई, टैनिंग तथा रंग सामग्री ने नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.11)। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान भारत का व्यापारिक आयात 6.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 350.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण पीओएल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातु और परिवहन उपकरण थे, जबकि मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिकेट, उर्वरक और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री का योगदान नकारात्मक रहा।

2024 के सितंबर में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 9 से आयात वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ा। 2024 के अप्रैल-सितंबर के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 14 से आयात में वृद्धि हुई।

चार्ट III.11: भारत का पण्य आयात – सापेक्ष योगदान (सितंबर 2023 की तुलना में सितंबर 2024)

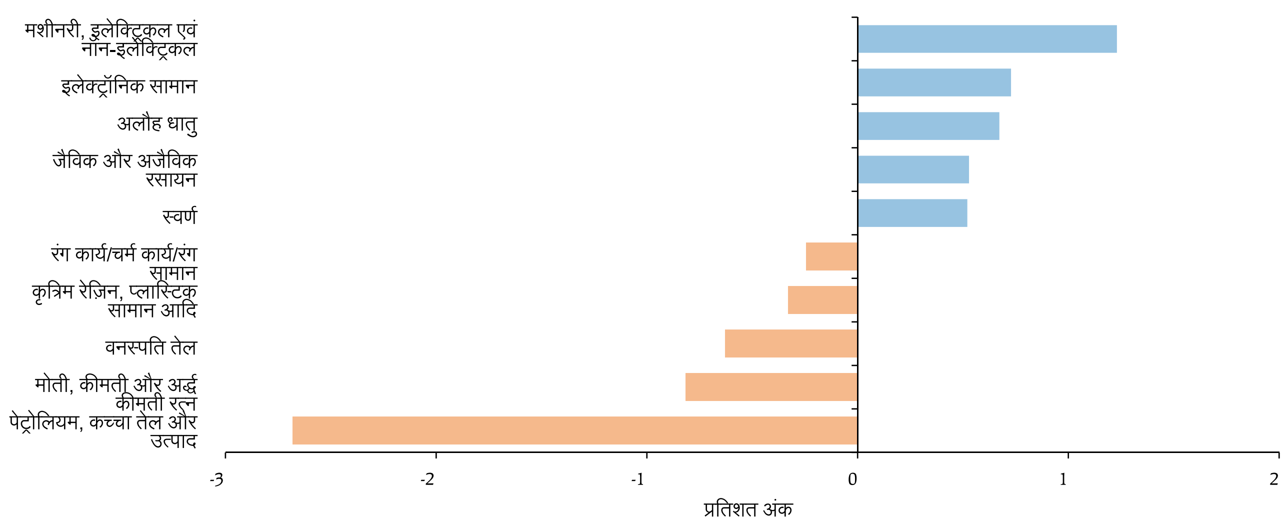

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.12: भारत के पण्य व्यापार घाटे का पृथक्करण

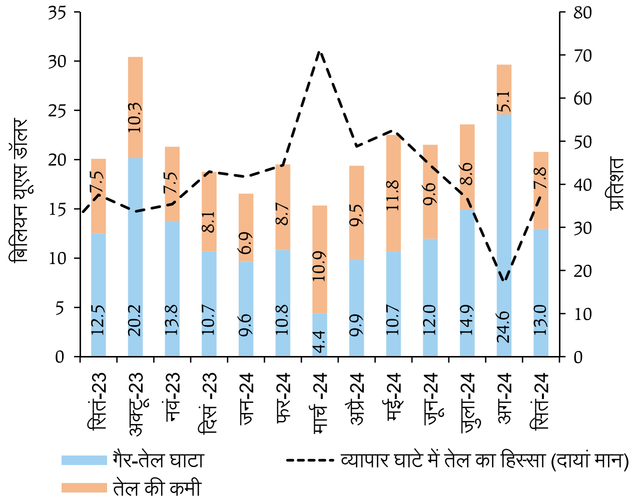

स्रोत: पीआईबी; और डीजीसीआई एंड एस

चार्ट III.13: पण्य-वार व्यापारिक घाटा

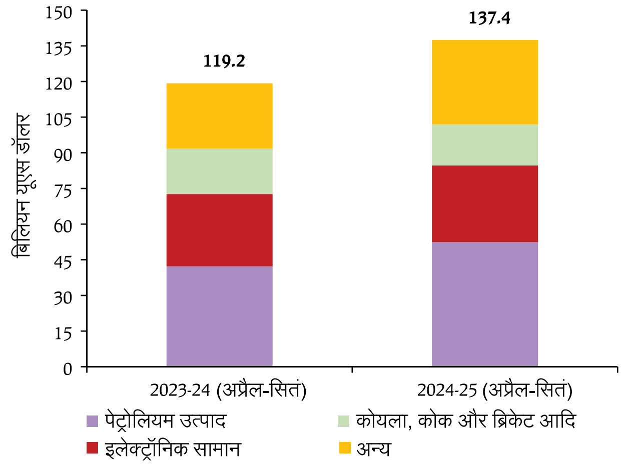

टिप्पणी: सितंबर 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट का निर्यात अगस्त 2024 के समान स्तर पर कल्पित है।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सितंबर 2024 में व्यापारिक व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर सिमट गया। कुल व्यापारिक व्यापार घाटे में पीओएल की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में एक साल पहले की तरह 37.6 प्रतिशत पर बनी रही (चार्ट III.12)।

अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा एक साल पहले के 119.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 137.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्रम था (चार्ट III.13)।

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग उत्पादन की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है[28], जो डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी), *बैसिलस कैलमेट-गुएरिन* (बीसीजी) और खसरे के टीकों की आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर आगे है। यह दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारत के निर्यात समूह में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स छठी सबसे बड़ी वस्तुएँ हैं, जिनकी 2023-24 में हिस्सेदारी 6.4 प्रतिशत रही। ड्रग फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल्स ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात के सबसे बड़े चालक रहे जिनकी हिस्सेदारी तीन-चौथाई से अधिक है, इसके बाद थोक ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स का क्रम है (चार्ट III.14ए)। 2023-24 में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 9.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2024-25 में अब तक (अगस्त तक), वे 8.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए हैं। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) अर्जित किया, जो मुख्य रूप से ड्रग फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल्स द्वारा संचालित रहा (चार्ट III.14बी)।

अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर भारत चीन के बाद पवन टरबाइन घटकों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी विनिर्माण क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात पर केंद्रित है (चार्ट III.15)। कम आयात निर्भरता लगभग 70-80 प्रतिशत स्वदेशीकरण को दर्शाती है जिसे मजबूत घरेलू विनिर्माण क्षमता द्वारा हासिल किया गया है (सारणी III.1)।

सारणी III.1: प्रमुख विंड टर्बाइन घटकों की विनिर्माण क्षमता

घटक	वैश्विक क्षमता 2023, गीगा वॉट में (जीडब्ल्यू)	भारत की क्षमता (वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी, प्रतिशत में)
गियरबॉक्स	166.5	15.5 (9)
जनरेटर	155.6	8.25 (5)
ब्लेड	156.8	12.92 (8)
पॉवर कन्वर्टर	222.7	10.6 (5)
टॉवर	38	2.8 (7)

स्रोत: सीईईडब्ल्यू

[28] वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट III.14 ड्रग और फार्मास्यूटिकल में भारत का निर्यात

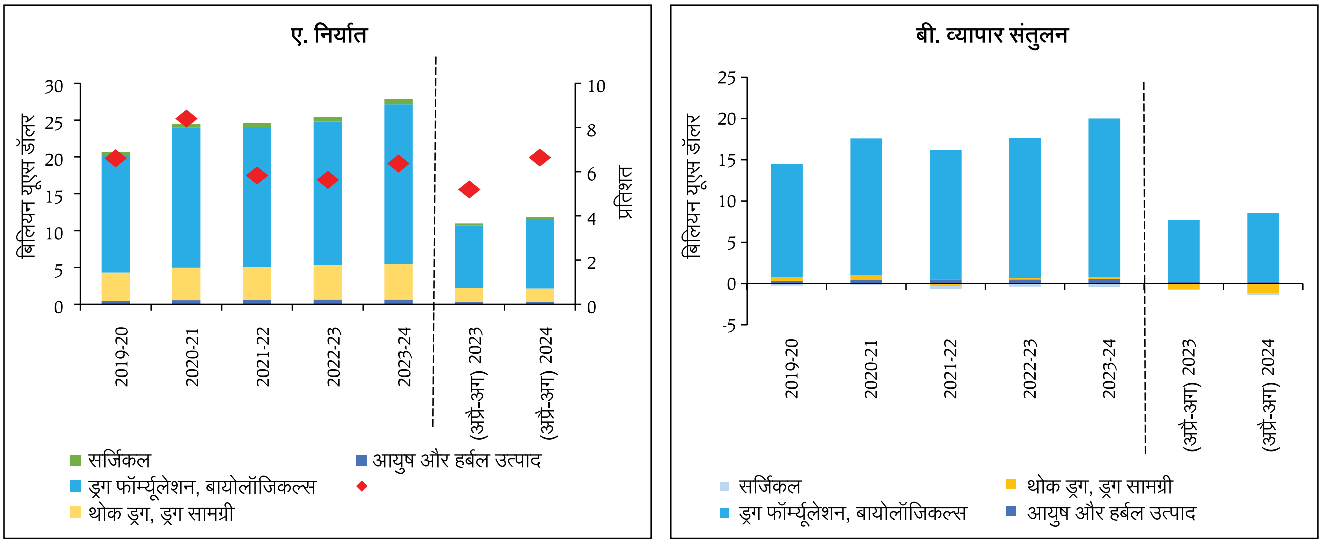

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत दुनिया में लिथियम-आयन बैटरी का एक प्रमुख आयातक है (चार्ट III.16)। भारत में एक परिपक्व लेकिन छोटा लिथियम-आयन बैटरी असेंबली क्षेत्र है, जिसमें 6.5 गीगावाट-घंटे (GWh) से अधिक विनिर्माण क्षमता है। सरकार ने ₹18500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी के निर्माण के लिए उत्पादन सह प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है जिससे आयात पर इसकी निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

अगस्त 2024 में सेवाओं का निर्यात 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और सेवाओं का आयात 8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.17)। परिणामस्वरूप महीने के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 2.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

चार्ट III.15 विंड जनरेटर

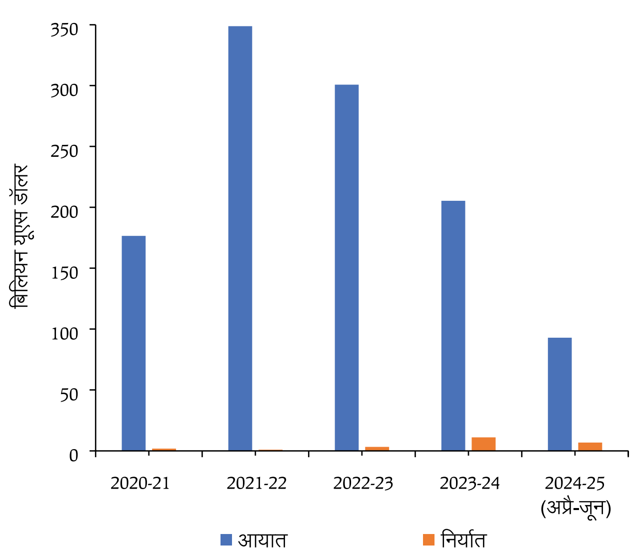

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चार्ट III.16 लिथियम-आयन बैटरी

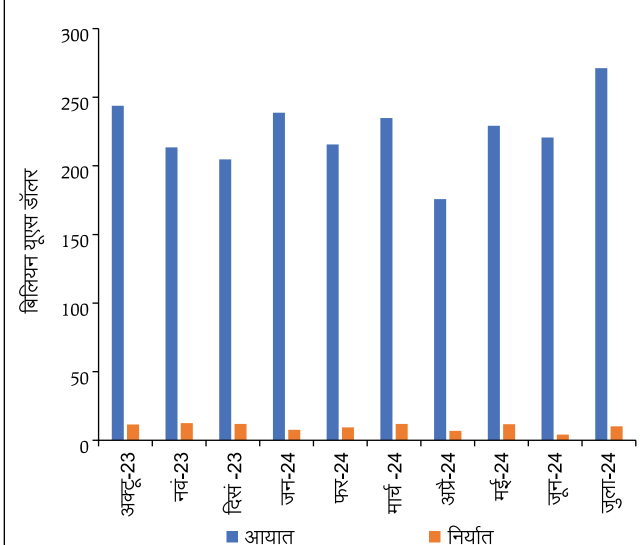

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चार्ट III.17: सेवाओं का निर्यात और आयात : वृद्धि दरें

स्रोत: आरबीआई।

केंद्र सरकार के सभी प्रमुख घाटा संकेतकों, अर्थात सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी), और प्राथमिक घाटा (पीडी) में अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सुधार दर्ज किया गया [पूर्ण रूप से और साथ ही बजट अनुमानों (बीई) के अनुपात में]। अप्रैल-अगस्त 2024 में जीएफडी बजट अनुमान का 27 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 36 प्रतिशत था (चार्ट III.18ए और III.18बी)। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ केंद्र सरकार के कुल व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.2 प्रतिशत की कमी के कारण केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।

चार्ट III.18: बजट घाटा (अप्रैल-अगस्त 2024)

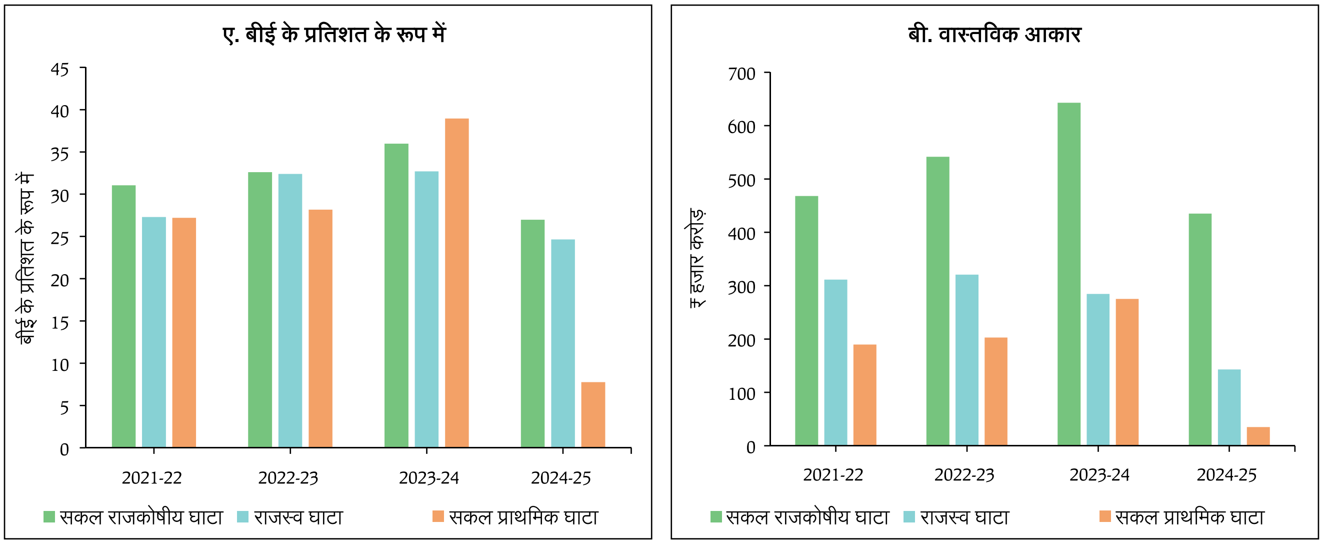

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़

अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान राजस्व व्यय में 4.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2023 में इसमें 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रमुख सब्सिडी व्यय में 1.2 प्रतिशत की मामूली कमी आई जिसका आंशिक कारण उर्वरक की अंतरराष्ट्रीय कीमत में गिरावट है। इसी तरह पूंजीगत व्यय वृद्धि में भी कमी दर्ज की गई, जिसका आंशिक कारण 2024-25 की पहली तिमाही में होने वाले आम चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता है। लेकिन, जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय में 25.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ उछाल आया। इसके अलावा सितंबर 2024 में सरकार ने व्यय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों में ढील दी।[29]

प्राप्तियों के मामले में सकल कर राजस्व में अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, आयकर संग्रह में 25.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि दर दर्ज की गई [चार्ट III.19ए]। हालांकि, इस अवधि के दौरान कारपोरेट करों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सितंबर के मध्य तक इसमें काफी सुधार हुआ।[30] अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, जीएसटी संग्रह में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा 2.1 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के साथ, गैर-कर राजस्व में अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान 59.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.19बी)। हालांकि, विनिवेश प्राप्तियां बजट लक्ष्य से पीछे रहीं, जिससे संबंधित अवधि के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 42.4 प्रतिशत की कमी आई। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों में अप्रैल-अगस्त 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर की तुलना में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सितंबर महीने का सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.73 लाख करोड़ रहा, जो व-द-व आधार पर 6.5 प्रतिशत

चार्ट III.19: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-अगस्त 2024)

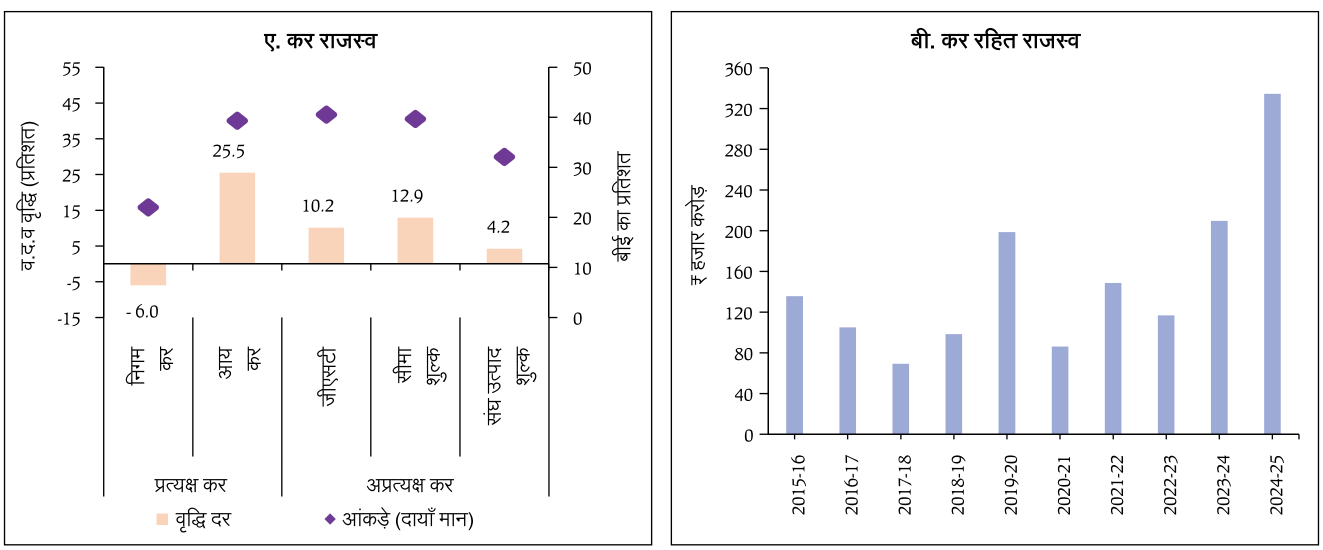

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़

[29] आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा 4 सितंबर 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बजट को निष्पादित करने हेतु परिचालनिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अगली सूचना तक बड़ी रिलीज (₹500 करोड़ या अधिक) से संबंधित शर्तों में रियायत दी जाएगी। नई प्रदान की गई रियायतें एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)/केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) और मासिक व्यय योजना (एमईपी)/तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी) के अनुपालन दिशानिर्देशों के अधीन रहेंगी।

[30] 17 सितंबर 2024 तक अग्रिम कर संग्रह के आंकड़ों के अनुसार, कॉरपोरेट कर संग्रह में 18.2 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि अप्रैल-अगस्त 2024 में गिरावट क्षतिपूर्ति से अधिक होने की संभावना है। (https://incometaxindia.gov.in/news/net-direct-tax-collection-provisional-as-on-17.09.2024-for-the-financial-year-2024-25.pdf)

चार्ट III.20: मासिक जीएसटी राजस्व

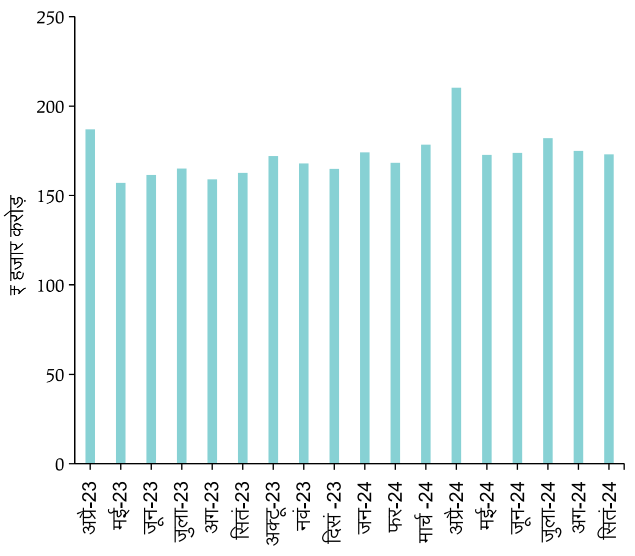

स्रोत: पीआईबी; और जीएसटी पोर्टल।

चार्ट III.21: बजट अनुमान में राज्यों की राजकोषीय स्थिति (अप्रैल-अगस्त)

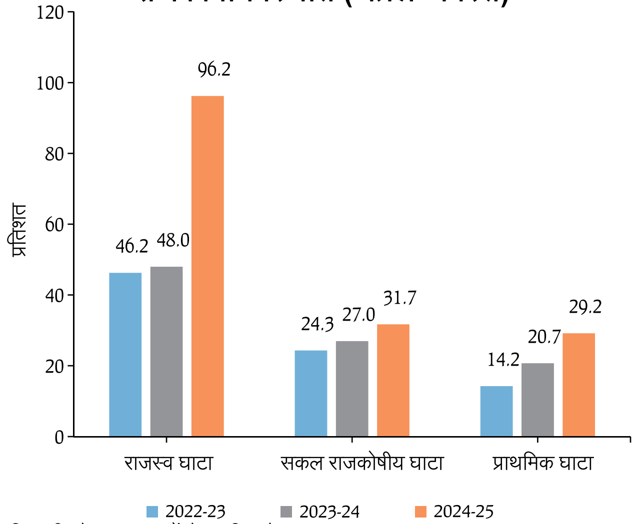

टिप्पणी: डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट III.20)। रिफंड को गणना में लेने के बाद निवल जीएसटी संग्रह ₹1.52 लाख करोड़ रहा, जो व-द-व आधार पर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, अप्रैल-सितंबर 2024 के लिए संचयी सकल जीएसटी संग्रह ₹10.9 लाख करोड़ रहा, जो अप्रैल-सितंबर 2023 की तुलना में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-अगस्त 2024 के अनंतिम आंकड़े बताते हैं कि राज्यों का जीएफडी पिछले वर्ष के 27 प्रतिशत से बढ़कर बीई का 31.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.21)। कर राजस्व वृद्धि में गिरावट और संघ सरकार से गैर-कर राजस्व और अनुदानों में संकुचन के कारण राजस्व प्राप्ति की वृद्धि धीमी हो गई (सारणी III.2)। राज्यों के वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), जो कर राजस्व का सबसे बड़ा कारक है, में वृद्धि कम हुई। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि बिक्री कर संग्रह में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सुधार के संकेत दिखाई दिए।

सारणी III.2: राज्यों के मुख्य राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-अगस्त 2024-25)

(प्रतिशत)

	बीई का प्रतिशत			व.द.व वृद्धि दर		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1. राजस्व प्राप्तियां	33.6	32.8	32.0	28.1	8.8	5.0
1.1. कर राजस्व	37.1	35.9	35.4	33.0	15.7	11.4
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	40.3	36.6	38.0	43.6	15.8	16.2
जीएसटी	43.6	43.9	43.3	31.7	19.0	10.3
बिक्री कर	40.1	34.4	35.2	20.1	-2.1	4.2
राज्य उत्पाद शुल्क	37.3	36.9	34.8	27.0	12.8	5.6
1.2. गैर-कर राजस्व	29.1	31.9	26.2	53.6	16.1	-9.9
1.3. अनुदान सहायता	24.1	20.2	15.7	10.2	-27.0	-33.5
2. राजस्व व्यय	33.9	33.2	33.8	15.6	7.7	10.4
2.1 ब्याज भुगतान	32.3	31.8	33.7	11.1	8.8	14.3
3. पूंजीगत व्यय	20.5	23.4	21.3	6.3	35.0	-4.9
3.1 पूंजीगत परिव्यय	19.6	23.8	20.3	4.4	42.3	-9.4

टिप्पणी: डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

व्यय पक्ष को देखें तो राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में गिरावट आई। आगे की ओर देखें तो केंद्र सरकार द्वारा ₹1.5 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण की विशेष सहायता के प्रावधान के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

सकल आपूर्ति

2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान रिकॉर्ड 332.3 मिलियन टन रहा, जो 2022-23 के अंतिम अनुमानों से 0.8 प्रतिशत अधिक था। उल्लेखनीय है कि 2023 सामान्य से कम मानसून वाला अल नीनो वर्ष था। गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि ने दालों और मोटे अनाज के उत्पादन में गिरावट की भरपाई की (चार्ट III.22)।

2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार बागवानी फसल उत्पादन 353.2 मिलियन टन तक कम हो गया, जो 2002-03 के बाद पहली बार हुआ। यह कमी प्याज और आलू के उत्पादन में क्रमशः 19.7 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत की गिरावट के कारण आई (चार्ट III.23)। वर्ष 2023-24 के दौरान वर्षा की कमी और अल नीनो मौसम की स्थिति से संबंधित उष्ण लहरों ने बागवानी फसल उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

2024 का दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) सामान्य से अधिक वर्षा के साथ समाप्त हुआ, जो दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) का 108 प्रतिशत था, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक है। यह 2024 के एसडब्ल्यूएम (जून-सितंबर) के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुरूप था। उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा क्रमशः एलपीए से 7 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 14 प्रतिशत अधिक थी, लेकिन पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में यह एलपीए से 14 प्रतिशत कम थी। 36 उपखंडों में से 33 में इस वर्ष सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जो पिछले वर्ष के 29 उपखंडों से अधिक है (चार्ट III.24)।

उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) एलपीए का 107 प्रतिशत रहा और यह चावल को छोड़कर अन्य प्रमुख फसलों के लिए सामान्य से अधिक रहा, जिसके लिए यह सामान्य था (चार्ट III.25)। यह उल्लेखनीय है कि इस मौसम के दौरान सभी प्रमुख फसलों के लिए पीआरएन उनके संबंधित पांच साल के औसत से अधिक रहे (चार्ट III.26)।

मानसून के मौसम के शुरुआती दौर में देखी गई वर्षा का उच्च स्थानिक फैलाव जुलाई के मध्य से कम हो गया क्योंकि वर्षा गतिविधि में व्यापकता आ गई (चार्ट III.27)।

चार्ट III.22: कृषि फसल उत्पादन 2023-24 (अंतिम अनुमान)

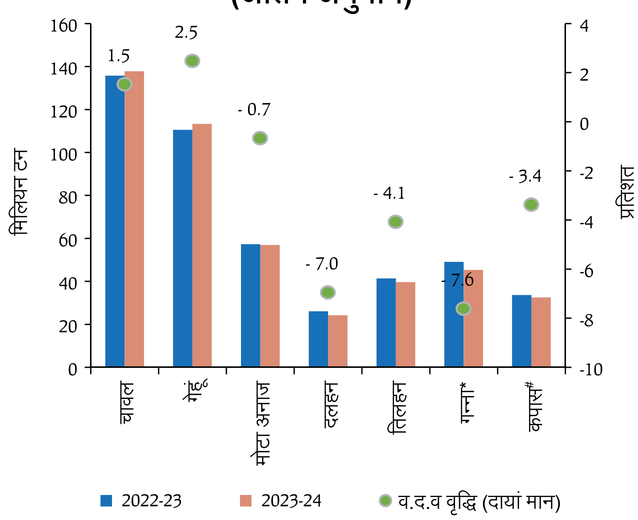

टिप्पणी: #:-170 किलो वाली मिलियन गांठें और *:- गन्ना 10 मिलियन टन में हैं।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

चार्ट III.23: बागवानी फसल उत्पादन 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान)

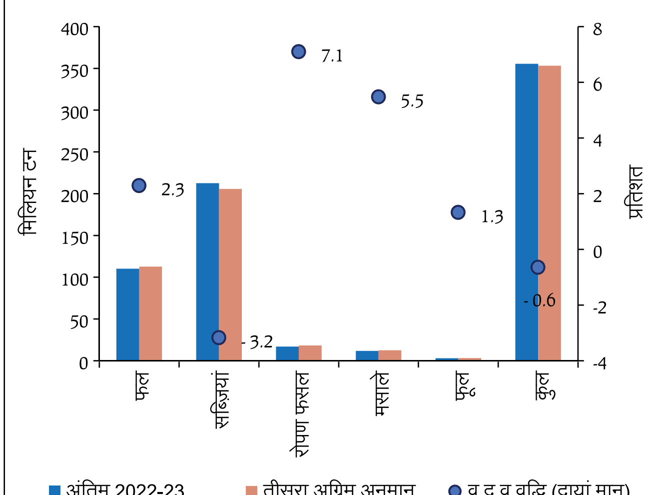

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

चार्ट III.24: एसडब्ल्यूएम मौसम की वर्षा – 36 मेट उप प्रभाग (1 जून – 30 सितंबर)

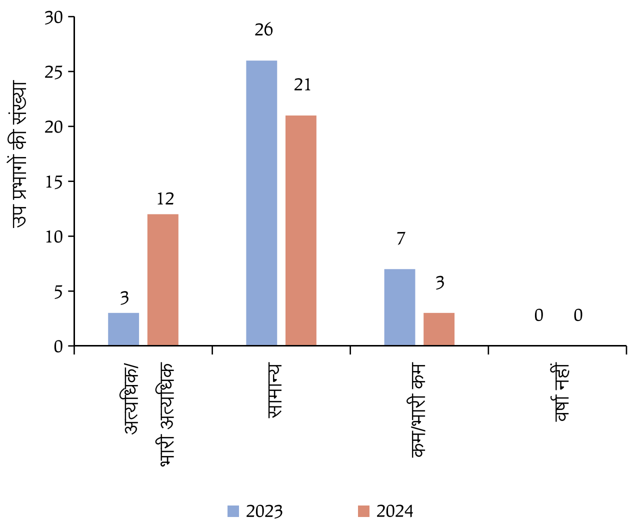

स्रोत: आईएमडी

चार्ट III.25: एसडब्ल्यूएम की सप्ताहवार स्थिति

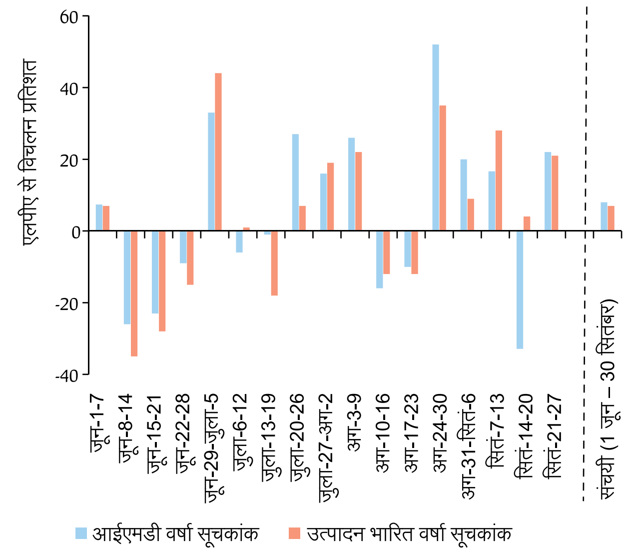

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

17 अक्टूबर 2024 को जलाशयों में जल स्तर कुल क्षमता के 87 प्रतिशत पर था, जो पिछले वर्ष और दशक के औसत से क्रमशः 19.9 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत अधिक था (चार्ट III.28)

27 सितंबर 2024 तक बोया गया कुल *खरीफ* क्षेत्र 1108.6 लाख हेक्टेयर (पूरे सीजन के सामान्य क्षेत्र का 101.1 प्रतिशत) था, जो पिछले वर्ष और सामान्य क्षेत्र की तुलना में अधिक था (चार्ट III.29)। कपास को छोड़कर सभी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

रबी के विपणन मौसम (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 2.4 प्रतिशत (कुसुंभ के लिए) से 7.0 प्रतिशत (जौ के लिए) की सीमा में वृद्धि की गई [चार्ट III.30]। रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में ₹300

चार्ट III.26: फसलवार पीआरएएन

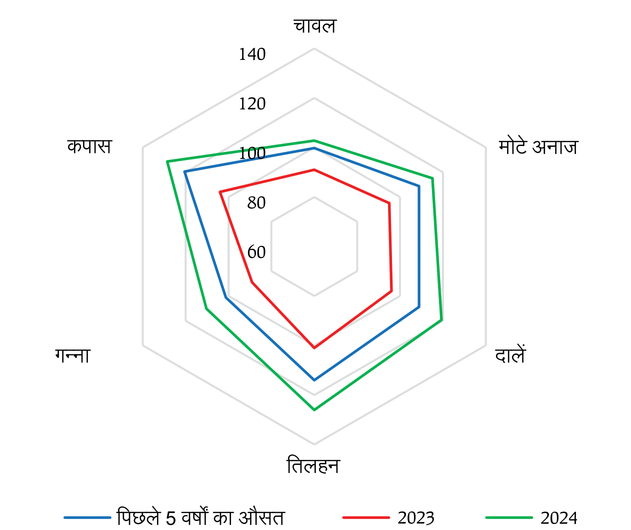

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.27: एसडब्ल्यूएम वर्षा का स्थानलक्षी मानक विचलन

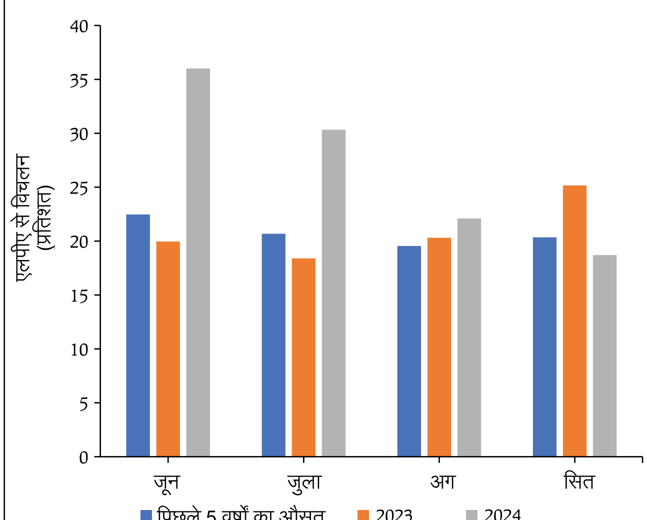

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.28: जलाशय स्तर (17 अक्टूबर की स्थिति)

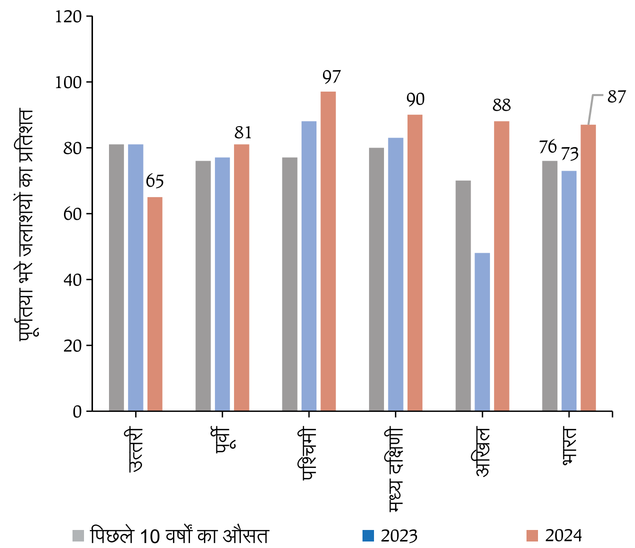

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

चार्ट III.29: *खरीफ* बुवाई क्षेत्र 2024-25 (27 सितंबर 2024 की स्थिति)

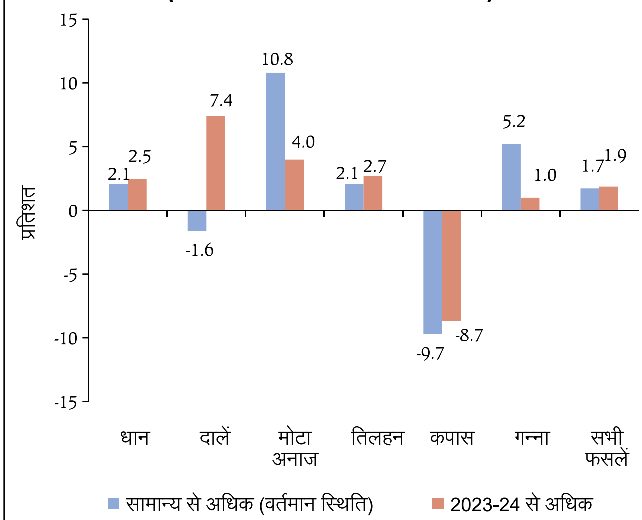

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रति क्विंटल और मसूर के लिए भी ₹275 प्रति क्विंटल की उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गई है। यह तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नीतियों के तहत है।

मॉनसूनोत्तर मौसम (अक्टूबर-दिसंबर) संबंधी आईएमडी के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश सामान्य से अधिक (एलपीए का 112 प्रतिशत से अधिक) होने

चार्ट III.30: *रबी* फसलों की एमएसपी में परिवर्तन

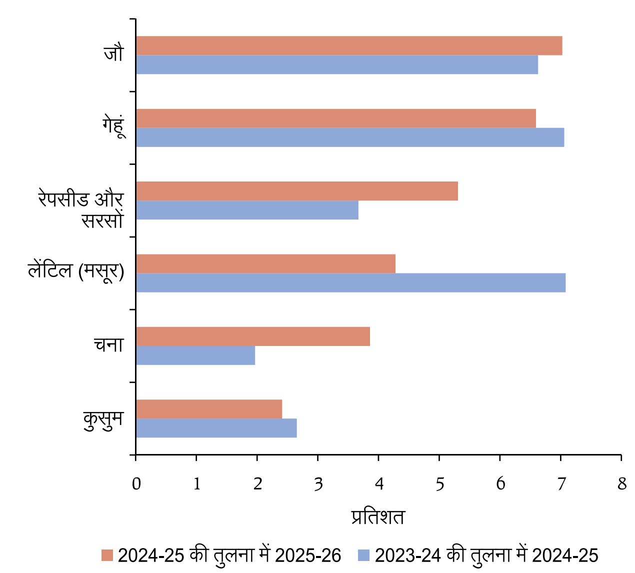

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

की संभावना है[31]। अब तक चालू पूर्वोत्तर मॉनसून (एनईएम) सीजन (01-18 अक्टूबर) के दौरान संचयी वर्षा एलपीए से 1 प्रतिशत कम रही है। पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि मॉनसूनोत्तर मौसम के दौरान ला नीना की स्थिति निर्माण होने की संभावना बढ़ गई है, जो *रबी* की बुवाई के लिए अच्छा संकेत है (चार्ट III.31)।

01 अक्टूबर 2024 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चावल का स्टॉक 387 लाख टन था, जो पिछले साल की इसी तारीख से 23.0 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने *खरीफ* विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 में 525.4 लाख टन चावल की खरीद की जो पिछले वर्ष के सीजन से 7.7 प्रतिशत कम थी। चावल के प्रचुर स्टॉक और खुदरा कीमतों में नरमी को देखते हुए सरकार ने 28 सितंबर 2024 को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात नीति में संशोधन कर इसे प्रतिबंधित स्थिति से मुक्त स्थिति कर दिया है, बशर्ते न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो। गेहूं के मामले में सरकार ने *रबी* विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 में 266 लाख टन की खरीद की जो पिछले सीजन से 1.6 फीसदी ज्यादा है। 238

[31] दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पांच मौसम संबंधी उपखंड (तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और माहे, तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक) शामिल हैं। आईएमडी 1998 से दक्षिण प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वोत्तर मानसून (मानसून के बाद) मौसम की वर्षा के लिए पूर्वानुमान तैयार कर रहा है क्योंकि इस मौसम के दौरान इस क्षेत्र में अधिक वार्षिक वर्षा होती है।

चार्ट III.31: उत्तर-पूर्वी मानसून अनुमान (अक्टूबर – दिसंबर 2024)

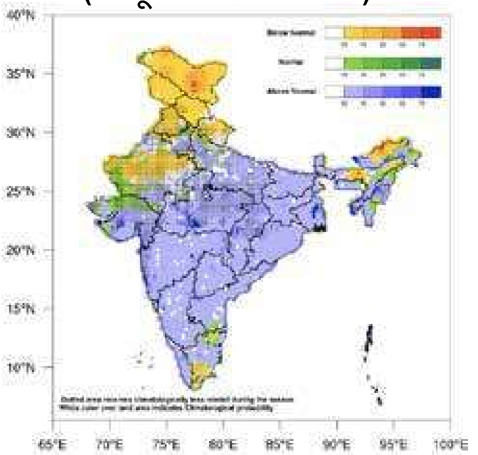

टिप्पण: चार्ट अक्टूबर से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान भारत में वर्षा की तीन श्रेणियों (सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक) के संभाव्यता पूर्वानुमान को दर्शाता है। यह आंकड़ा सबसे संभावित श्रेणियों के साथ-साथ उनकी संभावनाओं को भी दर्शाता है। तीन श्रेणियों में से प्रत्येक की जलवायु संबंधी संभावना 33.33 प्रतिशत है।
स्रोत: आईएमडी।

चार्ट III.32: केन्द्रीय जन वितरण प्रणाली

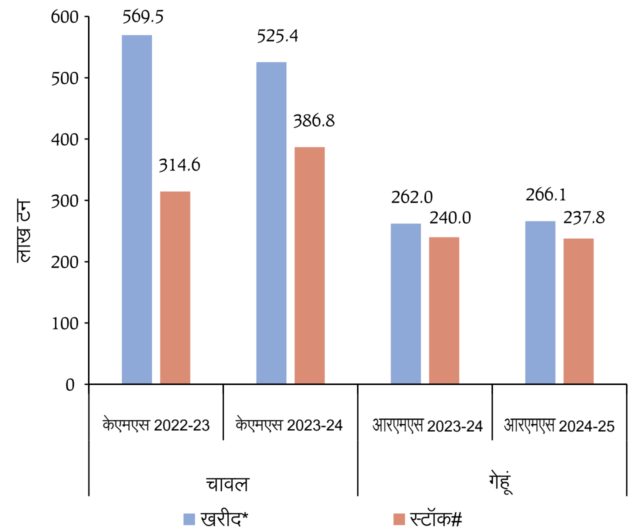

टिप्पण:- *30 सितंबर की स्थिति; #:- 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति।
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम।

लाख टन (01 अक्टूबर 2024 की स्थिति) गेहूं का स्टॉक पिछले साल से 0.9 फीसदी कम रहा। सरकार ने इसकी उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को कम किया। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए चावल और गेहूं के स्टॉक के लिए बफर मानदंड क्रमशः 102.5 लाख टन और 205.2 लाख टन था (चार्ट III.32)।

नए मांग-आदेश, रोजगार और उत्पादन में विस्तार की गति में कमी के कारण सितंबर में भारत के विनिर्माण पीएमआई में कमी आई (चार्ट III.33ए)। नई व्यावसायिक गतिविधि में मंदी के कारण सितंबर में सेवा क्षेत्र के पीएमआई में भी कमी आई और यह दस महीने के निचले स्तर पर आ गया (चार्ट III.33बी)। विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक उम्मीदों में नरमी के संकेत दिखे, जबकि सेवा क्षेत्र में सुधार दिखा।

चार्ट III.33: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

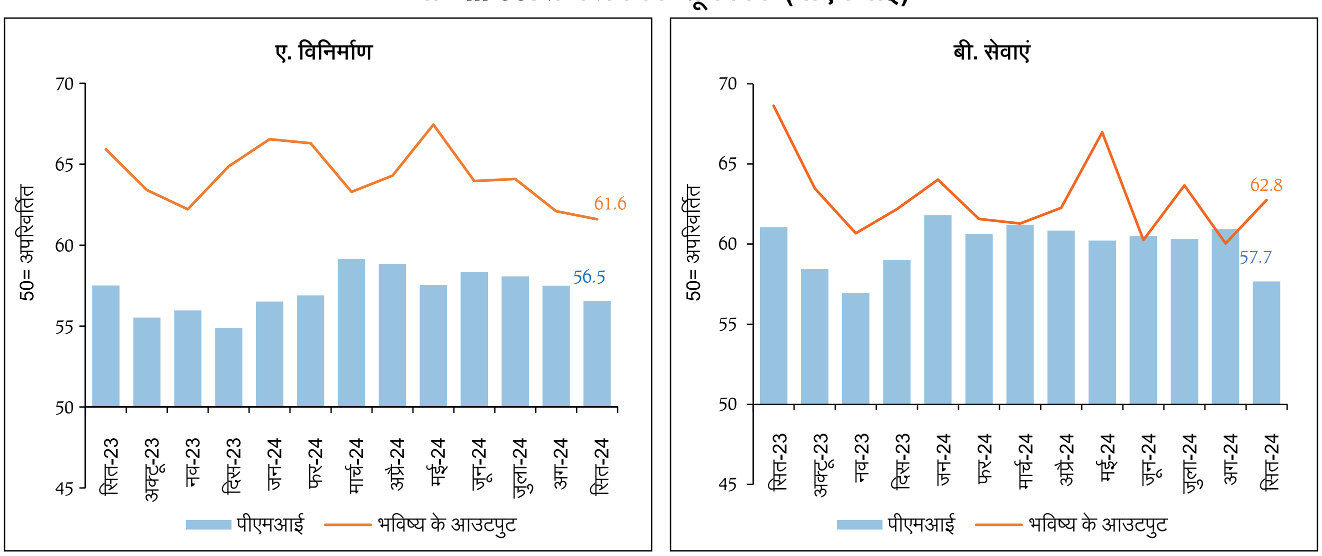

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में शून्य परिवर्तन को दर्शाता है और 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार को तथा नीचे का आंकड़ा उसकी विपरीत स्थिति को दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.34: घरेलू विनिर्माण क्षमता

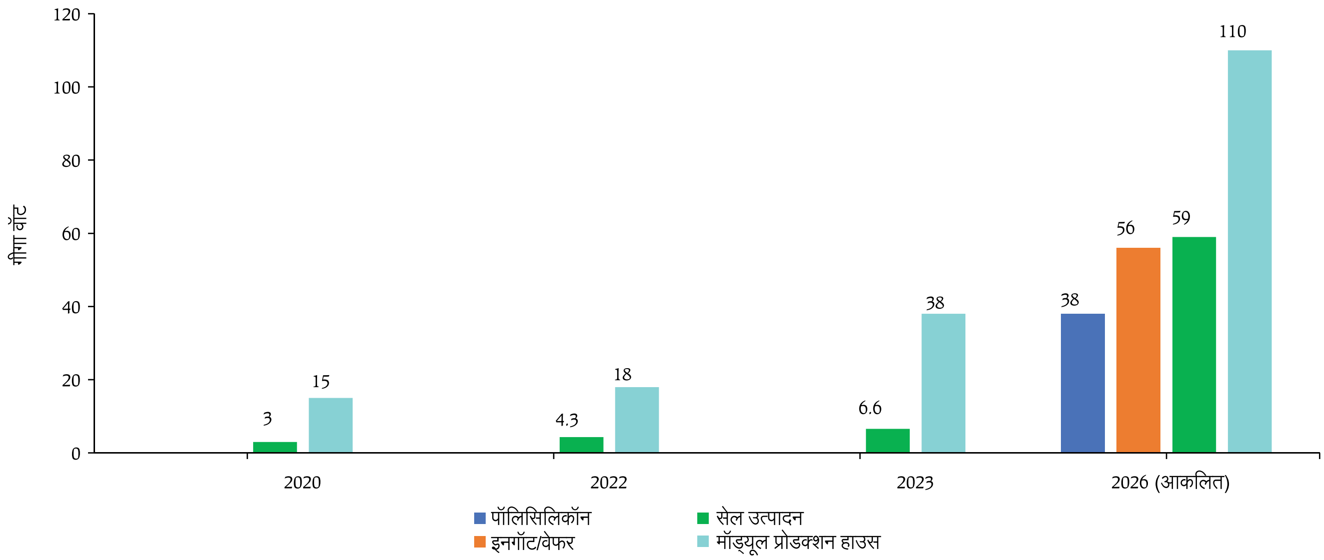

स्रोत: जेएमके रीसर्च।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 2023 में 6.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्वदेशी सौर सेल विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना[32] के तहत आवंटित विनिर्माण क्षमता के ऑनलाइन होने के बाद भारत में पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट वेफर्स, सेल और मॉड्यूल विनिर्माण में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमता विकसित होने की संभावना है (चार्ट III.34)।

सितंबर 2024 में बंदरगाह यातायात में 5.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें अन्य विविध कार्गो, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक प्रमुख रहे (चार्ट III.35ए)। दूसरी ओर कोयला और सीमेंट के बाद रेलवे माल यातायात ने अगस्त में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की (चार्ट III.35बी)।

चार्ट 35: पोर्ट कार्गो और रेलवे मालभाड़ा

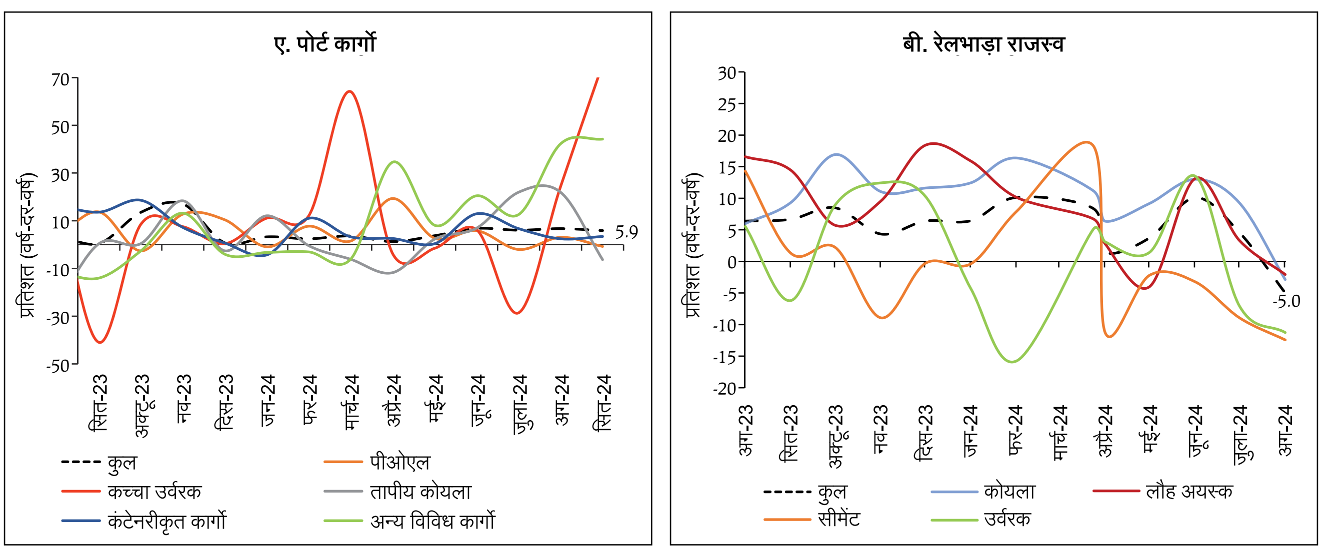

स्रोत: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन; रेल मंत्रालय; और सीएमआईई।

[32] सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत 18500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की कुल 48337 मेगावाट (मेगावाट) क्षमता आवंटित की है। इसमें पी + डब्ल्यू + सी + एम (पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल) बास्केट के तहत 15400 मेगावाट विनिर्माण क्षमता शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संपूर्ण विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला भारत में स्थापित की जा सकती है।

चार्ट III.36: इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन

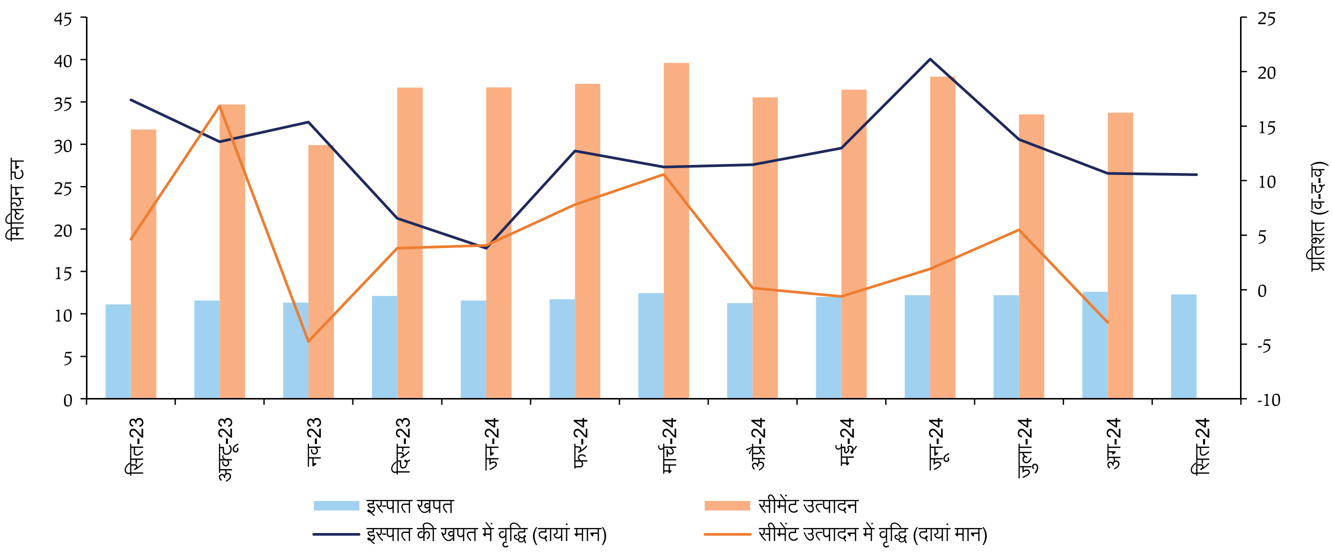

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

निर्माण क्षेत्र में, सितंबर में इस्पात की खपत में 10.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। हालांकि, सीमेंट उत्पादन में अगस्त 2024 में 3.0 प्रतिशत की गिरावट आयी (चार्ट III.36)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक सितंबर 2024 में गतिविधि की समुत्थानशीलता को दर्शाते हैं, जो ग्रामीण मांग, घरेलू हवाई यात्री यातायात और इस्पात खपत द्वारा समर्थित है (सारणी III.3)।

सारणी III.3: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सितं-24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.8	-0.4
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	6.7
	ट्रैक्टर की बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री		3.2			-3.8			3.5			-11.0	
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.6	-5.0	
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	6.0	6.7	5.9
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	10.6	9.0	8.7	10.0	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	-12.5
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	15.0	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	3.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	10.7	8.7	8.1	5.0	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.8
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	17.5	19.8	18.1	17.0	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	9.7
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर्राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7
	होटल अधिभोग दर @	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	62.3	60.3	62.0	63.1	61.3	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	
	पर्यटकों का आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0			
निर्माण	इस्पात खपत	13.6	15.4	6.5	3.8	12.7	11.2	11.5	13.0	21.1	13.8	10.7	10.5
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	-3.0	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7

<< संकुचन ------------------------------------- विस्तार >>

टिप्पणी: #: स्तरों में डेटा है। *: सितंबर 2024 डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। @: डेटा दर में है, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में नहीं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप बनाया गया है।

स्रोत: एसआईएएम; रेल मंत्रालय; सीएमआईई; ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय: संयुक्त संयंत्र समिति; तथा आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय सीपीआई[33] में वर्ष-दर-वर्ष होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, अगस्त 2024 के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत के नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (चार्ट III.37)। मुद्रास्फीति में 1.75 प्रतिशत अंकों की तीव्र वृद्धि 60 आधार अंकों की धनात्मक गति और 115 आधार अंकों के प्रतिकूल आधार प्रभाव से हुई। सभी सीपीआई उप-समूहों - खाद्य; ईंधन और प्रकाश; और मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) - ने धनात्मक गति दर्शायी तथा क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में वार्षिक आधार पर 8.4 प्रतिशत हो गई, जो धनात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण बढ़ी। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, फलों, दूध और उससे बने उत्पादों, गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि अनाज, मांस और मछली, अंडे, दालों और चीनी के दाम सामान्य हुए (चार्ट III.38)। लगातार 19 महीनों के बाद खाद्य तेलों और वसा की कीमतें अपस्फीति से बाहर आ गई, जबकि मसालों की कीमतों में अपस्फीति और अधिक हो गई।

ईंधन और प्रकाश के संबंध में अपस्फीति अगस्त के (-)5.3 प्रतिशत से सितंबर में काफी कम होकर (-)1.4 प्रतिशत हो गई, जिसका कारण बिजली, ईंधन की लकड़ी और चिप्स की कीमतों तथा एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति की कम दर थी, जो एक वर्ष पहले इन कीमतों में 16 प्रतिशत की कमी के प्रभाव के क्षय को दर्शाती है। दूसरी ओर, केरोसिन की कीमतों में पुनः अपस्फीति देखी गई।

मूल मुद्रास्फीति अगस्त के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 3.6 प्रतिशत पर स्थिर हो गई। आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, परिवहन और संचार, तथा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों के संबंध में मूल्य वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जबकि यह कपड़े और जूते, तथा स्वास्थ्य जैसे उप-समूहों के लिए स्थिर रही। हालाँकि, मनोरंजन और मन-बहलाव, शिक्षा और पान, तंबाकू और मादक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि में सामान्यता दर्ज की गई (चार्ट III.39)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, सितंबर में ग्रामीण और शहरी - दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत रही, जो 5.0 प्रतिशत की शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के करीब दर्ज की गई (चार्ट III.40)।

चार्ट III.37: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

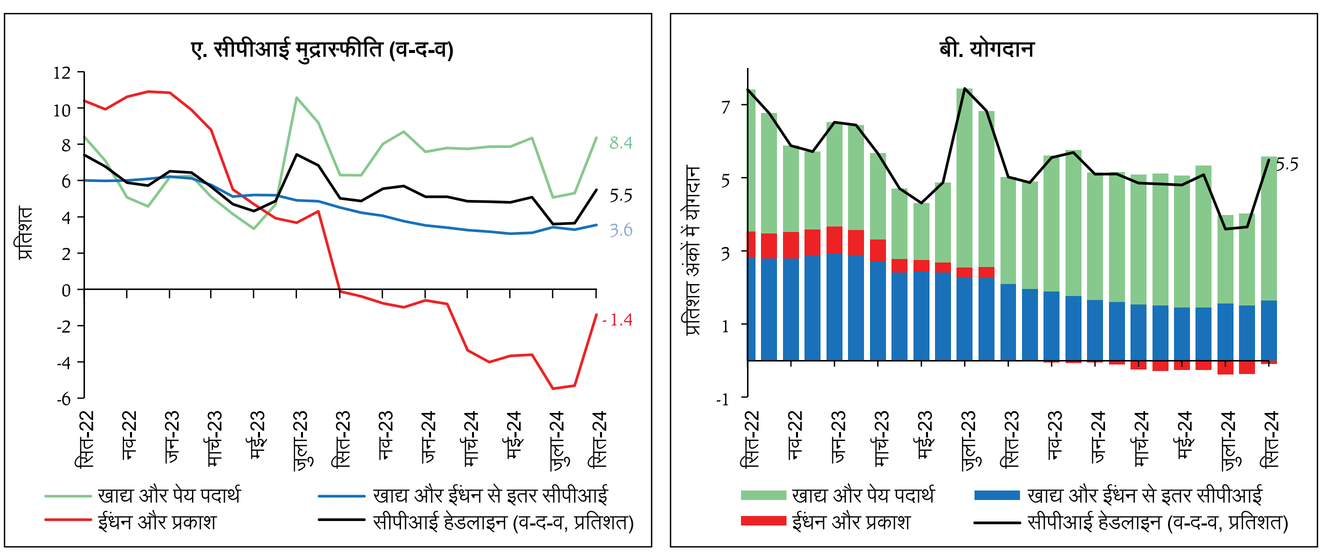

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[33] एनएसओ द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.38: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और गति (माह-दर-माह)

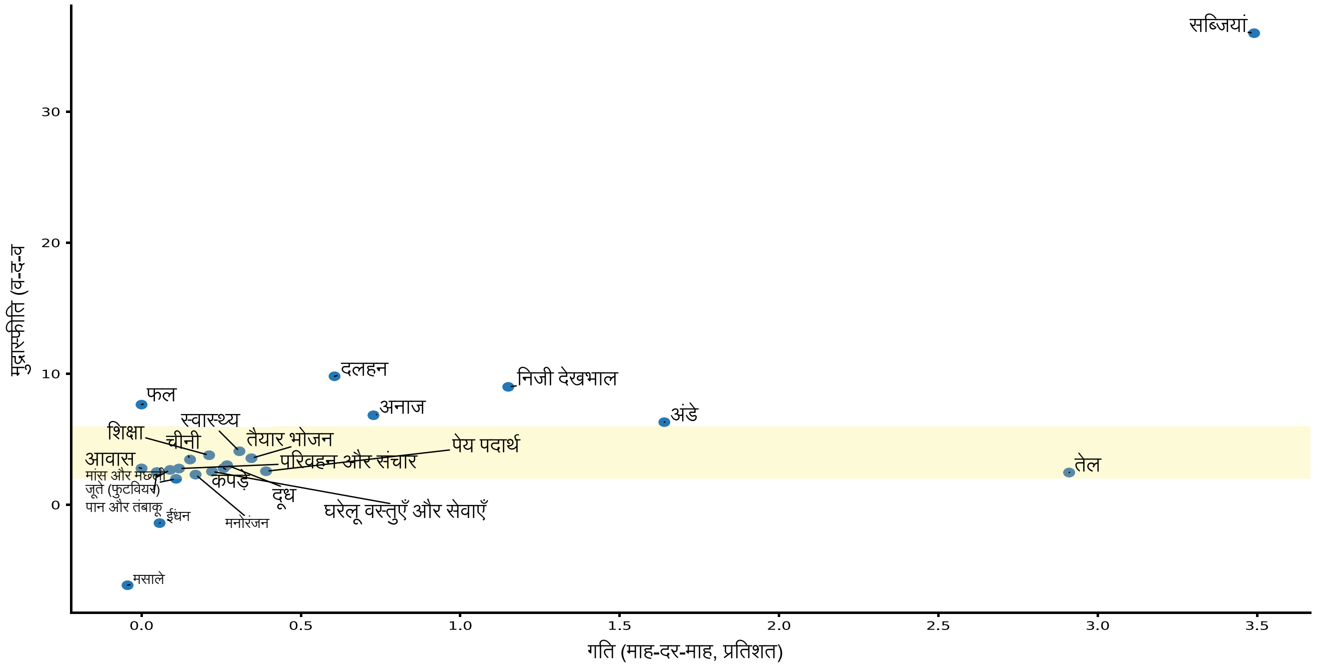

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अक्टूबर के लिए अब तक (17 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य संबंधी डेटा, अनाज (मुख्य रूप से चावल) और दालों (चना दाल को छोड़कर) की कीमतों में नरमी दर्शाते हैं। सितंबर 2024 में आयात शुल्क में 20 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी के बाद खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख सब्जियों में आलू की कीमतों में गिरावट आयी, जबकि प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.41)।

चार्ट III.39: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (अगस्त 2024 की *तुलना* में सितंबर 2024)

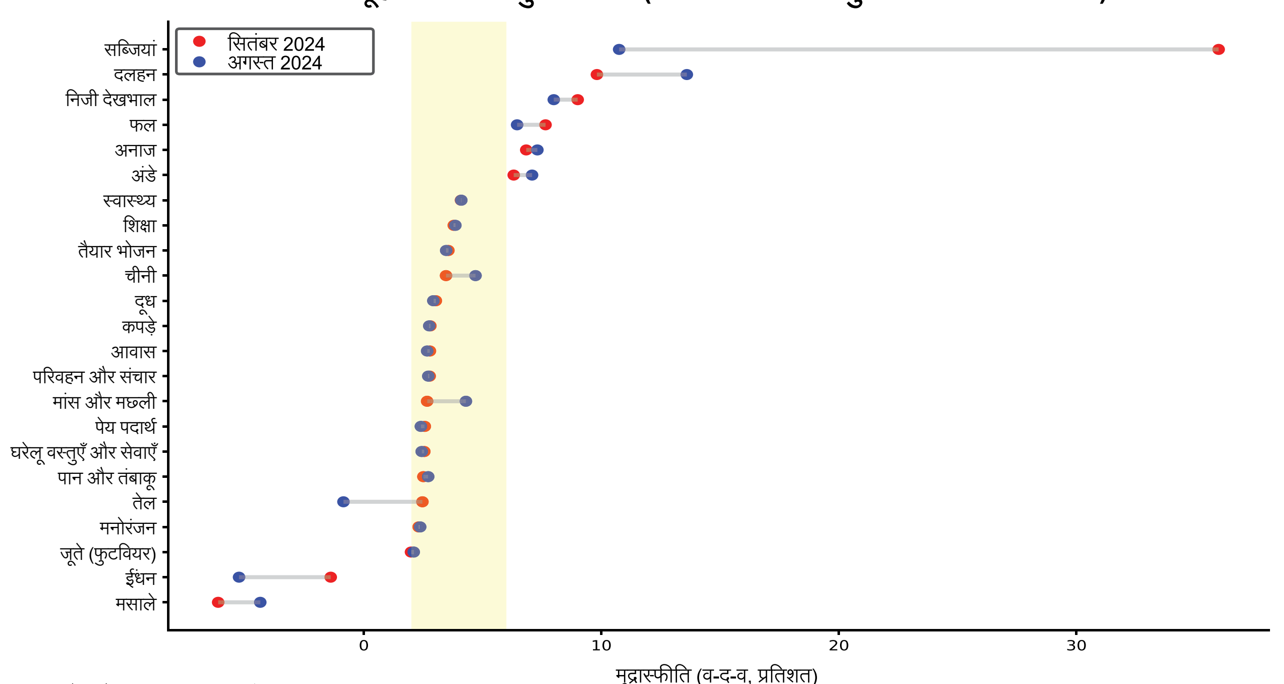

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.40: सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सरकार ने प्याज पर 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (3 मई 2024 को लागू) को समाप्त कर दिया और सितंबर में निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इन बदलावों से निर्यात मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे घरेलू कीमतों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, अनुकूल मानसून की स्थिति के कारण *खरीफ* मौसम के दौरान प्याज और टमाटर, दोनों फसलों का उत्पादन अधिक होने की उम्मीद है, जिससे कीमतों पर गिरावट का दबाव कम हो सकता है (चार्ट III.42)।

अक्टूबर में अब तक पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं (17 तारीख तक)। एलपीजी की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन की कीमतों में गिरावट जारी रही (सारणी III.4)।

सितंबर 2024 के लिए पीएमआई ने संकेत दिया कि अगस्त में गिरावट के बाद विनिर्माण और सेवा फर्मों, दोनों में इनपुट लागत के विस्तार की दर में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, विनिर्माण फर्मों में बिक्री कीमत दबाव चार महीनों के निम्नतम स्तर पर आ गया,

चार्ट III.41: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

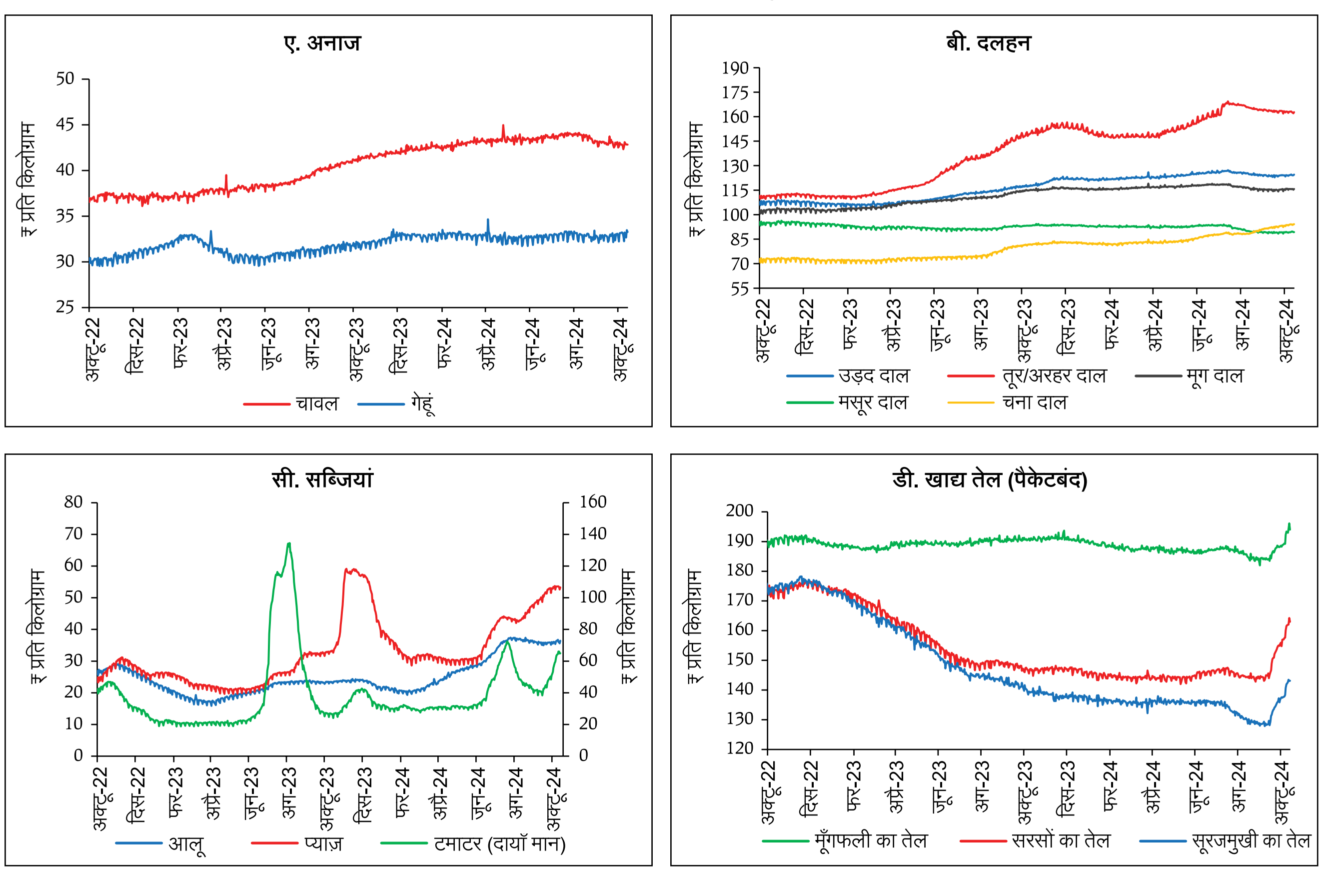

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.42: औसत मंडी कीमतें

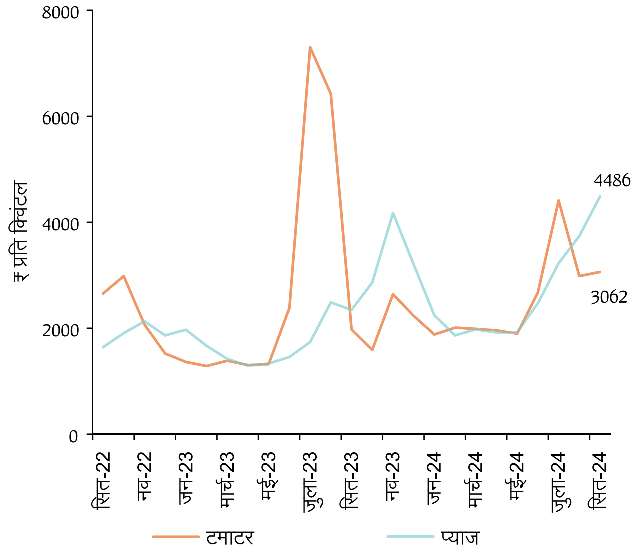

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम; तथा भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र।

सारणी III.4: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		अक्तू-23	सित-24	अक्तू-24	सितं-24	अक्तू-24^
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.97	100.97	0	0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.42	90.42	0	0
केरोसिन (छूट सहित)	₹/लीटर	57.95	45.78	42.93	-1.9	-6.2
एलपीजी (छूट रहित)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0	0

^: 1-17 अक्तूबर 2024 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि सेवा क्षेत्र ने पिछले 31 महीनों में बिक्री कीमतों में सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.43)।

आरबीआई के सर्वेक्षण के नवीनतम द्वि-मासिक चरण में, पारिवारिक इकाइयों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ 3 महीने और एक वर्ष के हॉरीज़ॉन के लिए क्रमशः 20 आधार अंक और 10 आधार अंक तक कम हो गईं। वर्तमान मुद्रास्फीति के बारे में उत्तरदाताओं की धारणा, सितंबर 2022 से मामूली वृद्धि के दो प्रसंगों को छोड़कर आम तौर पर घटती प्रवृत्ति पर रही है (चार्ट III.44)।

चार्ट III.43: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें

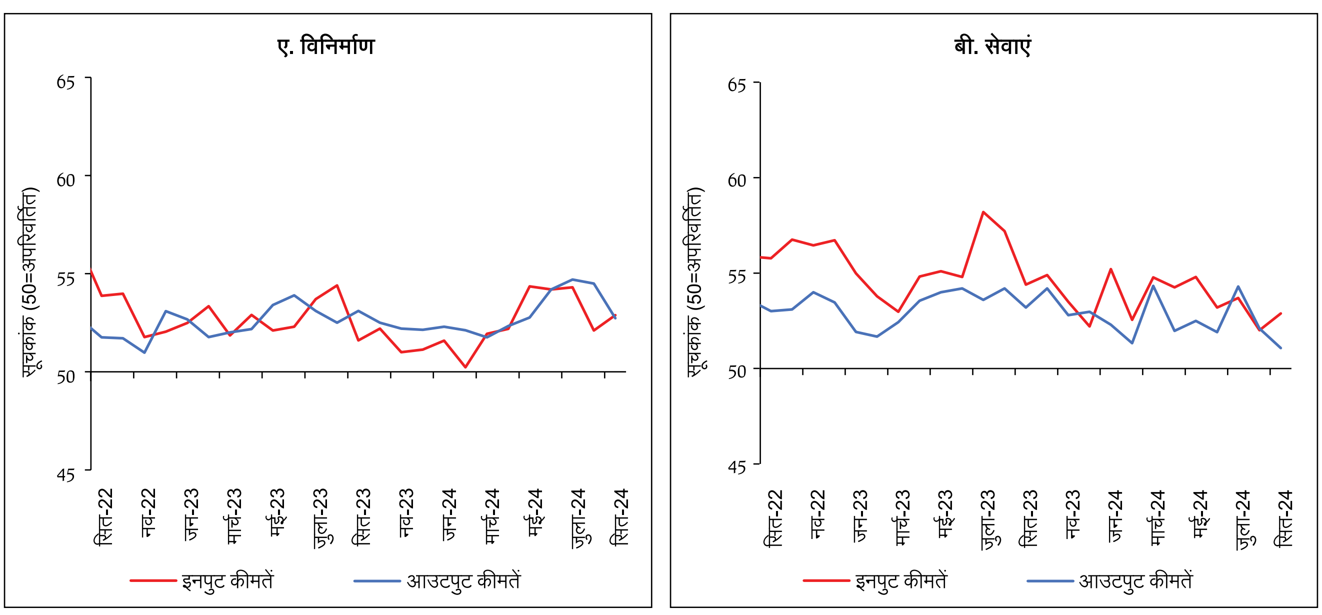

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसका विलोमतः होता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.44: पारिवारिक स्तर पर औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ

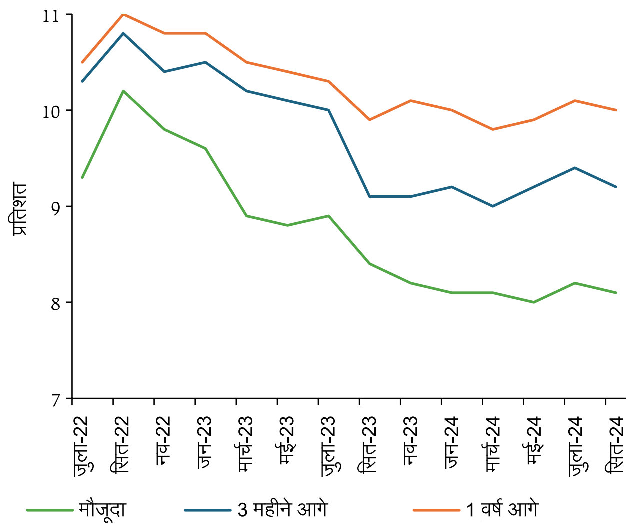

स्रोत: परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच), आरबीआई।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

अक्टूबर 2024 की द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5:1 के बहुमत से नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में एमपीसी ने स्पष्ट रूप से लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजन वापस लेने से अपना रुख बदलकर तटस्थ रुख अपनाया, और वृद्धि का समर्थन किया।

सरकारी व्यय में वृद्धि और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी के कारण, सितंबर-अक्टूबर के दौरान अब तक (17 अक्टूबर तक) प्रणालीगत चलनिधि अधिकतर अधिशेष में रही। हालाँकि, सितंबर के उत्तरार्ध (21-25 सितंबर) के दौरान अग्रिम कर भुगतान और जीएसटी से संबंधित बहिर्वाह के कारण चलनिधि घाटे की एक संक्षिप्त अवधि देखी गई। कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 के दौरान ₹1.2 लाख करोड़ था, जबकि 16 अगस्त और 15 सितंबर 2024 के दौरान यह ₹1.53 लाख करोड़ था (चार्ट IV.1)।

बदलती चलनिधि स्थितियों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने 17-24 सितंबर के दौरान एक मुख्य और तीन फाइन-ट्यूनिंग वेरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) परिचालन किए, जिससे पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संचयी रूप से ₹2.1 लाख करोड़ अंतर्वेशित किए गए। जैसे ही बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि वापस आयी, 30 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

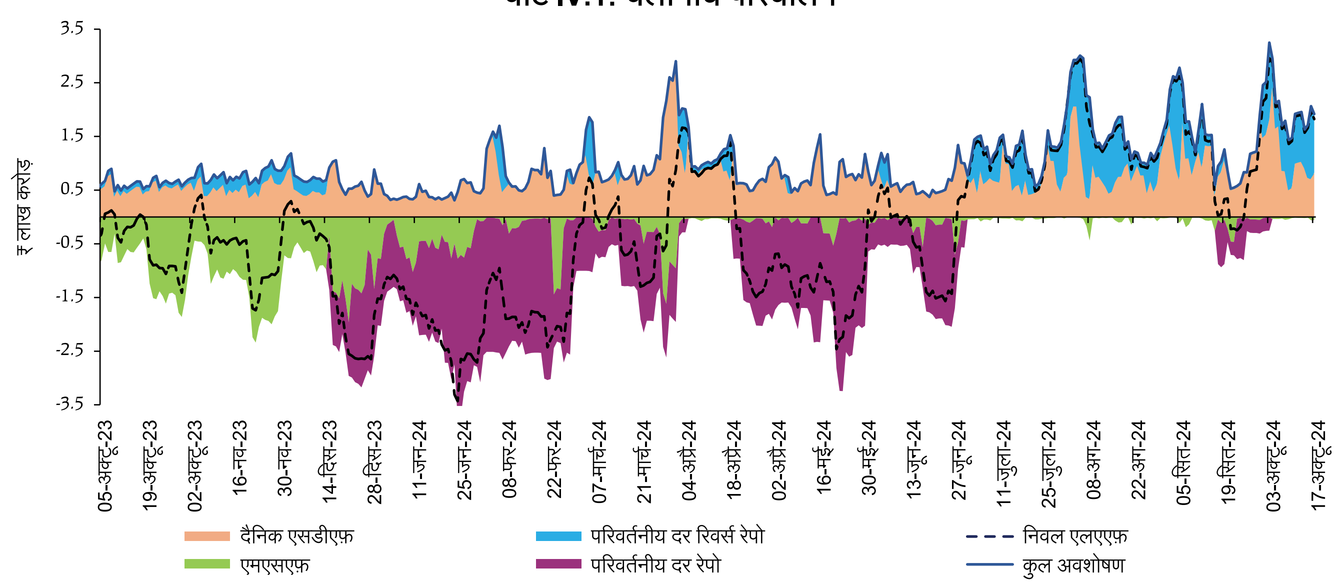

स्रोत : आरबीआई।

के दौरान ₹4.1 लाख करोड़ की अधिशेष चलनिधि को इकट्ठा करने के लिए एक मुख्य और छह फाइन-ट्यूनिंग वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियां आयोजित की गईं। मुख्य परिचालन में कम ऑफर-कवर अनुपात से स्पष्ट है कि बैंक दीर्घावधि के लिए चलनिधि छोड़ने में अनिच्छा दिखा रहे हैं। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 के दौरान ₹1.54 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का प्लेसमेंट 68 प्रतिशत था। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत औसत दैनिक उधार 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 के दौरान ₹0.08 लाख करोड़ हो गया, जो 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 के दौरान ₹0.05 लाख करोड़ था।

भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान 6.50 प्रतिशत रही, जबकि 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 के दौरान यह 6.52 प्रतिशत थी (चार्ट IV.2ए)। हालांकि, डब्ल्यूएसीआर में वृद्धि हुई और इसने पूर्व में चर्चा किए गए कारणों से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमी के कारण संक्षिप्त अवधि (21-25 सितंबर) के लिए नीति रेपो दर से ऊपर ट्रेड किया। डब्ल्यूएसीआर में 30 सितंबर को 15 आधार अंकों की तेजी आयी, जो छमाही अंत की सामान्य तंगी के कारण हुई, जो (i) बैंकों द्वारा गैर-संपार्श्विक बाजार में अपने एक्सपोजर को कम करने से आयी, जिससे पूंजी पर्याप्तता के लिए प्रावधान करने की उनकी आवश्यकताएं कम हो गईं; और (ii) म्यूचुअल फंड (एमएफ) ने मोचन दबावों के कारण त्रि-पक्षीय रेपो खंड में अपनी उधारियाँ कम कर दीं। संपार्श्विक खंड में, त्रिपक्षीय रेपो दर डब्ल्यूएसीआर के अनुरूप रही, जो इसी अवधि के दौरान नीतिगत रेपो दर से औसतन 11 आधार अंक कम थी (चार्ट IV.2बी)।

चार्ट IV.2: नीतिगत कॉरीडोर और मुद्रा बाजार दरें

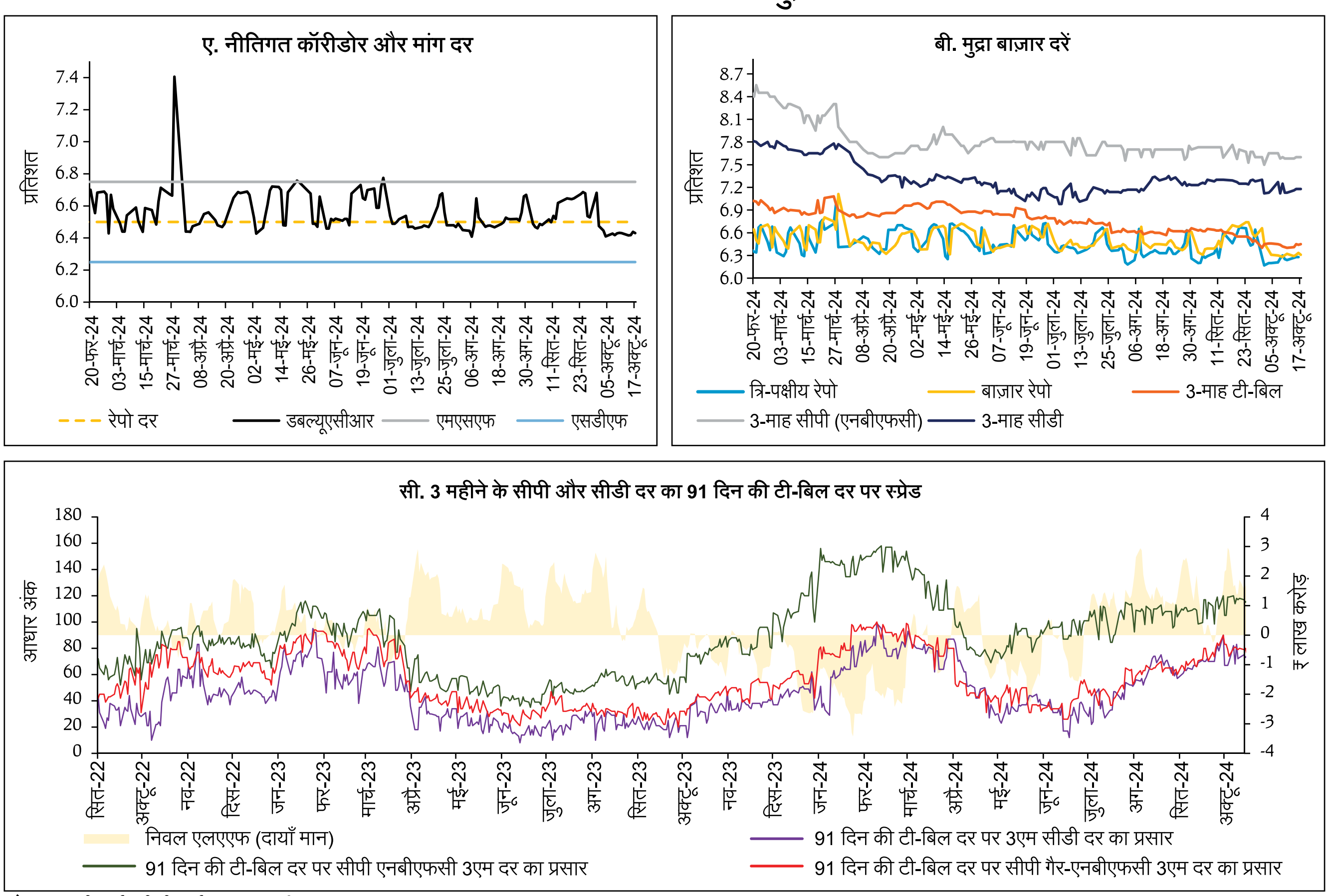

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; ब्लूमबर्ग।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में, सरकार की अल्पावधि उधार आवश्यकताओं में कमी के कारण 16 सितंबर और 17 अक्टूबर के दौरान 3 माह वाले खजाना बिलों (टी-बिल) पर प्रतिफल कम हुआ, जैसा कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े में टी-बिल नीलामी रद्द होने से पता चलता है। इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और 3 महीने के जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर दरें कम हुई हैं (चार्ट IV.2बी)।

मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने के सीपी और 91-दिवसीय टी-बिल दरों के बीच स्प्रेड) 16 सितंबर-17 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान 113 आधार अंक पर था, जो कि 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 के दौरान 6 बीपीएस अधिक था। द्वितीयक बाजार में, 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) और सीडी दरों का स्प्रेड अक्टूबर 2024 (17 अक्टूबर तक) के दौरान क्रमशः 115 आधार अंक और 73 आधार अंक रहा, जो एक वर्ष पहले के 71 और 28 आधार अंकों से अधिक था (चार्ट IV.2सी)। हालांकि आम तौर पर अधिशेष चलनिधि की अवधि के दौरान स्प्रेड कम हो जाते हैं, लेकिन हाल के महीनों में वे बढ़ गए हैं, जिसका मुख्य कारण 91-दिवसीय टी-बिल दरों में गिरावट है।

सीपी की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) और सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूएईआईआर) आम तौर पर मौद्रिक स्थितियों के अनुरूप विकसित होती है (चार्ट IV.3)। अक्टूबर 2024 (15 अक्टूबर तक) में डब्ल्यूएडीआर 7.51 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.45 प्रतिशत से अधिक था। इसके अलावा, डब्ल्यूएईआईआर एक वर्ष पहले के 7.23 प्रतिशत से बढ़कर 7.27 प्रतिशत (17 अक्टूबर 2024 तक) हो गया, जो सीडी निर्गम की बड़ी मात्रा को दर्शाता है।

प्राथमिक बाजार में वर्ष 2024-25 (4 अक्टूबर तक) के दौरान सीडी निर्गम में 69 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) की वृद्धि हुई और यह ₹5.58 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि बैंकों ने अपनी निधीयन आवश्यकताओं के लिए सीडी बाजार की ओर रुख किया (चार्ट IV.4)। बैंक, जमा दरों को बढ़ाने के बजाय अल्पकालिक सीडी निर्गम करके निधीयन अंतराल पाटने को प्राथमिकता देते हैं। वर्ष 2024-25 (15 अक्टूबर तक) के दौरान सीपी जारी करने की राशि ₹8.0 लाख करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹7.34 लाख करोड़ से अधिक थी। रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए बैंक ऋण पर जोखिम भार बढ़ाने से, एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करने में वृद्धि हुई क्योंकि उन्होंने अपने निधीयन स्रोतों में विविधता लाने की ओर ध्यान दिया।

चार्ट IV.3: डब्ल्यूएडीआर और डब्ल्यूएईआईआर

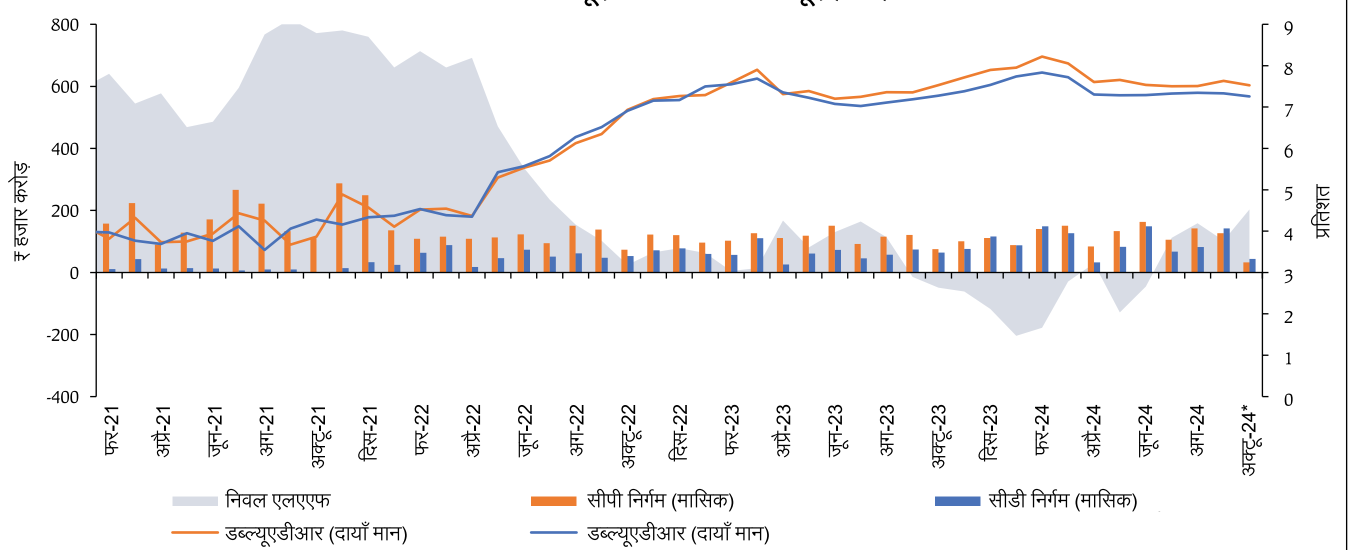

टिप्पणी: *:17 अक्तूबर 2024 तक।
स्रोत: आरबीआई; और सीसीआईएल-एफटीआईआरएसी।

चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

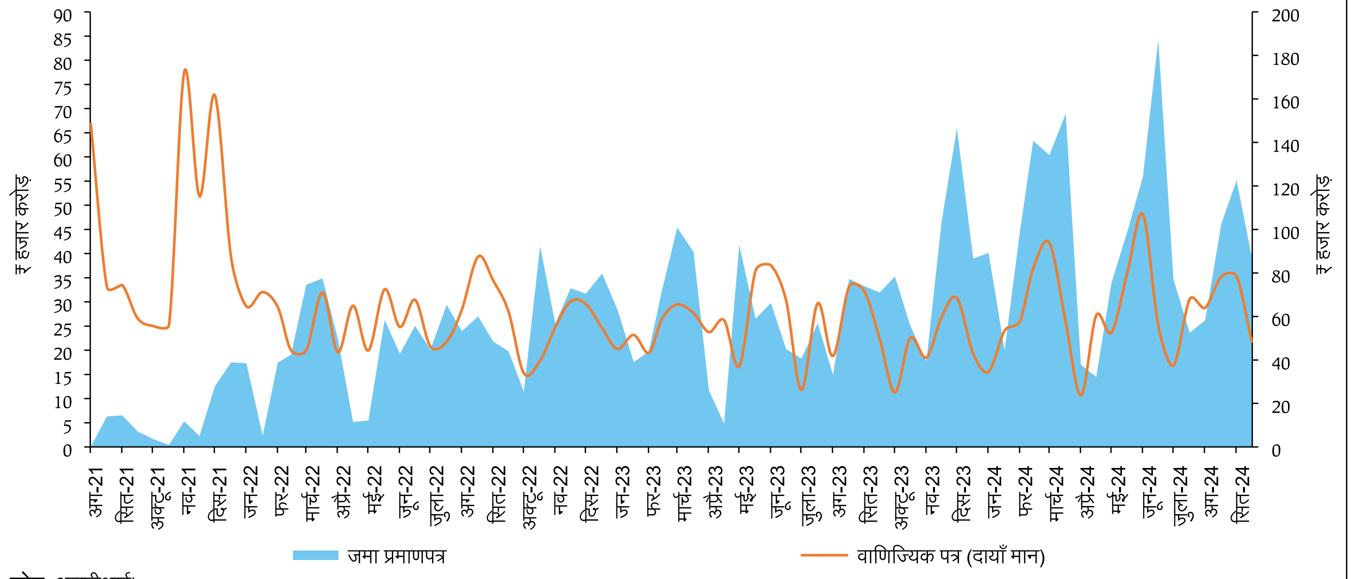

स्रोत: आरबीआई।

नियत आय खंड में, घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में सितंबर में सामान्य रूप से गिरावट देखी गई, इसकी वजह सौम्य घरेलू मुद्रास्फीति, वैश्विक निवेशक भावना में सुधार, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थी। लेकिन इनमें अक्टूबर की शुरुआत में थोड़ी मजबूती देखी गई। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 के दौरान 10 वर्षीय भारतीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर प्रतिफल 6.72 - 6.85 प्रतिशत की सीमा में रहा (चार्ट IV.5ए)। औसत सावधि स्प्रेड (10-वर्ष में से 91-दिवसीय टी-बिल घटाने पर) 16 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान 23 आधार अंकों (बीपीएस) की तुलना में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान 29 आधार अंकों पर स्थिर रहा। जी-सेक प्रतिफल मोटे तौर पर सावधि संरचना के मध्य खंड (10-वर्ष को छोड़कर) में स्थिर रहा (चार्ट IV.5बी)।

अक्टूबर 2023 में 10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर स्प्रेड, 17 वर्षों के निम्नतर स्तर पर

चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में गतिविधियां

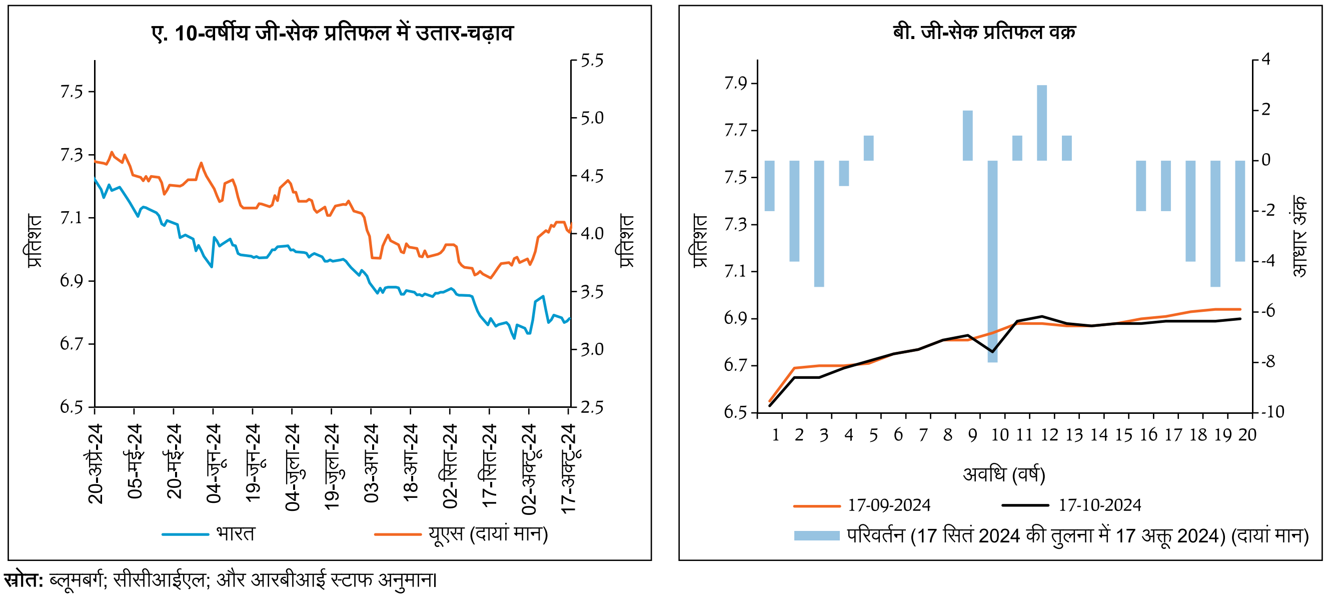

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.6: अस्थिरता और स्प्रेड-बॉण्ड बाजार

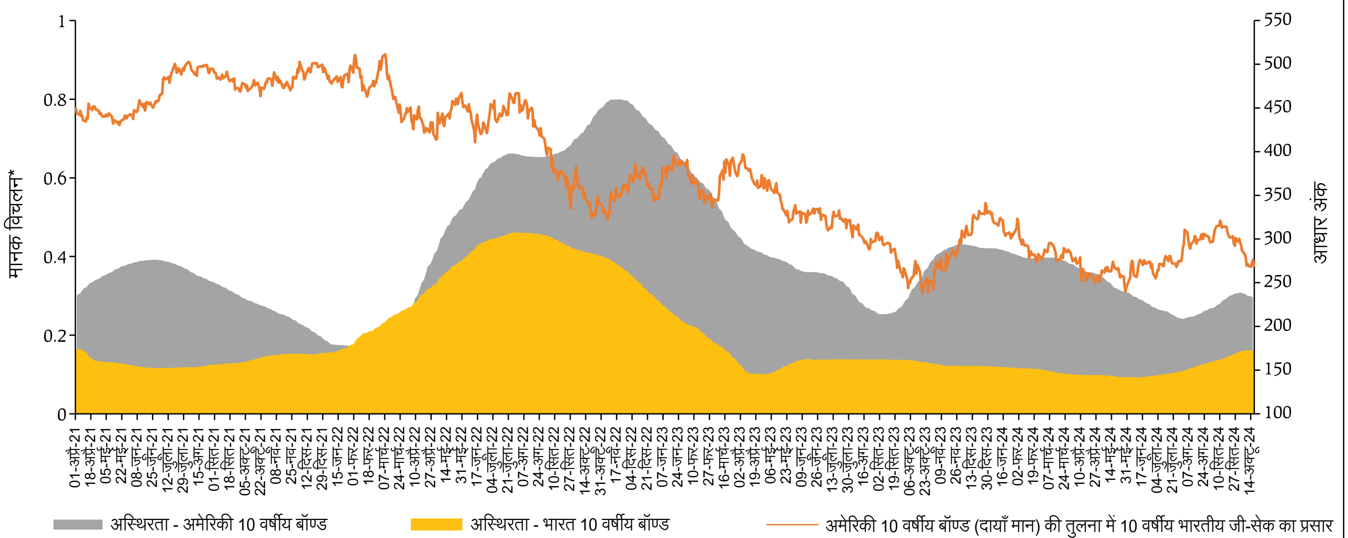

टिप्पणी: *: 12-माह का रोलिंग मानक विचलन।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

गिरने के बाद सीमित दायरे में बना हुआ है। 18 अक्टूबर 2024 तक स्प्रेड 271 बीपीएस पर था, जबकि एक वर्ष पहले यह 243 बीपीएस था। भारतीय बॉण्ड बाजार में प्रतिफल की अस्थिरता अमेरिकी ट्रेजरी बाजार की तुलना में कम रही है, हालांकि अगस्त 2024 से दोनों में वृद्धि हुई है। येन (मुद्रा) कैरी ट्रेड का मोचन और मौद्रिक नीति में सुलभता के परिमाण और समय के बारे में अनिश्चितता ने लाभ प्रदान किया (चार्ट IV.6)।

कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में कमी के साथ-साथ जी-सेक के प्रतिफल में भी गिरावट आयी। 16 सितंबर - 15 अक्टूबर 2024 के दौरान जोखिम प्रीमियम आम तौर पर अपरिवर्तित रहा (1-वर्षीय एएए श्रेणी को छोड़कर) (सारणी IV.1)। अगस्त 2024 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम की राशि ₹79,856 करोड़ थी, जबकि एक वर्ष पहले यह राशि ₹49,329 करोड़ थी। हालांकि 2024-25 (अगस्त तक) के दौरान, कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमन की राशि पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹3.4 लाख करोड़ की तुलना में मामूली रूप से कम होकर ₹3.3 लाख करोड़ रह गई।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 11 अक्टूबर 2024 तक 7.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 6.1 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 17 मई 2024 को 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 11 अक्टूबर 2024 को 6.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी के आधार प्रभाव के कारण है [34] – 98 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, ज्यादातर जमाराशियों के रूप में (30 सितंबर 2024 तक)।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार अंक) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
लिखत	16 अगस्त 2024 - 15 सितंबर 2024	16 सितंबर 2024 - 15 अक्तूबर 2024	उतार-चढ़ाव	16 अगस्त 2024 - 15 सितंबर 2024	16 सितंबर 2024 - 15 अक्तूबर 2024	उतार-चढ़ाव
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.94	7.83	-11	112	117	5
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.81	7.74	-7	95	95	0
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.75	7.65	-10	85	83	-2
(iv) एए (3 वर्ष)	8.56	8.49	-7	170	170	0
(v) बीबीबी-(3-वर्ष)	12.14	12.07	-7	528	528	0

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

[34] 19 मई 2023 को घोषित।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और संचलनगत मुद्रा में वृद्धि

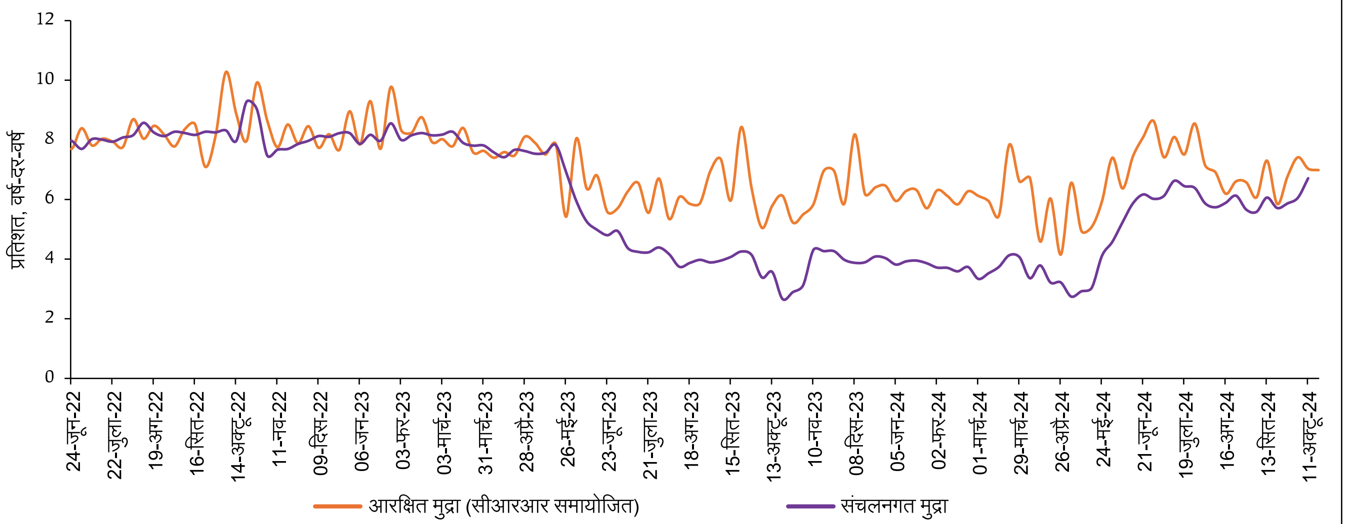

टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 11 अक्तूबर 2024 से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 11 अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा) 19.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ीं। स्वर्ण - एनएफए का दूसरा प्रमुख घटक 52.1 प्रतिशत बढ़ा, जो अगस्त 2020 के बाद से सबसे अधिक है। इसका कारण मुख्य रूप से सोने की बढ़ती कीमतों से पुनर्मूल्यांकन लाभ है (चार्ट IV.8)।

मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में 4 अक्टूबर 2024 तक 11.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले के समान)।[35] बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम$_3$ का लगभग 87 प्रतिशत

चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि

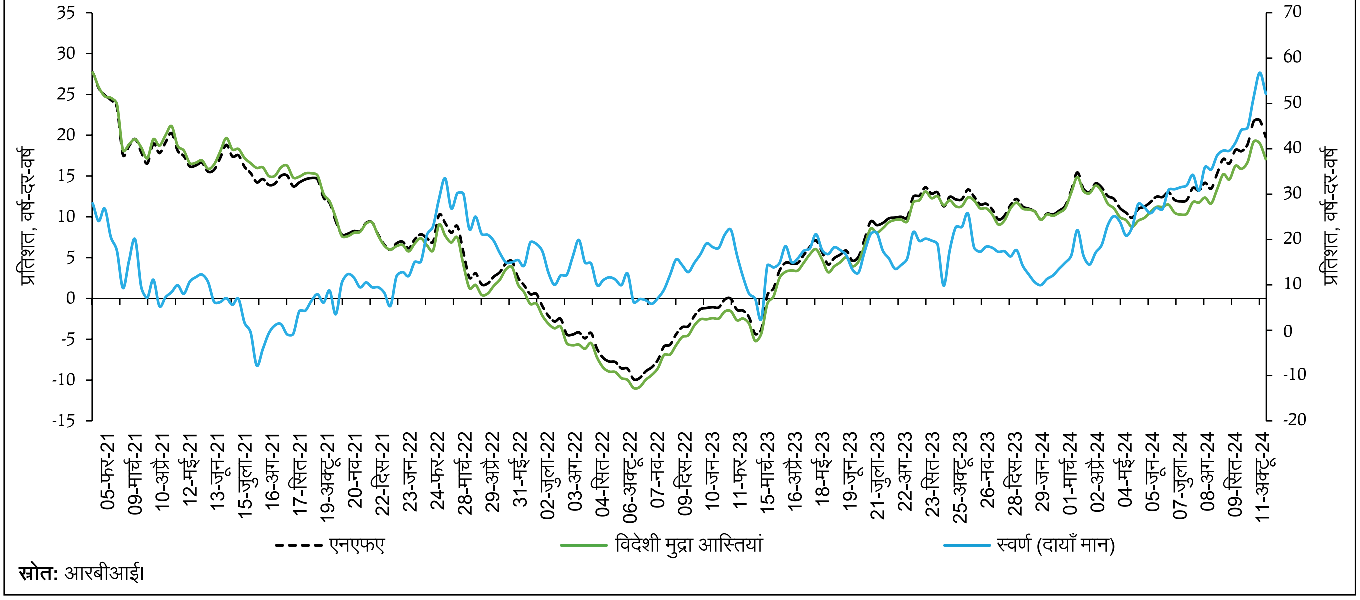

स्रोत: आरबीआई।

[35] किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.9: एससीबी की एम$_3$ वृद्धि और ऋण वृद्धि - आधार और गति प्रभाव

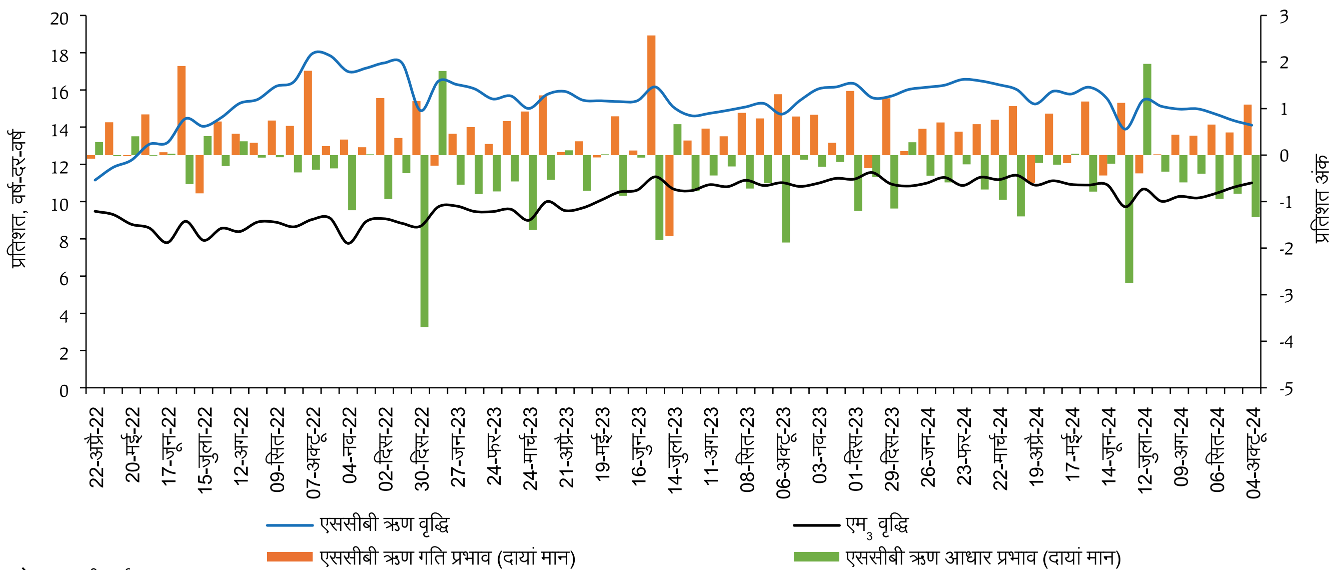

स्रोत: आरबीआई।

है, में 11.7 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्रेडिट वृद्धि 4 अक्टूबर 2024 तक 14.1 प्रतिशत रही (एक वर्ष पहले 14.7 प्रतिशत) [चार्ट IV.9]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर), जिसमें ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी के मद्देनजर वृद्धि देखी गई, अप्रैल 2023 से दहाई अंकों में बनी रही (चार्ट IV.10)।

यद्यपि एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा (सीडी) अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 4 अक्टूबर 2024 को 87.5 हो गया, ऋण और जमा के बीच अंतर कम हुआ है (चार्ट IV.11ए)। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 4 अक्टूबर 2024 को क्रमशः 102.5 प्रतिशत और 78.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 88.5 प्रतिशत और 87.4 प्रतिशत) था (चार्ट IV.11बी)। सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात

चार्ट IV.10: एससीबी की कुल जमाराशियां, ऋण वृद्धि और बकाया जमा प्रमाणपत्र

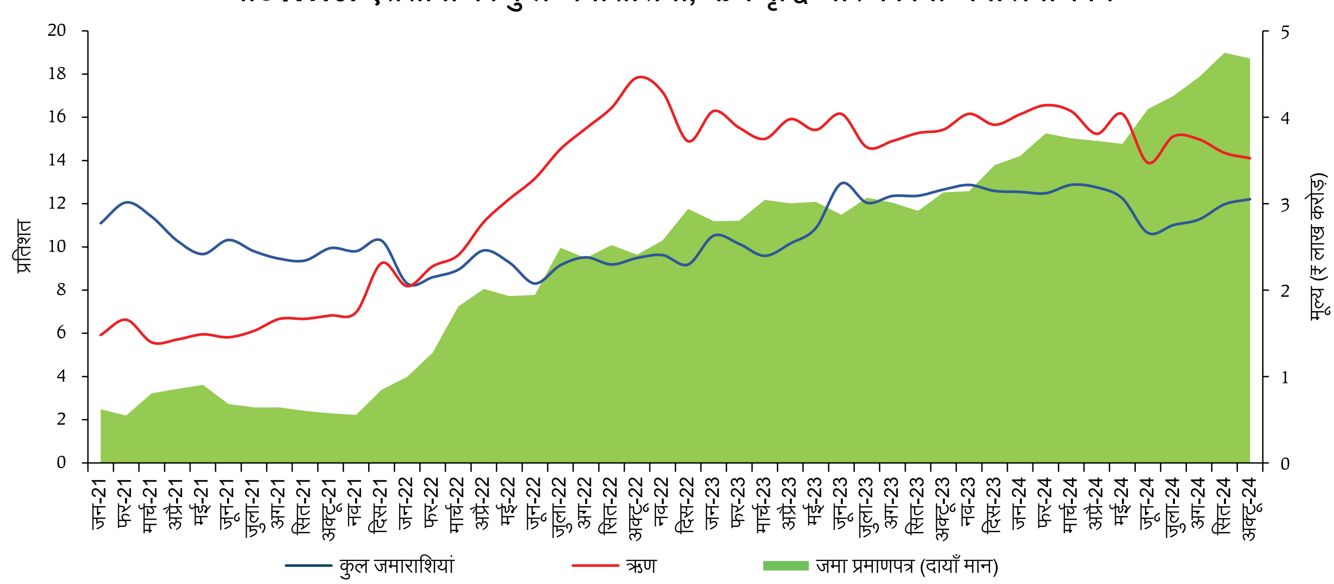

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.11: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

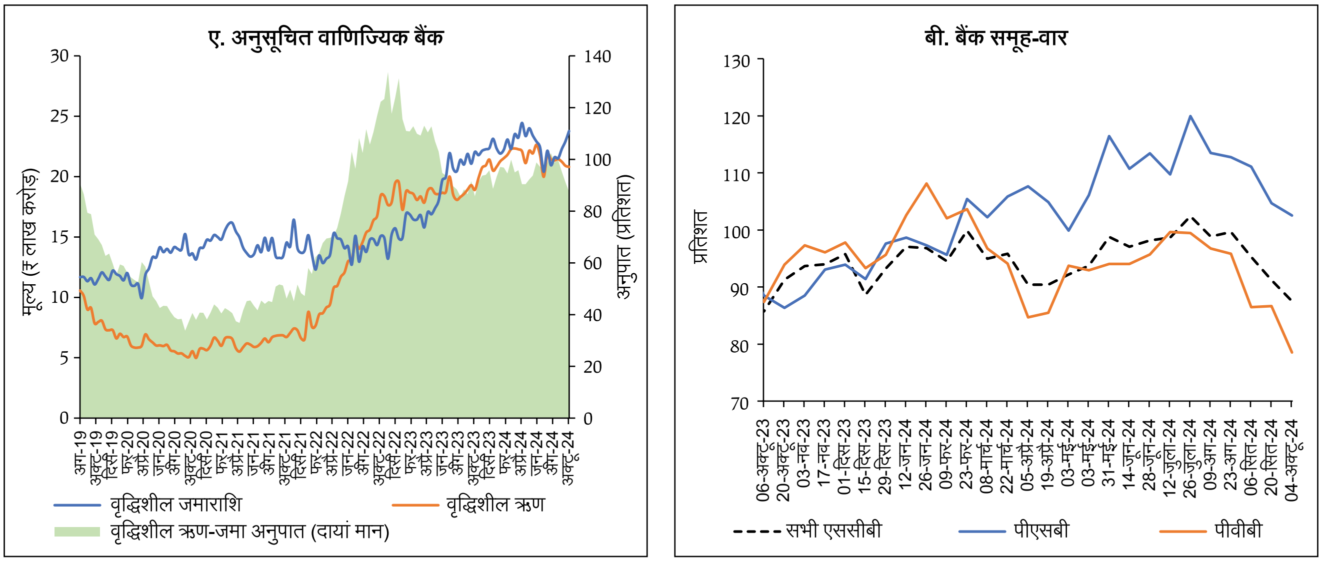

स्रोत: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत फॉर्म ए विवरणी।

(एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ, 4 अक्टूबर 2024 तक बैंकिंग प्रणाली के पास ऋण देने के लिए लगभग 77 प्रतिशत जमाराशियाँ उपलब्ध थीं।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी के जवाब में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान परिमाण तक संशोधित किया है। एससीबी की औसत 1-वर्षीय निधि की सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2022 से सितंबर 2024 के दौरान 170 आधार अंक बढ़ गई है। नतीजतन, नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में मई 2022 से अगस्त 2024 के दौरान क्रमशः 190 आधार अंकों और 119 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। जमा पक्ष पर, एससीबी की नई और बकाया रुपया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 243 आधार अंकों और 190 आधार अंकों की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

बैंक समूहों में संचरण यह दर्शाता है कि नए रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में निजी बैंकों की तुलना में अधिक थी; हालांकि, जमा के मामले में यह उसी अवधि के दौरान पीएसबी के लिए अधिक थी (चार्ट IV.12)।

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों पर संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

		सावधि जमा दरें		उधार दरें			
अवधि	रेपो दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर (नई जमाराशियाँ)	डब्ल्यूएडीटीडीआर (बकाया जमाराशियाँ)	ईबीएलआर	1 – वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर (नए रुपया ऋण)	डब्ल्यूएएलआर (बकाया रुपया ऋण)
नरमी का दौर फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
नियंत्रणाधीन अवधि मई 2022 से अगस्त 2024	+250	243	190	250	170	190	119

टिप्पणियां: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर नवीनतम डेटा सितंबर 2024 से संबंधित हैं।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर;
एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; और **ईबीएलआर:** बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.12: बैंक-समूहों में संचरण (मई 2022 से अगस्त 2024)

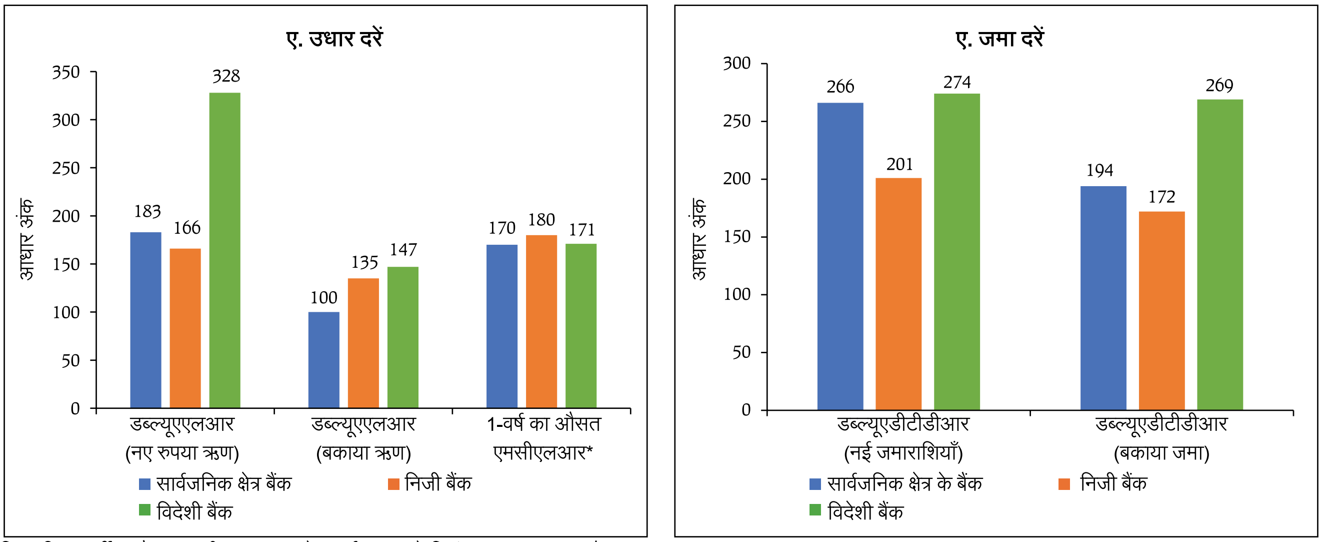

टिप्पणी: 1-वर्षीय औसत एमसीएलआर का डेटा मई 2022 से सितंबर 2024 तक का है।
स्रोत: आरबीआई।

भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है।[36] अधिकांश लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें अब फार्मूला आधारित दरों से अधिक हैं, सिवाय लोक भविष्य निधि और डाकघर आवर्ती जमा पर ब्याज दरों के।[37]

सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान अब तक भारतीय इक्विटी बाजारों ने नुकसान दर्ज किया, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 1.4 प्रतिशत घटकर 18 अक्टूबर 2024 को 81,225 पर बंद हुआ (चार्ट IV.13)। सितंबर के पहले पखवाड़े में सीमित दायरे में रहने के बाद, बीएसई सेंसेक्स ने ऐतिहासिक 85,000 अंक

चार्ट IV.13: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

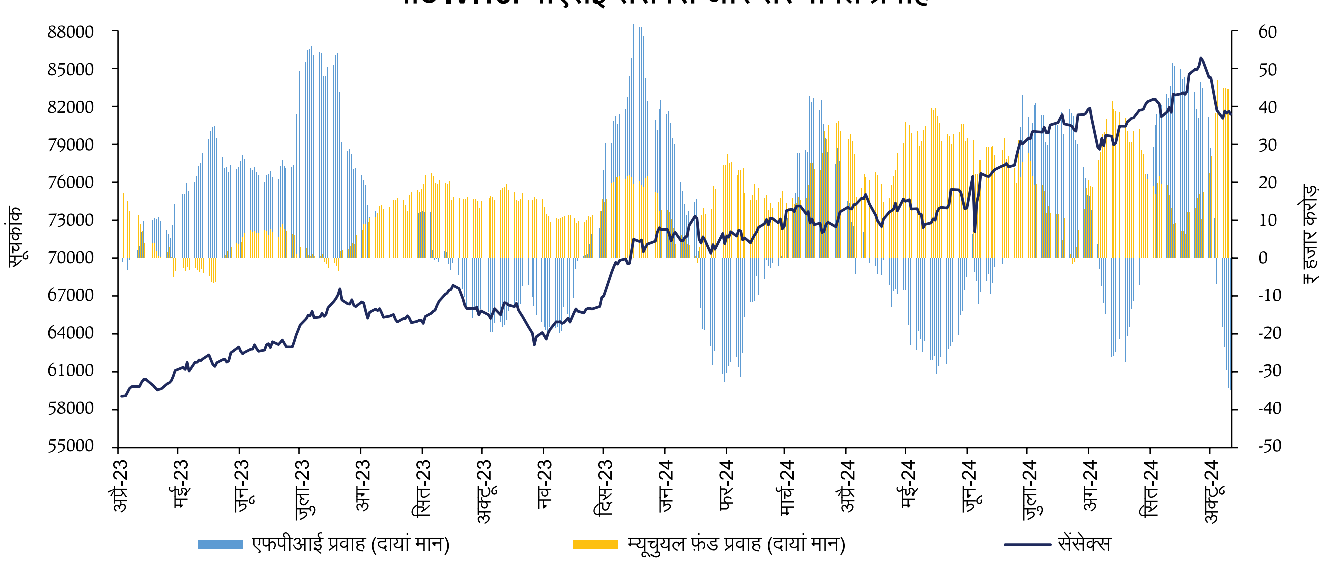

टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह 15-दिनों के आवर्ती योग (रोलिंग सम) आधार पर दर्शाये गए हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

36 https://dea.gov.in/sites/default/files/Q3_2425.pdf

37 अध्याय IV: मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्टूबर 2024, आरबीआई।

चार्ट IV.14: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

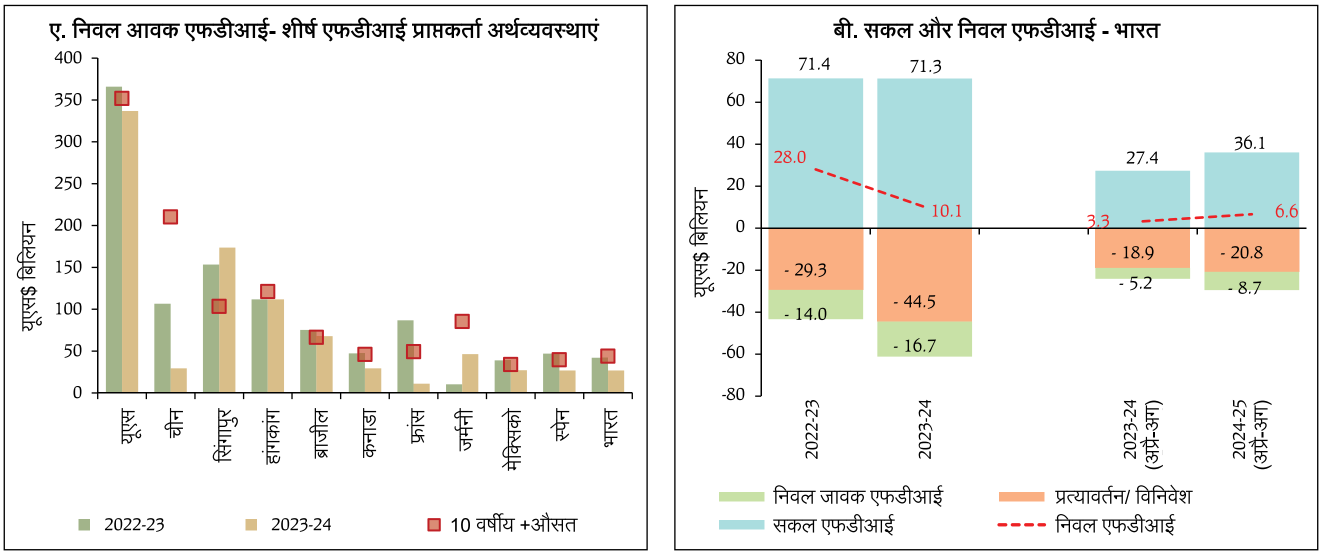

स्रोत: आरबीआई; और आईएमएफ।

को पार करने के साथ तेजी का अनुभव किया, जिसे अधिकांश वैश्विक बाजारों से मिले संकेतों से समर्थन मिला। इसके बाद, बाजारों में गिरावट का रुख देखने को मिला क्योंकि मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों के बढ़ने, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अन्य एशियाई ईएमई से चीन के लिए पोर्टफोलियो बहिर्वाह की मीडिया रिपोर्टों के बीच घरेलू भावनाएं मंद रहीं। वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए प्रत्याशा से कम कॉरपोरेट अर्जन की घोषणा ने भी घरेलू इक्विटी बाजारों में धारणा को प्रभावित किया। सितंबर के दौरान, एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में निवल खरीदार बने रहे, लेकिन जोखिम-विमुख रुझान के बीच अक्टूबर (16 अक्टूबर 2024 तक) में निवल विक्रेता बन गए।

शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में निवल एफडीआई अंतर्वाह में कमी आयी है (चार्ट IV.14ए)। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत में एफडीआई प्रवाह में सुधार के संकेत मिले हैं क्योंकि अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान सकल आवक एफडीआई एक वर्ष पहले के 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान निवल एफडीआई 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक वर्ष पहले के मुकाबले दोगुने से भी अधिक हो गई (चार्ट IV.14बी)। सकल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग दो-तिहाई हिस्सा विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाओं और बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया गया। लगभग तीन-चौथाई प्रवाह सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड और अमेरिका से प्राप्त हुए।

सितंबर 2024 में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह दिसंबर 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट IV.15ए)। इक्विटी खंड में निवल एफपीआई प्रवाह सितंबर 2024 में बढ़कर नौ महीने के उच्चतम स्तर 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसे अमेरिका में दर में कटौती, येन कैरी ट्रेड के मोचन और आशावादी घरेलू वृद्धि संभावनाओं से बढ़ावा मिला। समकक्षी ईएमई में, सितंबर में चीन के बाद भारतीय इक्विटी में सबसे अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ (चार्ट IV.15बी)। जेपी मॉर्गन के सरकारी बॉण्ड सूचकांक - इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआई-ईएम) में भारतीय सॉवरेन बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा के बाद, कर्ज खंड के लिए अक्टूबर 2023 से 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर स्थिर एफपीआई अंतर्वाह प्राप्त करना जारी है। क्षेत्रों में, वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार को सितंबर के दौरान सबसे अधिक एफपीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2024 (16 अक्टूबर तक) के दौरान निवल एफपीआई बहिर्वाह 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वैश्विक स्तर पर जोखिम-विमुख रुझान बढ़ने से प्रेरित था।

चार्ट IV.15: निवल पोर्टफोलियो निवेश

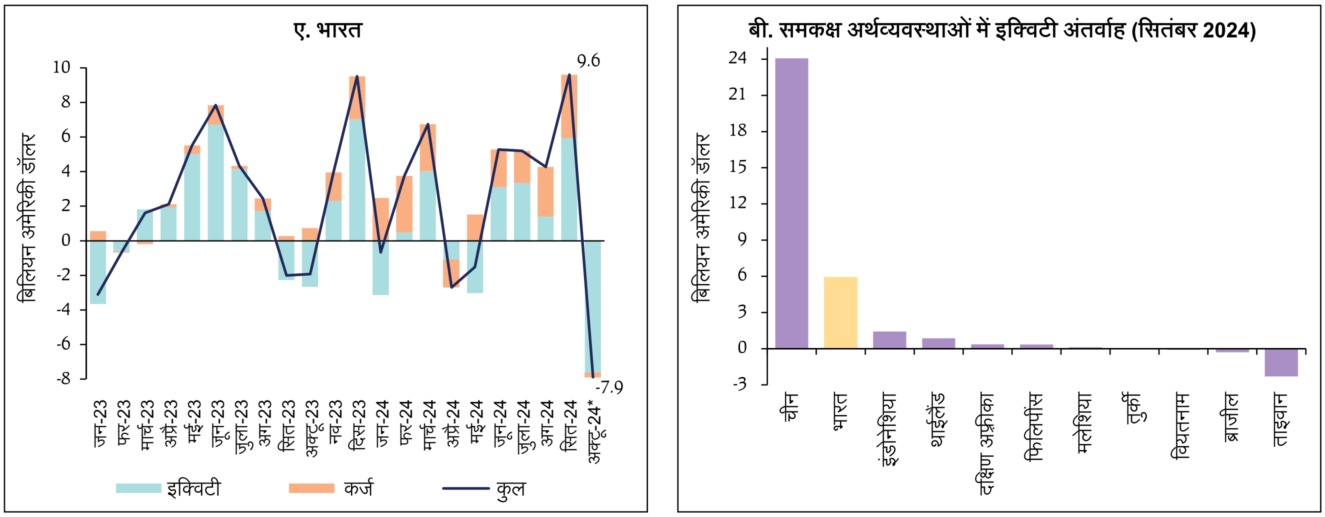

टिप्पणियाँ: 1. कर्ज में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और संकर (हाइब्रिड) लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।
2. *: 16 अक्तूबर 2024 तक का डेटा।

स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फ़ाइनेंस।

अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान अनिवासी जमाराशियों में निवल अभिवृद्धि एक वर्ष पहले के 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसकी अगुवाई सभी तीन खातों यथा अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर(बी)] खातों में अभिवृद्धि ने की।

अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के पंजीकरण (20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और सकल संवितरण (16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर), दोनों पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम थे (चार्ट IV.16ए)। मूलधन के पुनर्भुगतान को समायोजित करते हुए, वर्ष 2024-25 में अब तक निवल ईसीबी अंतर्वाह (5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान ईसीबी की कुल लागत पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 आधार अंक बढ़ गई। बेंचमार्क दरों पर भारित औसत ब्याज मार्जिन (डब्ल्यूएआईएम) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान 14 आधार अंक बढ़ा (चार्ट IV.16बी)। अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान जुटाए गए कुल ईसीबी ऋणों का दो-पांचवां हिस्सा पूंजीगत व्यय प्रयोजनों (पूंजीगत व्यय के लिए ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग सहित) के लिए था [चार्ट IV.16सी]।

भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ 27 सितंबर 2024 को 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। यह 11 अक्टूबर तक 690.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था, जिसमें 11.8 महीने का आयात और जून 2024 के अंत में बकाया कुल बाह्य ऋण का 101 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल था (चार्ट IV.17ए)। वर्ष 2024 के दौरान अब तक (11 अक्टूबर तक), भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, और यह विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ धारित करने वाले प्रमुख देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है (चार्ट IV.17बी)।

भारतीय रुपया (आईएनआर) सितंबर 2024 के दौरान सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्रा बना रहा, जिसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आयी (चार्ट IV.18)।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, सितंबर 2024 में भारतीय

चार्ट IV.16: बाह्य वाणिज्यिक उधार

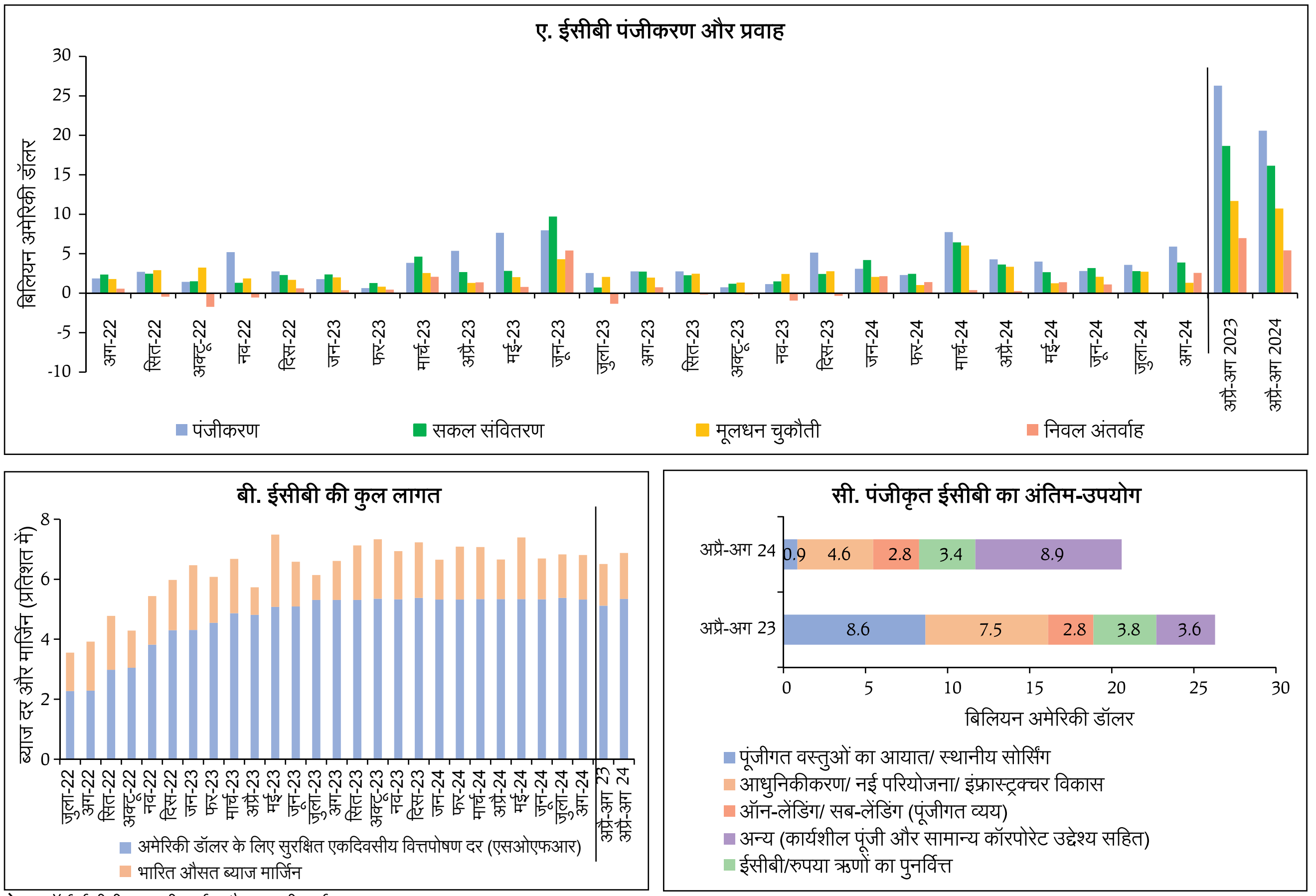

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रुपये में 0.3 प्रतिशत (माह-दर-माह) की कमी आयी, क्योंकि सांकेतिक प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये में गिरावट ने धनात्मक सापेक्ष मूल्य अंतरों की भरपाई कर दी (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.17: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

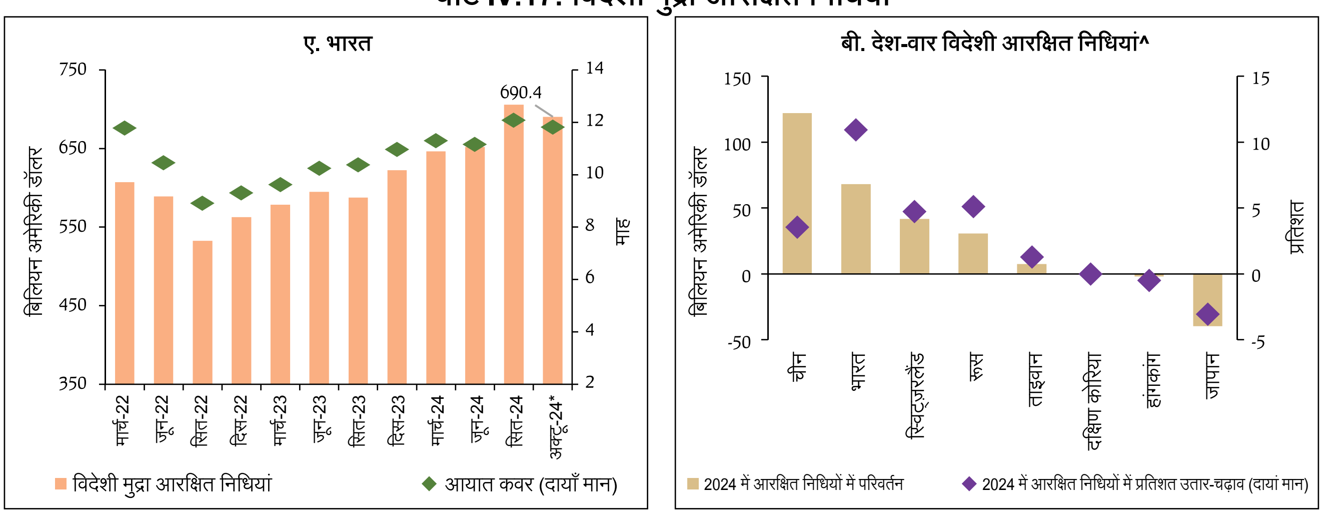

टिप्पणियाँ: 1. *: 11 अक्तूबर के लिए आंकड़े। सितंबर और अक्टूबर 2024 के लिए आयात कवर, भुगतान संतुलन के आंकड़ों पर जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिकीकृत पण्य आयात पर आधारित है।
2. ^: देशों को वर्ष 2024 में आरक्षित निधियों में परिवर्तन के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। भारत के लिए नवीनतम डेटा 11 अक्टूबर 2024, रूस के लिए 4 अक्टूबर, स्विट्ज़रलैंड और हांगकांग के लिए अगस्त के अंत और अन्य देशों के लिए सितंबर के अंत तक के लिए हैं।

स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइट; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.18: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव (अगस्त 2024 की तुलना में सितंबर 2024)

टिप्पणी: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई), प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के एक समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव को मापता है।

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) ने 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत घाटा दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही (2023-24 की चौथी तिमाही) में 0.5 प्रतिशत का अधिशेष था और एक वर्ष पहले (2023-24 की पहली तिमाही) में 1.0 प्रतिशत का घाटा था। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटे में एक वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि मुख्य रूप से पण्य व्यापार घाटे में वृद्धि के कारण हुई, जबकि इस अवधि में सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण प्राप्तियों में सुधार हुआ। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर) में 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 की पहली तिमाही में यह 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी (चार्ट IV.20)।

भारत का विदेशी कर्ज जून 2024 के अंत में 682.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो जीडीपी का 18.8 प्रतिशत था

चार्ट IV.19: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में मासिक उतार-चढ़ाव

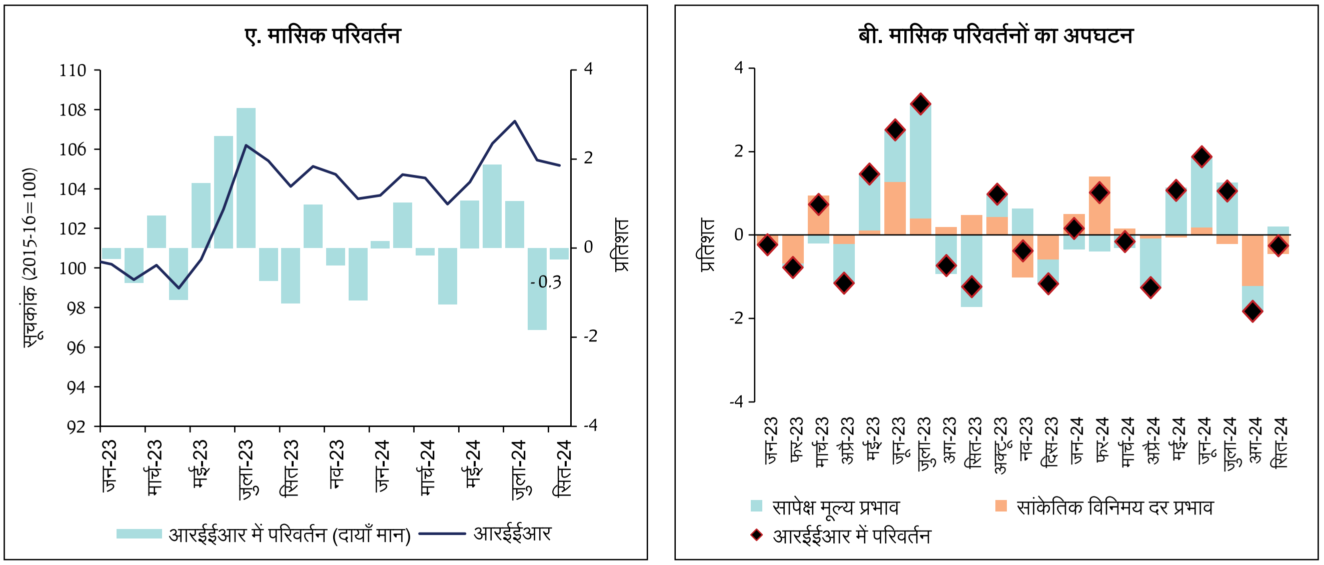

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.20: भारत का भुगतान संतुलन

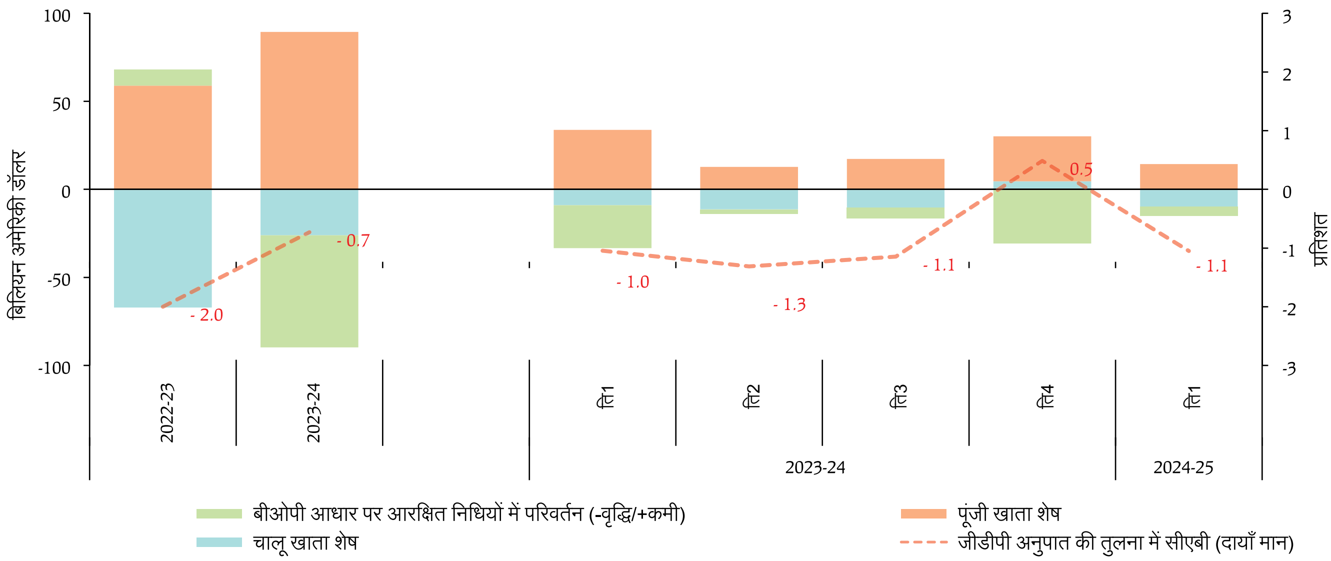

स्रोत: आरबीआई।

तथा यह मार्च 2024 के अंत के 18.9 प्रतिशत से थोड़ा कम था (चार्ट IV.21ए)। जून 2024 के अंत में प्रमुख बाहरी संकेतकों के संधारणीय स्तरों द्वारा संकेतित भारत का बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है (चार्ट IV.21बी)। निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों

चार्ट IV.21: बाह्य असुरक्षा - भारत

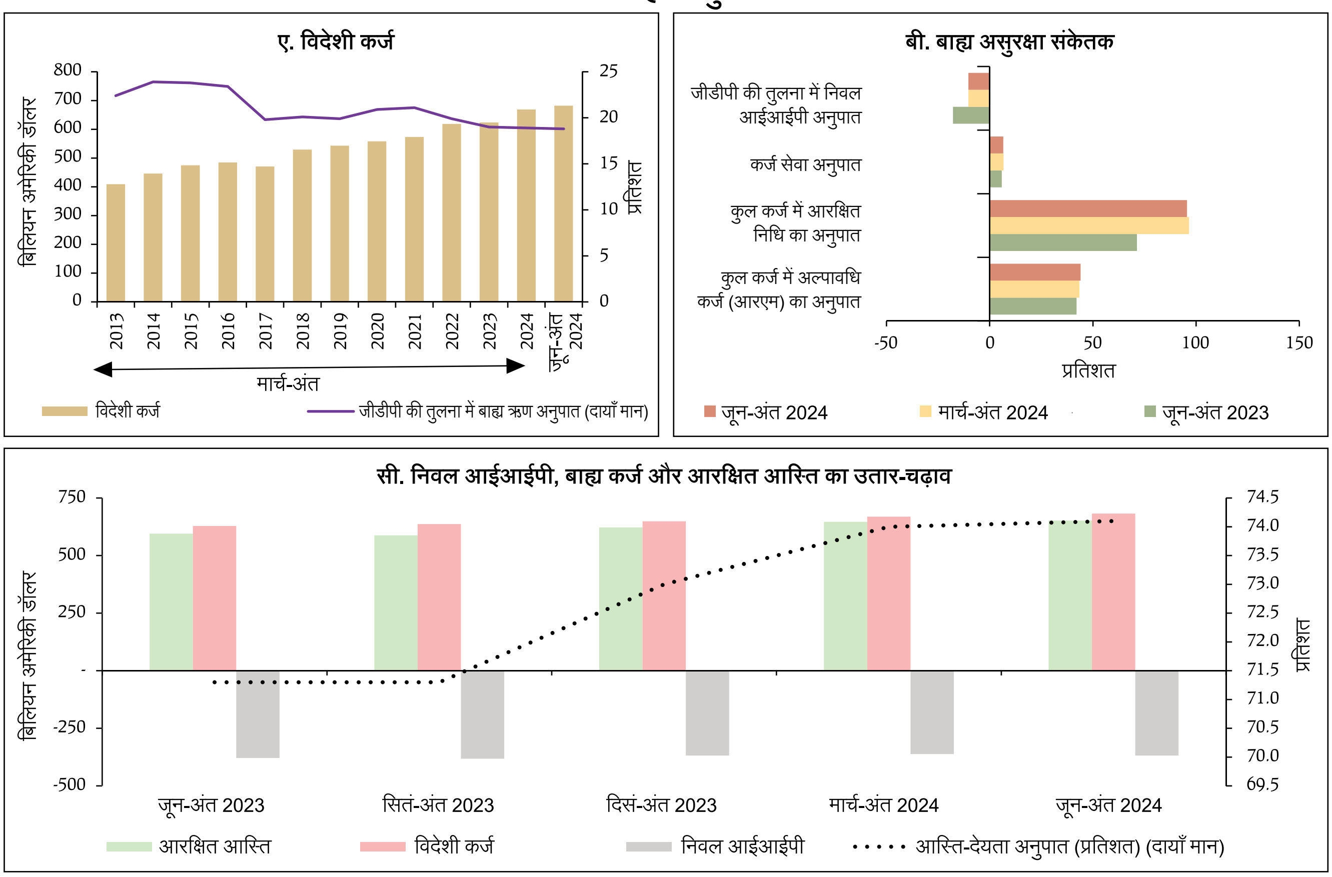

टिप्पणी: आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता।
स्रोत: आरबीआई; तथा भारत सरकार।

की तुलना में, भारत में विदेशी स्वामित्व वाली वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। हालांकि, भारत की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं का अनुपात जून 2023 के 71.3 प्रतिशत की तुलना में जून 2024 में 74.1 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले की तुलना में मजबूत बाह्य स्थिति का संकेत देता है (चार्ट IV.21सी)।

भुगतान प्रणालियाँ

सितंबर 2024 में विभिन्न भुगतान पद्धतियों में डिजिटल लेनदेनों में वृद्धि जारी रही (सारणी IV.3)। माह के दौरान रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) ₹177.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया - जो वर्ष 2024-25 में अब तक की सर्वाधिक राशि है। खुदरा पद्धतियों में, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के अंतर्गत लेनदेनों ने सितंबर में दहाई अंकों की वृद्धि (वार्षिक) दर्ज की। यूपीआई ने महीने में 15 बिलियन लेन-देन के साथ एक नया उच्च स्तर प्राप्त किया, जबकि इसका औसत टिकट आकार घटकर ₹1,372 हो गया, जो कम-मूल्य वाले लेनदेनों के लिए डिजिटल मोड को अपनाने में वृद्धि को दर्शाता है। पीयर-टू-मर्चेंट (पी2एम) और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) यूपीआई वॉल्यूम के बड़े हिस्से के '₹500 से कम' लेन-देन वाले बैंड के अंतर्गत आने से इसकी और पुष्टि होती है। अगस्त 2024 में क्रेडिट कार्ड जारी करने की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे कुल कार्डों की संख्या 10.5 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर, 2024-25 की पहली छमाही में, कुल डिजिटल भुगतान में (वर्ष-दर-वर्ष) मात्रा में 38 प्रतिशत (2023-24 में 43 प्रतिशत) और मूल्य में 19 प्रतिशत (2023-24 में 15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।[38]

सितंबर में निधियों के प्रभावी वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने के उद्देश्य से कई पहलें की गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के लिए भारत मुद्रा इंटरफ़ेस (भीम) ऐप के ज़रिए e-RUPI वाउचर को सक्षम किया है, ताकि योजना की राशि का वितरण किया जा सके और डिजिटल भुगतान मोड के अंगीकरण को बढ़ावा मिले।[39] इसी तरह, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट प्रोजेक्ट को कुशल निधि अंतरण के लिए राज्य सरकार की योजना के साथ एकीकृत किया गया है।[40]

यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए चल रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ एक रियल-टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए साझेदारी की है, जिससे यह भारत की घरेलू भुगतान पद्धति को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन जाएगा।[41]

सारणी IV.3: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-द-व प्रतिशत में)

भुगतान पद्धति	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन का मूल्य			
	अग-23	अग-24	सितं-23	सितं-24	अग-23	अग-24	सितं-23	सितं-24
आरटीजीएस	16.0	8.9	7.9	9.1	17.8	15.8	5.5	22.3
एनईएफ़टी	35.6	41.2	29.2	41.3	19.1	14.5	7.0	15.1
यूपीआई	60.8	41.3	55.7	42.5	46.9	30.7	41.4	30.7
आईएमपीएस	4.8	-7.3	2.3	-9.1	15.3	12.4	11.7	11.4
एनएसीएच	14.1	23.9	20.2	20.2	17.9	25.6	14.1	27.1
एनईटीसी	13.3	6.8	15.4	6.5	21.9	8.4	19.9	10.4
बीबीपीएस	23.9	86.1	20.2	106.6	46.5	258.6	43.8	268.5

टिप्पणी: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; **एनईएफटी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; **यूपीआई:** एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस; **आईएमपीएस:** तत्काल भुगतान सेवा **एनएसीएच:** राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; **एनईटीसी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; **बीबीपीएस:** भारत बिल भुगतान प्रणाली
स्रोत: आरबीआई।

[38] सितंबर 2024 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

[39] एनपीसीआई, (2024)। भीम (एप्लिकेशन), ई-रुपी वाउचर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को सशक्त बनाएगी।

[40] ओडिशा राज्य सरकार की सुभद्रा योजना (पीआईबी, 2024)।

[41] एनपीसीआई, (2024)। एनपीसीआई इंटरनेशनल, त्रिनिदाद और टोबैगो में यूपीआई जैसा रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करेगा।

रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2024 को घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, यूपीआई123 पे के लिए प्रति-लेनदेन सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 (₹5,000 से) और यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ₹1,000 (₹500 से) कर दिया। इसके अतिरिक्त, यूपीआई लाइट के लिए कुल सीमा को बढ़ाकर ₹5,000 (₹2,000 से) कर दिया गया। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी लेनदेन के लिए 'लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा' शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है।[42]

V. निष्कर्ष

आगे चलकर, मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के बारे में अनिश्चितता बनी रह सकती है। पण्य कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चे तेल और धातुओं की कीमतों में वृद्धि, निवल आयातक देशों के लिए प्रभाव-अंतरण वाले जोखिम बढ़ाती है। इसलिए दुनिया भर में मौद्रिक नीति के भविष्य को हाल ही में पण्य कीमतों में आए उतार-चढ़ाव से वृद्धि और मुद्रास्फीति, दोनों के लिए जोखिम को ध्यान में रखना होगा। घोषित प्रोत्साहन उपायों के प्रति चीनी अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया भी अस्पष्ट बनी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य जटिल हो रहा है।

भारत में त्योहारी मांग में तेजी आने और उपभोक्ता विश्वास में सुधार के कारण वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कुल मांग में अस्थायी मंदी दूर होने की उम्मीद है। बेहतर कृषि परिदृश्य से ग्रामीण मांग में तेजी आने की उम्मीद है। उपभोग मांग में तेजी और बढ़ते कारोबारी आशावाद के संकेतों के जवाब में निजी निवेश में तेजी आनी चाहिए। वित्तीय क्षेत्र, उत्पादक निवेश के लिए संसाधन जुटाने हेतु तैयार है, सुदृढ़ तुलन-पत्र द्वारा बफर किया गया है, और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिया जा रहा है, जिससे निवेश का परिदृश्य उज्ज्वल दिखाई देता है। वैश्विक व्यापार[43] की निरंतर मजबूती भारत के निर्यात के लिए बाहरी मांग को बढ़ावा दे सकती है, हालांकि भू-राजनीतिक तनावों का बढ़ना एक संभावित खतरा बना हुआ है।

कुल आपूर्ति के संदर्भ में, मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा देश में समग्र *खरीफ* उत्पादन के साथ-साथ जलाशय भंडारण के लिए भी शुभ संकेत है, जिससे *रबी* मौसम का परिदृश्य उज्ज्वल दिखता है। 2024 के मानसून के बाद के मौसम के दौरान ला नीना की स्थिति विकसित होने की बढ़ी हुई संभावना समग्र वर्षा के लिए हितकारी है, हालांकि अत्यधिक वर्षा से तैयार *खरीफ* फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है।

चलनिधि स्थितियां अधिशेष में बनी हुई हैं। रिज़र्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में मुस्तैद और लचीला बना रहेगा और ब्याज दरों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए घर्षणात्मक और टिकाऊ चलनिधि, दोनों को नियंत्रित करने के लिए लिखतों के उपयुक्त मिश्रण को विनियोजित करेगा।[44] भारतीय इक्विटी बाजारों ने मजबूत समष्टि-आर्थिक मूल-तत्व (मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल) और दीर्घकालिक वृद्धि संभाव्यता के कारण चालू वर्ष में नए शिखर हासिल किए हैं। हालांकि, वर्धित मूल्यांकन और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों के आसपास की अनिश्चितता को लेकर चिंता बनी हुई है, जो अक्टूबर में देखी गई गिरावट में परिलक्षित हुई। वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए कॉरपोरेट आय रिपोर्ट और वैश्विक बाजारों के रुझानों पर नज़र रखते हुए बाजारों द्वारा सतर्कता बरतने की संभावना है। इन चिंताओं के बावजूद, प्राथमिक बाजार के निर्गमों के लिए स्थिति मजबूत बनी हुई है।

भारत का बाह्य क्षेत्र बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद सुदृढ़ता प्रदर्शित कर रहा है। 08 अक्टूबर 2024 को, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज (एफटीएसई) - रसेल ने घोषणा की कि वह सितंबर 2025 से छह महीने की अवधि के लिए अपने उभरते बाजारों के सरकारी बॉण्ड सूचकांक (ईएमजीबीआई) में भारत के सॉवरेन बॉण्ड को शामिल करेगा, जिसमें बाजार मूल्य भारित आधार पर 9.35 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। इससे भारत को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के अलावा, कर्ज खंडों में प्रवाह को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत

[42] आरबीआई प्रेस प्रकाशनी । विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य। 09 अक्टूबर 2024 ।

[43] विश्व व्यापार संगठन के माल व्यापार बैरोमीटर (सितंबर 2024) के अनुसार, वैश्विक माल व्यापार में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2024 की तीसरी तिमाही में सुधार जारी रहेगा।

[44] गवर्नर का वक्तव्य: 9 अक्टूबर 2024, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 ।

के बाह्य क्षेत्र की अंतर्निहित शक्ति इसके मजबूत समष्टि-आर्थिक मूल-तत्वों में निहित है, जो उच्च विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों द्वारा समर्थित है।

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ डिजिटल भुगतान लेनदेनों में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका कारण मेगा ई-कॉमर्स बिक्री तथा छोटे शहरों और कस्बों से बढ़ती मांग है। टियर 3 से 6 शहरों में उपभोक्ता तेजी से डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।[45] ये घटनाक्रम आरंभिक स्तर पर डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसके निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने की विशाल संभाव्यता को उजागर करते हैं।

[45] चेज इंडिया रिपोर्ट (अगस्त 2024)। भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति।

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षणों से प्रमुख निष्कर्ष

- विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) ने 2024-25 की पहली तिमाही में मौसमी गिरावट दर्ज की (चार्ट ए1)। हालांकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू में तिमाही के दौरान 120 आधार अंकों की वृद्धि हुई। विनिर्माताओं ने आगामी तिमाहियों में सीयू पर धनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा (चार्ट ए2)।

चार्ट ए1: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू)

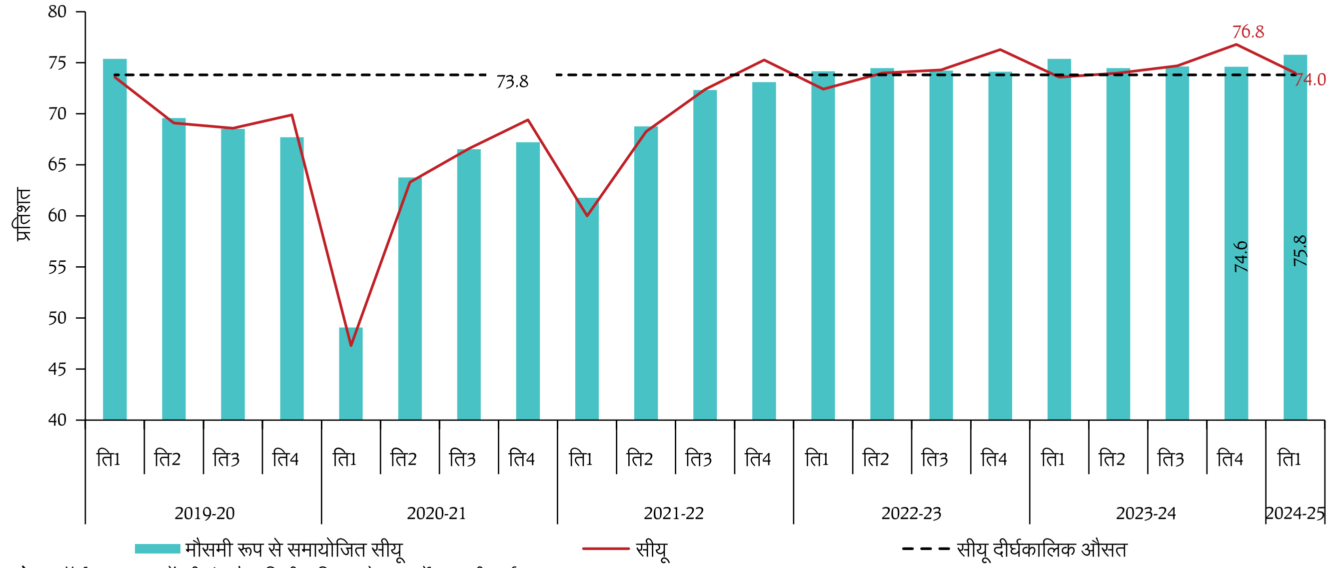

स्रोत: ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी एंड कैपासिटी यूटिलाइज़ेशन सर्वे, आरबीआई।

चार्ट ए2: क्षमता उपयोग पर विनिर्माताओं का मूल्यांकन और अपेक्षाएँ

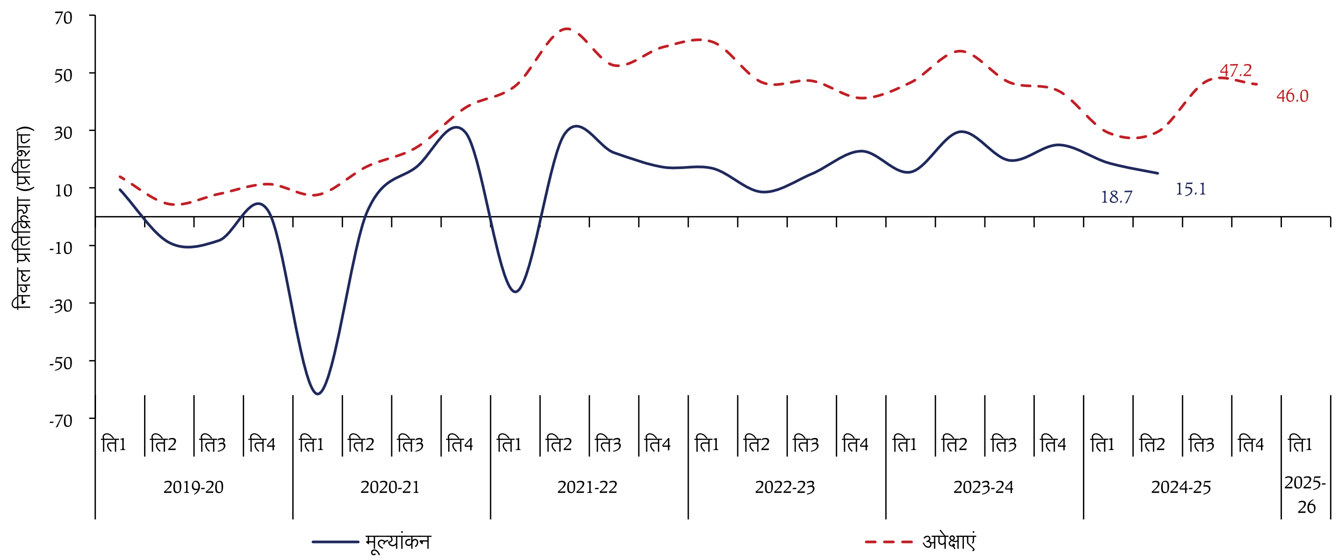

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- विनिर्माण फर्मों को 2024-25 की तीसरी तिमाही में उत्पादन पर इसी तरह के आशावाद की उम्मीद है और चौथी तिमाही से इसमें सुधार होने की संभावना है (चार्ट ए3)।

चार्ट ए3: उत्पादन/ टर्नओवर पर प्रत्याशाएँ

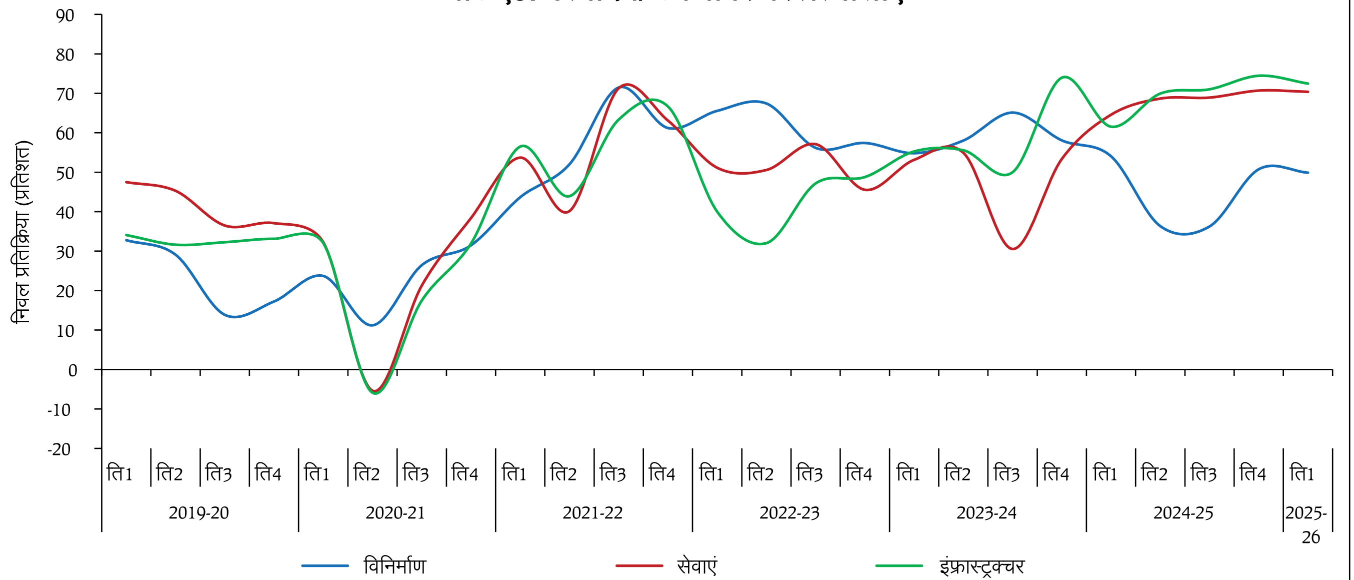

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों ने मांग की स्थितियों पर अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण दर्शाया है (चार्ट ए4)। कंपनियां 2025-26 की पहली तिमाही तक समग्र कारोबारी स्थिति के बारे में आशावादी बनी हुई हैं।

चार्ट ए4: समग्र कारोबारी स्थिति पर अपेक्षाएँ

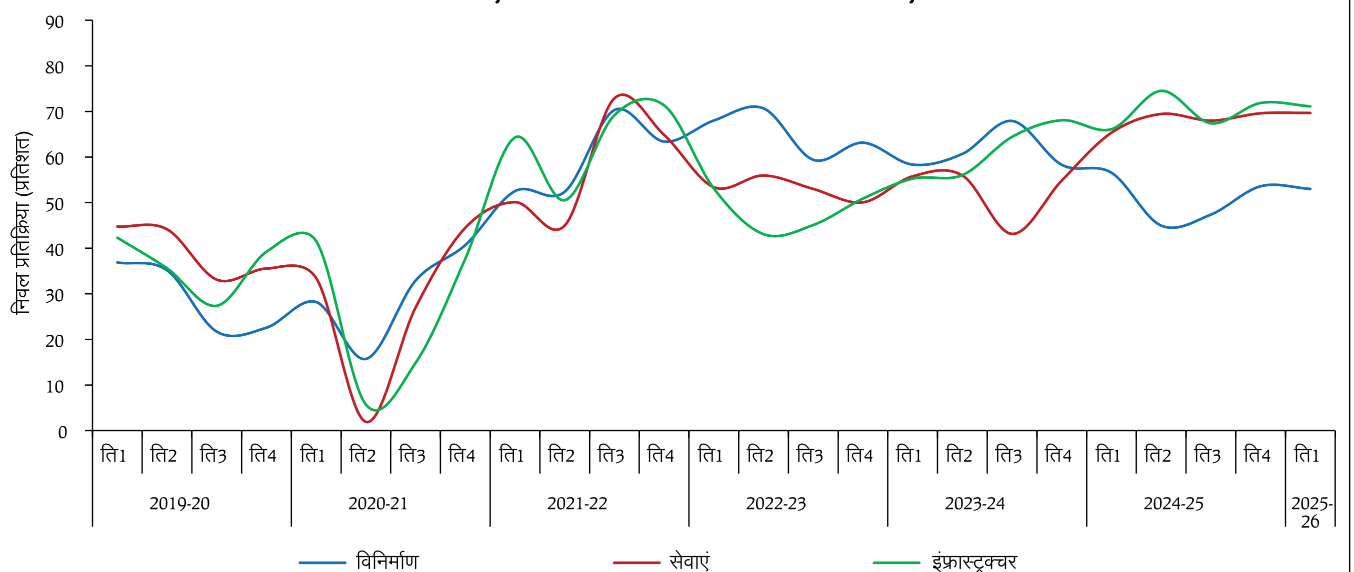

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- रोजगार के मांग की स्थिति के अनुरूप बढ़ने की उम्मीद है (चार्ट ए5)।

चार्ट ए5: समग्र रोजगार स्थिति पर अपेक्षाएँ

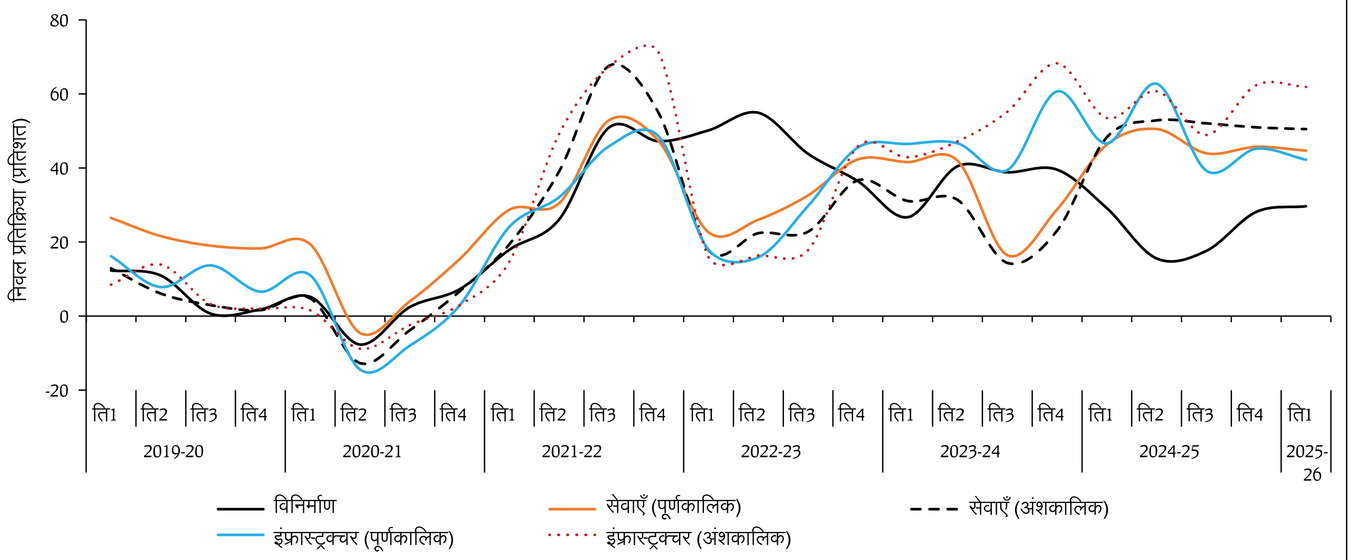

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट लागत का दबाव कम होने की संभावना है, जबकि 2024-25 की तीसरी तिमाही में सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए यह दबाव बरकरार रहने की उम्मीद है (चार्ट ए6)।

चार्ट ए6: इनपुट लागत पर अपेक्षाएँ

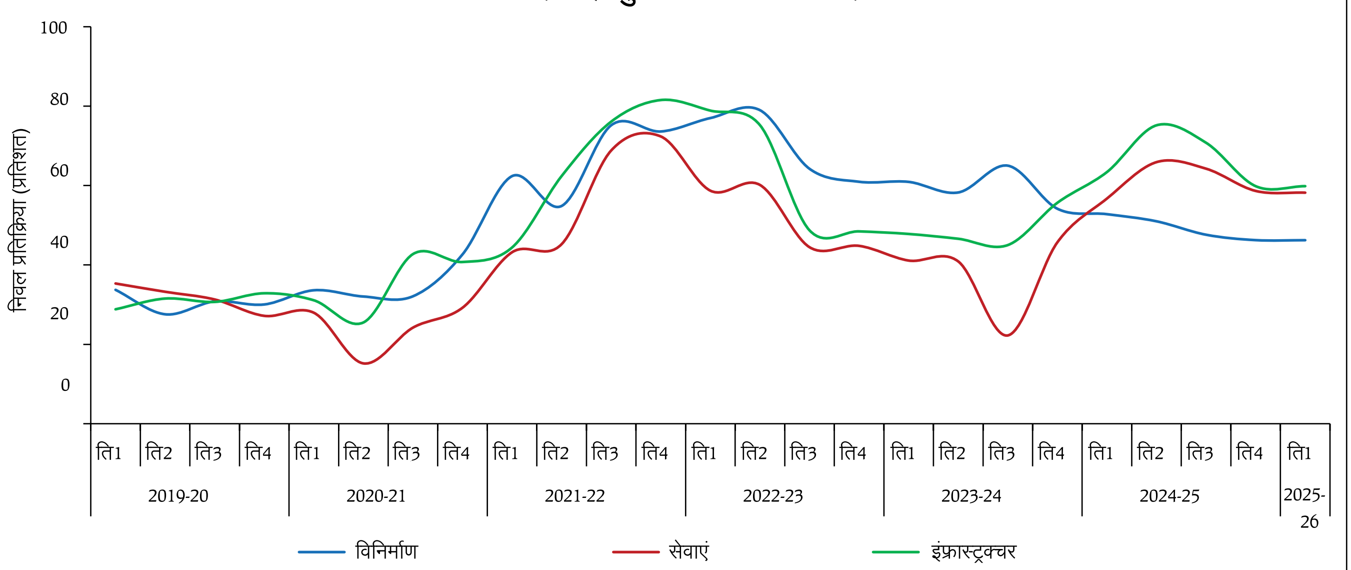

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण: और सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- विनिर्माण क्षेत्र को 2024-25 की तीसरी तिमाही में बिक्री कीमतों में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। 2024-25 की तीसरी तिमाही में सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए बिक्री कीमतों में सामान्य वृद्धि होने की उम्मीद है (चार्ट ए7)।

चार्ट ए7: बिक्री कीमत पर अपेक्षाएँ

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

- बैंकरों को उम्मीद है कि प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की मांग बढ़ेगी तथा ऋण के लिए नियम और शर्तें आसान होंगी (चार्ट ए8)।

चार्ट ए8: ऋण मांग पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों का आकलन और प्रत्याशाएँ

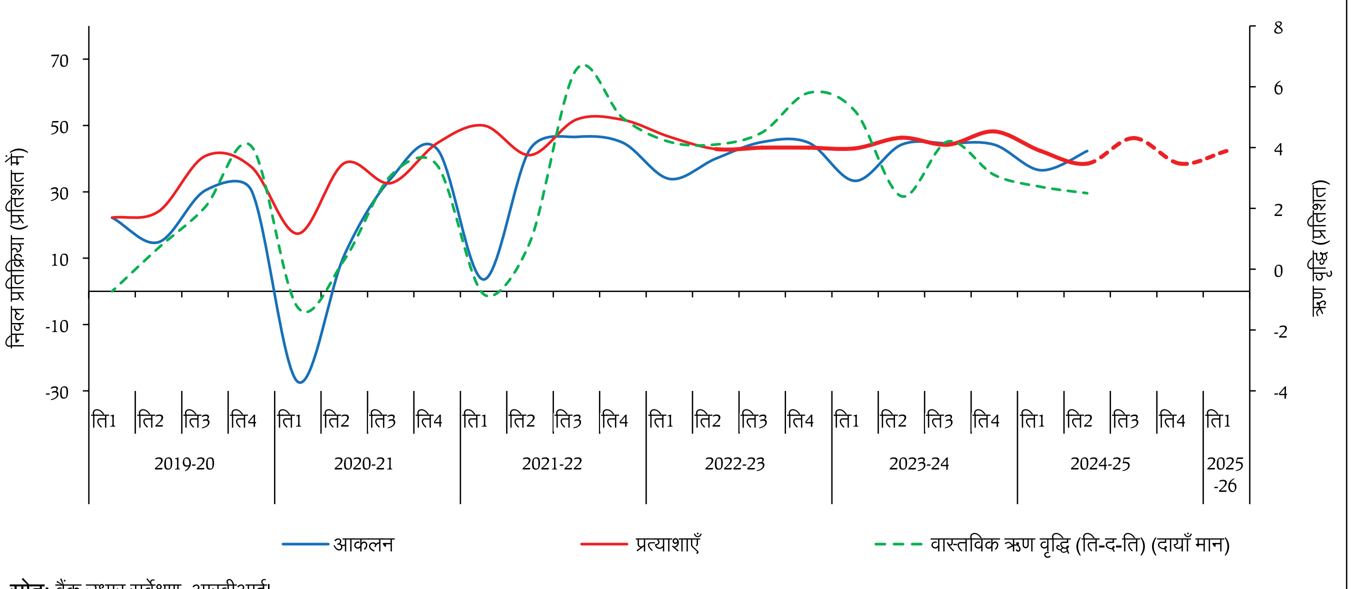

स्रोत: बैंक उधार सर्वेक्षण, आरबीआई।

टिप्पणी: 'निवल प्रतिक्रिया' की गणना आशावाद की रिपोर्ट करने वाले और निराशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। वृद्धि विकल्प (I) सभी मापदंडों के लिए एक आशावादी प्रतिक्रिया है, लागत से संबंधित मापदंडों को छोड़कर, जैसे कि कच्चे माल की लागत, आदि, जहाँ कमी वाला विकल्प (डी) उत्तरदाता कंपनी के दृष्टिकोण से आशावाद को दर्शाता है।